चौथी दुनिया

www.bhauthiduniya.bom

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 04 जुलाई– 10 जुलाई 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

गंगा की सौगंध झूठ बोलो कम

हम इस शीर्षक को क्षमायाचना के साथ लगा रहे हैं. उमा भारती ने कहा है कि साल 2018 तक गंगा बिल्कुल साफ हो जाएगी. लेकिन ऐसा हो पाएगा, इसकी संभावना दूर-दूर तक नजर नहीं आती. गंगा 2018 तक तो क्या, 2028 तक भी साफ हो सकेगी, ऐसा लगता नहीं. इसके कारण क्या हैं, पढ़िए इस रिपोर्ट में...

श्वेता सिंह

गोमुख में इंसानी आबादी नहीं होने के कारण वहां बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है. हालांकि क्लाइमेंट चेंज गोमुख को प्रभावित करता है. उसके नीचे हम गंगोत्री की बात करते हैं, जहां पर लोगों की आबादी है. गंगोत्री में मैंने एक बात देखी कि वहां लोगों में गंगा की साफ-सफाई को लेकर जागरूकता है. सभी जगह मरे हुए जानवर या लाशों को सीधे गंगा नदी में डाल दिया जाता है, लेकिन वहां कई साल से इसको वैक्यूम में डालकर नष्ट किया जाता है. वे लोग बिना किसी सरकारी मदद के ऐसा करते हैं. गंगोत्री मंदिर समिति भी सफाई को लेकर हमेशा प्रयत्नशील रहती है. स्थानीय लोगों को इस बात की चिंता रहती है कि लोग बाहर से आकर यहां बस जाते हैं और अपने पीछे गंदगी का अंबार छोड़ जाते हैं. इन इलाकों में बाहरी लोगों के लिए जो छोटे टेंट लगाए जाते हैं, उनके आस-पास गंदगी का ढेर लगा रहता है. बाहरी लोगों को साफ-सफाई के लिए प्रेरित करना उनकी सबसे बड़ी समस्या है. अभी तक वहां पर उनका नियंत्रण था कि कोई चीजें छूट जाती थी तो उसे वैक्यूम या मिट्टी में डालकर नष्ट कर दिया जाता था. अब उनका कहना है कि लोग बाहर से आकर यहां छोटे-छोटे होटल बना रहे हैं, जिसपर उनका नियंत्रण नहीं है. उनका कहना है कि उमा भारती मंत्री बनने के बाद वहां उतना नहीं गई हैं, जितना पहले जाती थीं. मोदी सरकार से स्थानीय लोग खुश हैं. लेकिन एक शिकायत हर जगह मिली, गंगोत्री से लेकर बनारस तक सफाई कार्य में कहीं भी तेजी नहीं दिख रही है. जब हमने हाल में उमा भारती का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि सफाई कार्य में तेजी लाई जा सकती है या हम बेहतर कर सकते हैं. ऋषिकेष से गंगा में प्रदूषण दिखने लगता है. उत्तरकाशी में भी लोग गंगा की सफाई को लेकर सजग हैं. उत्तरकाशी में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर कोई नियंत्रण नहीं है.यहां के घरों से निकलने वाली गंदगी सीधे गंगा में जाती है. ऋषिकेश में कई आश्रमों की गंदगी गंगा में प्रवाहित हो रही है. गंगा के बीच में शिव की मूर्ति को हमने श्रद्धा की बात मानी, जो बाद में बाढ़ में बह गई. लेकिन शिव जी की मूर्ति का निर्माण ही अवैध था. हरिद्वार में अवैध खनन पर सरकार कोई रोक नहीं लगा पाई है. गंगोत्री में प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है, लेकिन रास्ते में चारों तरफ गंदगी फैली है जैसे चिप्स के पैकेट, पानी के बोतल वगैरह.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

गंगा के लिए अलग मंत्रालय हो

शफीक आलम

गंगा को बचाने और संवारने के लिए गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ और खत्म भी हो गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला. अब नई सरकार ने एक नई योजना शुरू की है–नमामि गंगे. योजना की घोषणा हुए एक साल बीत चुके हैं. 1986 से गंगा एक्शन प्लान शुरू होने से लेकर आज तक गंगा की सफाई का काम जारी है. नरेन्द्र मोदी की सरकार को सत्ता में आये दो वर्ष हो चुके हैं. केन्द्रीय जल संसाधन एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती कहती हैं कि 2018 तक गंगा को दुनिया की सबसे साफ नदियों की पंक्ति में खड़ा कर दिया जाएगा. फिलहाल गंगा विश्व की 10 सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में से एक है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनावी अभियान के दौरान और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी गंगा की सफाई पर बल देते रहे हैं. लेकिन गंगा एक्शन प्लान की नाकामयाबी से कोई सबक नहीं लेते हुए, उन्हीं गलतियों को नमामी गंगे के क्रियान्वयन में भी दोहराया जा रहा है. गंगा प्रदूषण की वजह गंगा तट पर बसे शहरों और उद्योगों द्वारा प्रवाहित खतरनाक कचरे ही नहीं, बल्कि गंगा के बहाव में अवरोध भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है. अगर इसपर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया और केवल कचरे के प्रवाह को ही गंगा सफाई का केन्द्र बना दिया गया तो नमामी गंगे के 20 हज़ार करोड़ रुपए का भी वही हश्र होगा जो गंगा एक्शन प्लान का हुआ था. सरकार के लचर रवैये का अन्दाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जो काम जनता द्वारा चुनी सरकार को करना चाहिए, वह एनजीटी को करना पड़ रहा है.

हालांकि, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती पहले यह कह रही थीं कि अक्टूबर 2016 तक नमामी गंगे के अच्छे परिणाम दिखने शुरू हो जायेंगे, लेकिन एक वर्ष बाद उन्होंने 2018 तक गंगा को दुनिया की सबसे स्वच्छ नदियों में शामिल कराने की बात कही. वहीं मोदी सरकार के एक अन्य मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं कि नमामी गंगे के तहत गंगा की सफाई का काम अभी प्लानिंग के स्तर पर है. अगले तीन साल में गंगा सफाई की दिशा में ठोस काम लोगों को दिखने लगेगा. नमामी गंगे को एक और बड़ा झटका तब लगा जब इस परियोजना में तकनीकी परामर्श देने वाली जापानी कंपनी एनजेएस कंसल्टेंट ने इस परियोजना से हाथ खींच लिया. कंपनी का कहना था कि पिछले दो साल में जो सुझाव दिये गए, उस पर कोई अमल नहीं किया गया, इसलिए कंपनी अपना काम समेट रही है. दो मंत्रियों का इस परियोजना को लेकर परस्पर विरोधी बयान, कंसल्टेंट कंपनी का परियोजना से हाथ खींच लेना नमामी गंगे के लिए शुभ संकेत नहीं हैं. वर्ष 2014–15 में गंगा सफाई के लिए बजट आवंटित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि सभी हितधारकों द्वारा ठोस प्रयासों के अभाव में वांछित नतीजे नहीं मिले थे.

नमामी गंगे मिशन शुरू करने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई थी ताकि अलग-अलग मंत्रालयों, पंचायतों, और गंगा सफाई अभियान से जुड़े दूसरे हितधारकों में समन्वय स्थापित किया जा सके और वे एक साथ मिल कर इस मिशन को अंजाम तक पहुंचा सकें. लेकिन जब केंद्र सरकार के दो मंत्रालयों में ही समन्वय नहीं है तो दूसरे हितधारकों की बात कौन करे. ऐसे में अगर जापानी कंपनी अपने सुझाव पर अमल नहीं होने की शिकायत करते हुए इस परियोजना से अलग हो जाती है तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं. इस बात पर भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जो काम सरकार को करना था

(शेष पृष्ठ 2 पर)

दो साल, तीन साल, पांच साल या...

अगर आप समझते हैं कि हमने स्वच्छ गंगा की दिशा में कदम उठाना छोड़ दिया है, तो आप गलत समझते हैं. किसी बड़ी दौड़ पर जाने से पहले धावक कुछ पलों के लिए रुकता है, गंतव्य का आकलन करता है और तब दौड़ शुरू करता है. हमारा गंतव्य अक्टूबर 2018 है और हम दुनिया को दिखा देंगे कि गंगा दुनिया की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक है.

-उमा भारती, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री

गंगा की सफाई को लेकर अभी प्लानिंग लेवल पर ही काम चल रहा है. अगले तीन साल के दौरान गंगा के निर्मलीकरण की दिशा में ठोस काम लोगों को दिखाई देना लगेगा. गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उसमें गिरने वाला कचरा और सीवेज को रोकने की दिशा में काम चल रहा है. जब तक गंगा में गिरते नालों को नहीं रोका जाएगा, तब तक इसकी प्रगति पर चर्चा करना ठीक नहीं है.

-पीयूष गोयल, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री

पांच वर्ष में गंगा की सफाई होगी. इस योजना में केंद्र सरकार धन की कोई कमी नहीं आने देगी. 15 स्थानों पर जलशोधन संयंत्र स्थापित करने का कार्य जल्द आरंभ कर दिया जाएगा.

-नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री

118 शहर, 144 नाले कैसे साफ हो गंगा

विजय विद्रोही

हाल में मेरा गोमुख से लेकर गंगोत्री, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद और बनारस जाना हुआ था. गोमुख का अनुभव ये रहा कि वहां 500 मीटर के भीतर जाने की मनाही है, लेकिन लोग वहां जाते हैं, नहाते हैं. नए कपड़े पहनते हैं और पुराने कपड़े वहीं छोड़कर चले जाते हैं. सर्दी ज्यादा पड़ती है तो लोग थर्मस में चाय भरकर ले जाते हैं, चाय पीने के बाद कप वहीं फेंक कर चले जाते हैं. पान मसाला और अन्य खाने वाली चीजों के रैपर आदि वहीं फेंक देते हैं. गोमुख में इस तरह का कृत्य लोगों की मानसिकता को दर्शाता है. तीन साल पहले मुझे यहां एक अमेरिकी नौजवान मिला था. मुझसे कहने लगा कि हमलोग आपकी तरह नदियों की पूजा नहीं करते, लेकिन हम नदियों को साफ जरूर रखते हैं. जहां तक गंगोत्री की बात है, गंगोत्री में सुरेश रैंगवाल है जो गंगोत्री समिति मंदिर से जुड़े हैं, उनका कहना था कि एक-डेढ़ महीने पहले उमा भारती यहां आई थीं. उन्होंने उमा भारती से कहा कि सफाई को लेकर कुछ होना चाहिए. उमा भारती ने कहा कि मैं कसम खाती हूं कि मैं गंगा को साफ करूंगी. लेकिन वहां पर भी जो धर्मशालाएं हैं, होटल बने हुए हैं, उसकी गंदगी गंगा में जा रही है. लोगों ने स्थानीय स्तर पर मिलकर गड्ढे खोदे हैं ताकि गंदगी को नदी में जाने से रोका जा सके. तीन साल का मेरा अनुभव ये रहा कि कचरा पात्र पहले भी थे, अब भी हैं. पहले कचरा, कचरा पात्रों के अंदर कम, बाहर ज्यादा होता था. लेकिन इस बार गंगोत्री और खासकर हरिद्वार में मैंने देखा कि लोग अब कचरा, कचरा पात्र में डाल रहे हैं.

हरिद्वार की बात करें तो यहां रोज शाम को गंगा आरती होती है. हर आदमी गंगा की कसम खाता है कि वह गंगा को साफ रखेगा, गंगा में साबुन का इस्तेमाल नहीं करेगा, कपड़े धोएगा नहीं. लेकिन, सुबह होते ही लोग कसम भूल जाते हैं. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का अध्ययन बताता है कि एक आदमी जो पूजा सामग्री लेकर आता है, उसमें से करीब 600 ग्राम कचरा वहीं छोड़कर चला जाता है. प्लास्टिक, फूल-मालाएं, अगरबत्तियां आदि. हरिद्वार में ही जगजीतपुर में 40 एमएलडी के एसटीपी की नींव उमा भारती ने रखी थी. एक साल बाद भी वह नींव वहीं की वहीं है. उस पर कोई भी काम नहीं हुआ है. अगर, हम इलाहाबाद की बात करें तो यहां 8 एसटीपी (सीवर ट्रीटमेंट प्लांट) लगे हुए हैं, जिसमें से 4 बंद हैं. एक प्लांट 200 करोड़ रुपये का है. जो 4 प्लांट काम कर रहे हैं वह भी आधी क्षमता का ही काम कर रहे हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक शोध किया था, जिसके मुताबिक गंगा किनारे 55 एसटीपी हैं. जांच में बोर्ड ने पाया कि 55 में से 15 तो बंद पड़े थे, बाकि के भी अपनी क्षमता से कम पर काम कर रहे थे. यही हालत हमें कानपुर में देखने को मिली. यहां टैनरी से 90 लाख लीटर रासायनिक कचरा निकलता है. लेकिन, वहां के जानकारों के मुताबिक यह मात्रा

(शेष पृष्ठ 2 पर)

गंगा की सौगंध, झूठ बोलो कम

पृष्ठ 1 का शेष

वह काम एनजीटी कर रही है. यही कारण है कि नमामी गंगे की आधिकारिक मंज़ूरी के बाद भी इसके नतीजे उत्साहजनक नहीं दिख रहे हैं. ज़ाहिर है, उमा भारती अगर गंगा को 2018 तक दुनिया की सबसे साफ़ नदियों की पंक्ति में लाने में सफल रहीं तो यह बेशक मोदी सरकार की बड़ी जीत होगी. लेकिन, ऐसा कर पाना फिलहाल मुश्किल ही दिख रहा है.

सरकारी दावा

मौजूदा केन्द्र सरकार ने एक एकीकृत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामी गंगे की शुरुआत की. लेकिन, नमामि गंगे की घोषणा के एक साल बीतने के बाद भी धरातल स्तर पर अभी तक बेहतर परिणाम नहीं दिख रहे हैं. किसी योजना की सफलता का आकलन करने के लिए एक साल का समय काफी होता है. यदि नमामी गंगे और सरकार की कोशिशों का एक साल का लेखा-जोखा तैयार किया जाए तो निराशा ही हाथ लगती है. अब सवाल यह उठता है कि नमामी गंगे मिशन ने अब तक क्या काम किया है? अब तक इस मिशन द्वारा जितने काम हुए हैं क्या उनसे भविष्य की कोई उम्मीद बंधती है या यह योजना भी गंगा एक्शन प्लान की तरह धराशाई हो जाएगी? अंतिम सवाल एक अन्य सवाल को जन्म देता है कि आख़िर गंगा एक्शन प्लान की विफलता के क्या कारण थे? सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि गंगा के प्रदूषण की मौजूदा स्थिति क्या है? क्या पिछले कुछ वर्षों की तुलना में प्रदूषण की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है या यथास्थिति बनी हुई है? मई 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई थी. यानि इसे शुरू हुए एक साल से ज़्यादा समय बीत चुका है. नमामी गंगे का मक़सद गंगा को समग्र रूप से संरक्षित और स्वच्छ बनाने के लिए क़दम उठाना है. इस मिशन पर अगले पांच वर्षों के दौरान 20 हज़ार करोड़ रुपए ख़र्च होने हैं, जो गंगा की सफाई पर पिछले तीस साल के दौरान ख़र्च की गई रक़म से चार गुना अधिक है. गंगा की सफाई और संरक्षण का काम फिलहाल नमामी गंगे योजना के तहत चल रहा है. अब सवाल यह उठता है कि एक वर्ष के दौरान क्या गंगा की हालत में कोई सुधार हुआ है या नहीं? सरकार की मानें तो सुधार हुआ है. केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर के अनुसार गंगा में औद्योगिक कचरे के बहाव में 35 प्रतिशत की कमी आई है. सरकार का दावा इस बुनियाद पर आधारित है कि उसने नदी में कचरा बहाने वाली औद्योगिक इकाइयों की पहचान कर उन्हें बंद करने या प्रदूषण की निगरानी करने का आदेश दिया है. प्रकाश जावडेकर का कहना है कि डिस्टिलरी और चीनी मिलों के लिए गंदे जल या कचरे के नियमों में बदलाव कर दिया गया है इसलिए ब्लैक लीकर और गंदे पानी का बहाव गंगा में रोक दिया गया है. इसकी वजह से गंगा का प्रदूषण 30-35 प्रतिशत तक कम हुआ है.

सरकारी दावे की हकीकत

एक नज़र गंगा प्रदूषण पर केंद्रित हालिया रिपोर्टों पर भी डालते हैं. सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के

कंसोर्टीयम द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक गंगा बेसिन के अंतर्गत आने वाले राज्यों में हर दिन सीवेज का 12051 एमएलडी गंदा पानी पैदा होता है. जबकि इन राज्यों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता केवल 5717 एमएलडी है. अब अगर केवल उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लें तो यहां चार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में से केवल एक काम कर रहा है, तो 5717 एमएलडी के आंकड़ों में और कमी आ जाएगी. बहरहाल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक़ गंगा में अनुमानतः 7301 एमएलडी सीवेज बहाया जाता है, जबकि इसमें केवल 2126 एमएलडी सीवेज का पानी ग्रहण करने की क्षमता है. गंगा के प्रवाह क्षेत्र में 764 भारी प्रदूषण पैदा करने वाले औद्योगिक यूनिट्स हैं, जिनमें टैनरी, पल्प एंड पेपर, चीनी, कपड़ा और रसायन के यूनिट्स शमिल हैं. ये यूनिट्स 501 एमएलडी कचरा पैदा करते हैं, जिसका अधिकतर हिस्सा गंगा में बहा दिया जाता है. एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक़ नगरपालिकाओं का तकरीबन 14,000 मिट्रीक टन ठोस कूड़ा रोज़ाना गंगा में प्रवाहित होता है.

यूपीपीसीबी रिपोर्ट और गंगा सफाई की हकीकत

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) से गंगा प्रदूषण से संबंधित रिपोर्ट मांगी थी. इस रिपोर्ट में चौंकानेवाले आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं और ये आंकड़े केंद्र सरकार के दावों की भी पोल खोलते हैं. दरअसल यूपीपीसीबी ने जस्टिस स्वतन्त्र कुमार की अध्यक्षता वाली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की खंडपीठ को बताया कि उसने फेज-1, पार्ट-बी (हरिद्वार से कानपुर तक) में 1070 भारी प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक यूनिट्स (एसपीआई) की पहचान की है जो आज भी 219.18 मिलियन लीटर (एमएलडी) कचरा गंगा में बहा रहे हैं. जहां तक नगरपालिका के ठोस कूड़े (एमएसडी) का सवाल है तो यूपीपीसीबी ने एनजीटी को बताया कि हरिद्वार से कानपुर तक कुल 31 शहर हैं, जो गंगा या उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हैं. इन 31 शहरों में से केवल चार शहर, कन्नौज, कानपुर, मोरादाबाद और बरेली, ऐसे हैं जहां एमएसडी ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद हैं. दरअसल सरकारें कचरों के निपटारे को लेकर कितनी गंभीर हैं, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि उपरोक्त चार शहरों/महानगरों के एमएसडी ट्रीटमेंट प्लांट्स में से केवल कन्नौज का प्लांट काम कर रहा है. बरेली के प्लांट को ट्रिब्यूनल के आदेश पर बंद कर दिया गया है, जबकि मोरादाबाद और कानपुर के प्लांट्स ऑपरेशनल नहीं हैं. हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर प्लांट को बहाल करने के लिए एक आर्थिक पैकेज की मंज़ूरी दे रखी है. जहां तक उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक पर प्रतिबंध का सवाल है, तो यूपीपीसीबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्पूर्ण राज्य में दिसम्बर 2015 से हर तरह के प्लास्टिक बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री और ढुलाई पर प्रतिबंध लगा दिया है. लेकिन, प्लास्टिक के मामले में सरकारें या आम लोगों को जो रवैया है उसे देखते हुए इसे महज़ कागज़ी खानापूर्ति ही कहा जा सकता है. बहरहाल, जिस मात्रा में प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ गंगा में छोड़े जा रहे हैं उसे लेकर ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यूपीपीसीबी को खरी खोटी सुनाते हुए उसे राज्य के अलग-अलग शहरों द्वारा गंगा में छोड़े जा रहे घरेलू और औद्योगिक कचरे की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. हाल में प्रकाशित खबरों के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर के कुछ औद्योगिक यूनिट्स राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिबंध के बावजूद गंगा के सहायक नालों में खतरनाक औद्योगिक कचरा प्रवाहित कर रहे हैं. बिजनौर ज़िले में ऐसे दर्जन भर नाले हैं, जहां कम से कम 21 औद्योगिक यूनिट्स हैं जो खतरनाक रसायन-युक्त कचरा इन नालों में बहा रहे हैं. वहीं कानपुर की बदनाम टैनरीज (चमड़ा उद्योग) में भी काम जारी है और उसका दूषित कचरा बदस्तूर गंगा में गिर रहा है. कानपुर के आस-पास गंगा में प्रदूषण की ताज़ा स्थिति का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कानपुर से कुछ किलोमीटर दूर उन्नाव ज़िले के शुक्लगंज घाट पर कई मरी हुई मछलियां पाई गईं. इससे मिलती जुलती रिपोर्ट वाराणसी से भी आ रही है, जहां गंगा किनारे रहने वाले लोगों में दांत और चर्म रोग की शिकायत बढ़ रही है.

गंगा एक्शन प्लान की असफलता से सीखना नहीं चाहती सरकार

1984 में गंगा बेसिन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक सर्वे किया था. इस रिपोर्ट में बोर्ड ने गंगा के प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताई थी. इसके बाद, यानी 1985 में गंगा एक्शन प्लान फेज वन की शुरुआत हुई. 15 साल के प्रयास के बाद, हज़ारों करोड़ रुपये ख़र्च करने के बाद फेज वन को साल 2000 में बंद कर दिया गया. इसी दौरान गंगा एक्शन प्लान फेज टू भी 1995 में शुरू किया गया. एक अनुमान के मुताबिक साल 2014 तक गंगा सफाई की इन योजनाओं पर चार हज़ार करोड़ रुपये से भी अधिक ख़र्च किए गए. इसके बाद भी सवाल वही है कि क्या गंगा स्वच्छ हुई? कमी कहां रह गई थी? वैज्ञानिकों के मुताबिक गंगा में दो करोड़ नब्बे लाख लीटर प्रदूषित कचरा प्रतिदिन गिर रहा है. विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश की 12 फीसदी बीमारियों की वजह प्रदूषित गंगा जल है. वाराणसी के घाटों पर प्रदूषण खतरनाक स्तर को छू चुका है. यहां के पानी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड 25 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गया है. सामान्य पानी में यह प्रति लीटर तीन मिलीग्राम से कम होना चाहिए. इसके 15 मिलीग्राम से अधिक होने पर जल को अत्यधिक प्रदूषित माना जाता है. केवल हरिद्वार में ही 3.7 करोड़ लीटर और इसके किनारे बसे 12 बड़े शहरों से प्रतिदिन करीब 9 करोड़ लीटर मल-जल गंगा नदी में गिरता है. गोमुख से बंगाल की खाड़ी तक 2510 किलोमीटर की यात्रा में गंगा को करीब एक अरब लीटर मल-जल ढोना पड़ रहा है. गंगा एक्शन प्लान के तहत गंगा के किनारे बसे शहरों और कारखानों में गंदे और जहरीले पानी को साफ करने के प्लांट लगाए गए थे. इनसे गंगा के पानी में थोड़ा सुधार जरूर हुआ, लेकिन गंगा में गंदगी का गिरना बदस्तूर जारी रहा. अंत में यह पाया गया कि गंगा एक्शन प्लान असफल हो गया है. इस प्लान की सबसे बड़ी खामी शायद यही थी कि उसमें गंगा के बहाव को बढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. गंगा में ग्लेशियरों और झरनों से आने वाले पानी को तो कानपुर से पहले ही नहरों में निकाल लिया जाता है. जमीन का पानी गंगा की धारा बनाए रखता था, लेकिन नंगे पहाड़ों से कट कर आने वाली मिट्टी ने गंगा की गहराई कम करके अब इस स्रोत को भी बंद कर दिया. विशेषज्ञ मानते हैं कि गंगा को बचाने के लिए सबसे पहले हिमालय के ग्लेशियरों को बचाना होगा.

बहरहाल, गंगा सफाई के लिए नीतियां बनाने से पहले अन्य तथ्यों पर भी नजर डालने की जरूरत है. लगभग नौ राज्यों की नदियों का पानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गंगा में मिलता है. इन नदियों के प्रदूषण का असर भी गंगा पर पड़ता है. गंगा में हिमालय क्षेत्र में टिहरी तथा अन्य स्थानों पर बांध बना दिए गए, इससे गंगा के जल प्रवाह में भारी कमी आई है. गंगा पर कई बांध बनाए गए हैं, कई का निर्माण प्रस्तावित है. एक तो पहले ही हिमालय के सघन वनों की कटाई से हिमालय क्षतिग्रस्त था, इन बांधों के कारण हिमालय क्षेत्र में तबाही का सिलसिला शुरू हो चुका है. उत्तराखंड का हादसा उसका एक उदाहरण है. पूरा हिमालय क्षेत्र प्रलय क्षेत्र बनता जा रहा है. दूसरा तथ्य ये भी है कि नदियों के प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है कल-कारखानों के जहरीले रसायनों एवं रंगीन या काले तरल का गिराया जाना. जब कल-कारखानों या थर्मल पावर स्टेशन का गर्म पानी तथा जहरीला रसायन नदी में गिरता है तो नदी की स्वयं शुद्धीकरण की क्षमता नष्ट हो जाती है. ■

क्या इन नदियों से सीखेगा भारत !

- **टेम्स नदी :** यह दुनिया की सबसे स्वच्छ नदी है. इसे लंदन की गंगा भी कहा जाता है. करीब 80 लाख की आबादी वाला लंदन शहर टेम्स के किनारे बसा है. यह नदी 346 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है. पहले यह नदी काफी प्रदूषित थी, जिस कारण से कई लोगों की मौत भी हो गई. इसकेबाद इसकी सफाई की गई और यह दुनिया की सबसे स्वच्छ नदी में शुमार की जाने लगी.
- **तारा नदी, मोंटेनेग्रो और बोस्निया :** दुनिया की दूसरी सबसे स्वच्छ नदी में तारा नदी का नाम लिया जाता है. यह नदी मोंटेनेग्रो और बोस्निया के बीच बहती है. यह ग्राड कैन्यन के बाद दूसरी सबसे लम्बी और गहरी घाटी का निर्माण करती है, जिसकी लम्बाई 78 किलोमीटर है. इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है.
- **सेंट क्रोइक्स नदी, अमेरिका :** सेंट क्रोइक्स नदी दुनिया की तीसरी सबसे स्वच्छ नदी है. इसे मिसिसिपी की सहायक नदी के रूप में जाना जाता है. इस नदी की कुल लम्बाई 272 किलोमीटर है.
- **टॉर्न नदी, स्वीडन :** स्वीडन में टॉर्न नदी को टॉर्नियों केनाम से भी जाना जाता है. यह दुनिया की चौथी सबसे स्वच्छ नदी है. यह उत्तरी स्वीडन और फिनलैंड के बीच बहती है.
- **ली नदी, गुआंग्जी, चीन :** दुनिया की सबसे स्वच्छ नदियों में चीन के गुआंग्जी क्षेत्र में बहने वाली ली नदी भी शामिल है. स्वच्छता के मामले में इसका नाम 5वें नम्बर पर आता है. यह नदी माओआर माउंटेन से निकलकर गुली नदी में मिल जाती है.

118 शहर, 144 नाले, कैसे साफ हो गंगा

पृष्ठ 1 का शेष

150 लाख लीटर के करीब है. हालांकि, टैनरी उद्योग का कहना है कि हम अपना कचरा तो एसटीपी में डालते हैं और एसटीपी के रख-रखाव के लिए हर साल पैसा भी देते हैं. अब, एसटीपी ही ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या किया जा सकता है. ऐसे ही कानपुर में सीसामाऊ का नाला है, जहां से 15 करोड़ लीटर गंदा पानी रोज निकलता है और गंगा में जाता है. वहां एक स्थानीय निवासी वकार भाई से मेरी बात हुई. उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 40 साल से यहां रह रहा हूं. मैंने सीसामाऊ नाले को ऐसे ही बहते हुए देखा है. गंगा एक्शन प्लान वन आया, गंगा एक्शन प्लान टू आया. उसके बाद और योजनाएं आईं. जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत कानपुर को 360 करोड़ रुपये मिला. लेकिन, कुछ नहीं हुआ. बनारस की बात करें तो बनारस के घाट को चमका दिया गया है. अस्सी घाट चमक रहा है, लेकिन इससे मात्र दो किलोमीटर की दूरी पर नांगल का नाला है. ये नाला पिछले कई सालों से वैसा का वैसा ही पड़ा है. सीवर लाइन बिछाने का काम जरूर तेजी से चल रहा है. अखिलेश यादव ने भी थोड़ी प्रेरणा ली है. वरुणा नदी पर 319 करोड़ रुपये की लागत पक्के घाट बनाने का काम चल रहा है. दूसरी तरफ गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट है, वहां बने विद्युत शवदाह गृह में बहुत कम लोग आते हैं. 2018 तक गंगा को साफ करने की बात असंभव है. सबसे बड़ी बात है कि गंगा के किनारे 118 शहर हैं, 144 नाले हैं, जिनका गंदा पानी सीधे गंगा में गिरता है. इन 118 शहरों में एसटीपी लगाना है. अभी तो जुलाई के अंत तक इसके लिए टेंडर ही निकलना है. एक एसटीपी के शुरू होने में ढाई से तीन साल लगते हैं. इस हिसाब से तो 2018 तक कुछ हो ही नहीं पाएगा. ■

(लेखक एबीपी समाचार चैनल से संबद्ध वरिष्ठ पत्रकार हैं)

गंगा के लिए अलग मंत्रालय हो

पृष्ठ 1 का शेष

गौमुख की बात करें, तो वहां पूरे देश से लोग जाते हैं और गोमुख ग्लेशियर के साथ-साथ लोग पूरे रास्ते गंदगी फैलाते हैं. वहां पर लोग प्लास्टिक के साथ-साथ कई चीजें फेंक देते हैं. वहां पर उन्हें गंदगी फैलाने से रोकने वाला कोई नहीं. वहां पर केवल वन विभाग के कुछ अधिकारी तैनात होते हैं. वहां प्रतिदिन लगभग 50, 60, 100 या 150 लोग जाते हैं. कानपुर में टैनरी पर रोक लगाई थी. लेकिन वहां पर एक लिस्ट तैयार करने की बात कही गई थी कि कौन गंदगी फैला रहा, किसके पास ट्रीटमेंट प्लांट है, किससे ले पास नहीं है. लेकिन दो साल में इसका जमीन पर कोई असर नहीं दिखा और न ही कोई बदलाव हुआ. अभी भी गंगा में गंदगी वैसे ही जा रही है. ट्रीटमेंट प्लांट जो बदहाल थे जिनमें पानी जाने का बाद भी साफ नहीं हो रहा था, लेकिन उनको ठीक करने का काम पिछले एक साल में हुआ है. इस एक साल में ट्रीटमेंट प्लान के रख-रखाव का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है. इलाहाबाद में गंगा की स्थिति बिल्कुल खराब है. गंगा और यमुना के किनारे जो अवैध निर्माण चल रहा है उसे कोई रोकने वाला नहीं है. नमामि गंगे के तहत सरकार दो काम कर रही है. एक तो घाटों की सफाई हो रही है और दूसरी गंगा की सफाई. 2500 किलोमीटर में फैली गंगा को 2018 तक साफ कर पाना तो असंभव है. नमामि गंगे में थोड़ा-थोड़ा ही सही, काम हो हो रहा है. घाटों के किनारे बसे लोगों ने मुझे बताया कि उनकी कोई मजबूरी नहीं है कि वे किसी पार्टी या मंत्री को सपोर्ट करें. लेकिन दो साल बाद भी उनके लिए उम्मीद कायम है, वे कहते हैं कि अपनी आंखों के सामने बदलाव देख रहे हैं. उमा भारती जब खेल मंत्री थीं तब भी मैंने उनके साथ काम किया था. उन्होंने उस वक्त काम किया था. अभी मुझे लगता है कि बतौर जल संसाधन मंत्री उमा भारती के पास गंगा सफाई का भी जिम्मा है और सूखे से निपटने की चुनौती और जिम्मेदारी भी. उमा जी ने कहा था कि हर हफ्ते मैं गंगा के किसी न किसी किनारे रहा करूंगी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पा रही हैं. मुझे लगता है कि उनकी मंशा अच्छी है, लेकिन उनके पास पर्याप्त समय नहीं है. गंगा सफाई की जिम्मेदारी अकेले किसी को देनी चाहिए. या तो उमा जी को ही वे जिम्मेदारी अकेले दी जाए या फिर किसी और को. या फिर उनका एमओएस (राज्य मंत्री) ऐसा हो जो गंगा की जिम्मेदारी अकेले संभाल ले. गंगा के लिए दिन के 24 घंटे कम पड़ जाते हैं. एक नदी खत्म होती है तो एक सभ्यता खत्म होती है. अगर हम सभ्यता को खत्म होने से बचाना चाहते हैं, तो हमें गंगा पर विशेष ध्यान देते हुए इसके लिए अलग से एक मंत्रालय बनाना चाहिए. ■

(लेखिका आजतक समाचार चैनल से संबद्ध वरिष्ठ पत्रकार हैं)

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 08 अंक 18
04 जुलाई- 10 जुलाई 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)

सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एच-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

feedback@chauthiduniya.com

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों और पिछड़ों को आरक्षण देने पर जोर

चुनावी बिसात पर भाजपा का दांव

- एएमयू में आरक्षण मसले पर दलितों और पिछड़ों को गोलबंद करने का अभियान
- यूपी के सांसदों-विधायकों को दिल्ली बुलाकर समझाया और काम पर लगाया
- इलाहाबाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एएमयू-रणनीति पर किसी ने कुछ नहीं कहा

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश की अकादमिक राजधानी इलाहाबाद में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से अधिक अहम वह बैठक थी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बुलावे पर 18 जून को दिल्ली में बुलाई गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के सारे सांसद और विधायक मौजूद थे. यह भी कह सकते हैं कि सांसदों-विधायकों की उक्त बैठक के असली सूत्रधार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विचार-वाहक थे. इस बैठक की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी भाजपा सांसद और सभी भाजपा विधायक अनिवार्य रूप से शामिल हुए. राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चुनावी रणनीतियों पर कोई चर्चा नहीं हुई थी और जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उसमें भी उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर कोई उल्लेखनीय जिक्र नहीं हुआ. लेकिन 18 जून को भाजपा सांसदों-विधायकों की जो बैठक दिल्ली में हुई वह उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और उसकी तासीर पूरे देश में असर दिखाने वाली है. दिल्ली के पटेल चेस्ट ऑडिटोरियम में तीन सत्र में सम्पन्न हुई बैठक में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के महासचिव कृष्ण गोपाल ने सांसदों-विधायकों को पूरे मसले पर विस्तार से अवगत कराया और रणनीति समझाई. उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही भारतीय जनता पार्टी ने दलितों और पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने का एएमयू-फार्मूला अख्तियार किया है.

दलितों और ओबीसी समुदाय को भावनात्मक रूप से बसपा, सपा और कांग्रेस से तोड़ कर अपने साथ जोड़ने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय आरक्षण नीति लागू किए जाने का मसला उठाने की रणनीति बनाई है. देश के सारे विश्वविद्यालयों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति-जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था लागू है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं है. हालांकि इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी की छात्र और युवा इकाइयां लंबे अर्से से संघर्ष करती रही हैं, लेकिन कभी यह चुनावी मुद्दा नहीं रहा. भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि यह मसला व्यापक पैमाने पर दलितों और पिछड़ों के हितों से जुड़ा है, लिहाजा यह मुद्दा उनका ध्यान आकर्षित करेगा और चुनाव के पूर्व इसे व्यापक अभियान के तौर पर उठाया जा सकेगा. एएमयू में छात्रों के नामांकन से लेकर व्याख्याताओं और शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति तक में आरक्षण की संवैधानिक प्रणाली लागू नहीं है. भाजपा सांसदों और विधायकों की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि इस मसले पर प्रदेशभर में माहौल बनाया जाए ताकि एएमयू में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का रास्ता भी प्रशस्त हो और चुनाव के पहले दलितों और पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच सार्थक संदेश भी जाए. सारे सांसदों और विधायकों से इस काम में पूरी गति से जुट जाने को कहा गया है.

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण के मसले पर दिल्ली में हुई सांसदों-विधायकों की बैठक के बारे में भाजपा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, संघ ने भी आधिकारिक तौर पर इस बैठक के संदर्भ में कुछ नहीं कहा. लेकिन यूपी के सांसदों और विधायकों को संघ के संयुक्त महासचिव कृष्ण गोपाल ने जो बौद्धिकी दी, वह हम आपको जरूर बताएंगे. कृष्ण गोपाल ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की नीति लागू नहीं कर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बड़ा अपराध कर रहा है. एएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे पर राजग सरकार का रुख संप्रग सरकार को छोड़ कर बाकी पूर्ववर्ती सरकारों के रुख और 1968 में आए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप है. कृष्ण गोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार का रुख वही है जो मौलाना अबुल कलाम आजाद, तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री एमसी छागला और सैयद नुरूल हसन का रुख था. तीनों तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी भी वहां थे. हमारा रुख उच्चतम न्यायालय के फैसले जैसा है. हमने फैसला नहीं बदला, बल्कि संप्रग सरकार ने 2005 में ऐसा किया था. मौजूदा केंद्र सरकार ने कोई नया फैसला नहीं लिया है. केंद्र का फैसला वही है जो 1968 में उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की एक पीठ ने दिया था. ऐसा ही फैसला संविधान सभा ने भी लिया था जिसमें डॉ. बाबा साहब अंबेडकर, मौलाना आजाद और कई मुस्लिम नेता शरीक थे.

उल्लेखनीय है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने इस साल अप्रैल में सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि वह एएमयू को गैर अल्पसंख्यक संस्थान करार देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली संप्रग सरकार के समय दाखिल याचिका वापस ले लेगी. एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का मसला हो या वहां आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं करने का मुद्दा रहा हो, इसे गरम करने की भूमिका पहले से चल रही है. आपको याद ही होगा कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को कुछ दिनों पहले पत्र लिखकर एएमयू में आरक्षण की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की थी. गहलोत ने मीडिया से भी कहा था कि उनके मंत्रालय को जामिया और एएमयू, दोनों विश्वविद्यालयों के बारे में प्रतिवेदन मिलते रहे हैं, जिनमें यह शिकायत की जाती रही है कि अल्पसंख्यक स्टेटस की आड़ में दलित-आदिवासी और ओबीसी छात्रों को संविधान प्रदत्त आरक्षण और अन्य सुविधाएं सिरे से नकारी जा रही हैं.

यानी, यह साफ है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले एएमयू में दलितों और ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने का मसला गरमाया जाएगा और आरक्षण-कार्ड को नए स्टाइल से चुनावी बिसात पर फेंका जाएगा. लेकिन इस मसले को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से दूर रखा गया और हफ्तेभर बाद दिल्ली में बैठक बुला कर इस पर रणनीति तैयार करने पर विचार-विमर्श किया गया. जबकि इलाहाबाद में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर देशभर की निगाह लगी हुई थी. राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी उम्मीद थी कि कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके बारे में घोषणा की जाएगी. विधानसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर कुछ अंतरविरोध ही सामने आए, पार्टी ने इस पर कोई आधिकारिक राय जाहिर नहीं की. लोगों को यह लग रहा था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रित होगा, लेकिन वह भी नहीं हुआ. भाजपा कार्यकारिणी असम विधानसभा चुनाव में जीत और केरल में संघर्ष को लेकर आत्मरतिगान ही करती रही. लेकिन इलाहाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी-केंद्रित भाषण से यह जरूर स्पष्ट हुआ कि भाजपा किस इरादे से चुनाव में उतरने वाली है. यूपी चुनाव में उतरने के पहले केंद्र की भाजपा सरकार के मुखिया ने यह साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की लड़ाई सपा और बसपा से ही होगी, अन्य कोई भी दल उसके रास्ते में नहीं है. भाजपा यह मान चुकी है कि कांग्रेस की यूपी में कोई बिसात नहीं है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई वरिष्ठ नेताओं के मौद्रिक संकेत भी आने वाले दिनों के राजनीतिक रिश्ते बता रके थे. मसलन, कौन नेता अब नेतृत्व से नाराज नहीं है, या नेतृत्व किस नेता के साथ तनाव खत्म कर बेहतर रिश्ते की तरफ बढ़ रहा है.

बहरहाल, उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को केंद्र में रख कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को देखें तो यह बिल्कुल साफ है कि भाजपा इस बार चुनाव में अन्य सारे राजनीतिक दलों को उस दांव पर रखने की कोशिश जरूर करेगी कि सारे दल यह सार्वजनिक शपथ लें कि अगर जीते तो अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार की एक भी शिकायत नहीं आने देंगे और अगर एक भी शिकायत आई तो कुर्सी छोड़ देंगे. राजनीतिक दलों के लिए यह मुश्किल चुनौती होगी, लेकिन विधानसभा चुनाव के दरम्यान यह मसला सामने आने वाला है कि मोदी के इतने दिन के शासनकाल में भ्रष्टाचार का कौन सा मुद्दा सामने आया और मोदी के पूर्ववर्ती शासनकाल में इतना ही शासन-अवधि में भ्रष्टाचार के कितने मामले उजागर हुए थे. भ्रष्टाचार का मसला विकास के दावों के साथ-साथ जुड़ा हुआ है. आम नागरिक यह समझते हैं कि भ्रष्टाचार के बिना ही विकास असली विकास है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाकी बातें तो वैसी ही चलताऊ राजनीति-प्रेरित रहीं, मसलन, यूपी में विकास की गंगा बहा देंगे, वंचित गांवों में बिजली पहुंचा देंगे, कर्जा चुका देंगे... वगैरह, वगैरह. लेकिन मोदी के भाषण का केंद्रीय संदेश यही रहा कि अगर पांच साल में हमने प्रदेश का कोई नुकसान किया तो हमें लात मारकर निकाल देना. स्पष्ट है कि मोदी ने यह चुनौती दूसरे दलों के सामने भी फेंकी. उन्होंने कहा भी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच प्रदेश को लूटने को लेकर साठगांठ है. मोदी ने विकासवाद को मूल मंत्र बताया और कहा कि जहां-जहां भाजपा की सरकार है, उन प्रदेशों में खुशहाली है.

सम्प्रदायवाद को कोसने वाले नरेंद्र मोदी के समक्ष ही उसी मंच से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कैराना से हिंदुओं के पलायन का मसला उठा दिया और लोगों को उकसाते हुए सपा को उखाड़ कर फेंकने की अपील की. भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सम्पूर्ण रूप से असम विधानसभा चुनाव में मिली जीत में डूबती उतराती रही. जो प्रस्ताव पारित हुआ वह भी असम जीत की चाशनी में ही डूबा हुआ था. भाजपा ने असम जीत के नाम पर खुद के अकेली राष्ट्र-व्यापी पार्टी होने का खम ठोका और घोषित किया कि भाजपा ही भारत का वर्तमान है और भविष्य दोनों है. प्रस्ताव में असम में मिली जीत के अलावा केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में मत-प्रतिशत बढ़ने पर संतोष जताया गया, लेकिन जहां विधानसभा चुनाव सामने है, प्रस्ताव में उसकी कोई चर्चा ही नहीं है. ■

साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण का तानाबाना

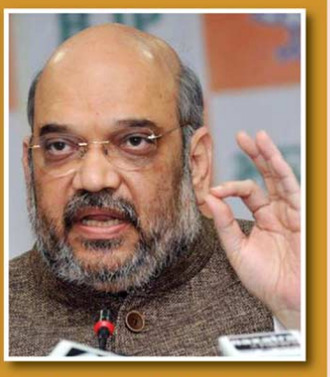

एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर लंबे अर्से से तर्क और प्रतितर्क दिए जा रहे हैं. इन तर्कों और प्रतितर्कों के जाल में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना का मसला भी उलझा हुआ है. तकनीकी तौर पर यह बात खारिज हो चुकी है कि एएमयू की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी. इस्लामी अध्ययन के विद्वान और समाजसेवी सर सैयद अहमद खान ने शिक्षा में पिछड़े मुस्लिम समुदाय के लिए एक संस्थान बनाने की कल्पना की थी. मई 1872 में उनके द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज फंड कमेटी. समिति के प्रयासों से मई 1873 में छोटे बच्चों के एक स्कूल की स्थापना की गई, जो 1876 में हाई स्कूल बना. वर्ष 1877 में तत्कालीन वायसराय लार्ड लिटन ने मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की नींव रखी. 1898 में जब सर सैयद की मृत्यु हुई, तब तक यह कॉलेज एक समृद्ध संस्थान के रूप में अपनी पहचान बना चुका था. माना जाता है कि सर सैयद का मूल उद्देश्य एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का था. लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मांग उनकी मृत्यु के बाद ही मजबूत हुई. 1911 में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन बना और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गठन कर दिया गया. 1920 के एएमयू एक्ट में यह प्रावधान था कि यूनिवर्सिटी की कोर्ट (सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई) में सभी सदस्य अनिवार्य रूप से मुस्लिम ही होंगे. आज़ादी के बाद जब देश में भारतीय संविधान लागू हुआ तब 1920 के एएमयू एक्ट में कुछ जरूरी संशोधन किए गए. इन संशोधनों के जरिए यूनिवर्सिटी के कोर्ट में सभी सदस्यों के मुस्लिम होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, साथ ही इस्लामिक पढ़ाई की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया. 1951 और 1965 में ये संशोधन इसलिए किए गए थे क्योंकि एएमयू एक्ट के पुराने प्रावधान भारतीय संविधान के प्रावधानों के विपरीत थे. लेकिन इसके खिलाफ यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले में सुनवाई की. यहां मुस्लिम समुदाय ने अपने तर्क दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर यह माना ही नहीं कि एएमयू की स्थापना सर सैयद अहमद ने की थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एएमयू की स्थापना तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने की थी. अदालत ने मामले को तकनीकी तौर पर जांचा-परखा. लेकिन भावनात्मक रूप से देखें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि एएमयू की स्थापना सर सैयद के प्रयासों के परिणाम के बतौर ही सामने आई. लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को विशुद्ध तकनीकी तौर पर देखा और 1967 में यह फैसला सुना दिया कि एएमयू की स्थापना मुस्लिम समुदाय ने नहीं, बल्कि तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने की थी. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने यह देखा कि जिस एएमयू एक्ट के तहत एएमयू का गठन हुआ था वह एक संसदीय अधिनियम था, जिसे तत्कालीन सरकार ने पारित किया था. मुस्लिम समुदाय 1920 में एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकता था, क्योंकि उस दौर में ऐसा कोई कानून नहीं था जो उसे ऐसा करने से रोकता. ऐसा कानून 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के गठन के बाद बना. अब यूजीसी की अनुमति के बिना कोई भी विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यदि मुस्लिम समुदाय ने निजी विश्वविद्यालय की जगह संसदीय अधिनियम के जरिए स्थापित हुए विश्वविद्यालय को चुना था तो यह कैसे माना जा सकता है कि इसकी स्थापना एक समुदाय विशेष ने की थी! न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि यह हो सकता है कि 1920 का अधिनियम मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रयासों से ही पारित हुआ हो. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस अधिनियम से जो यूनिवर्सिटी स्थापित हुई, वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने स्थापित की थी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही घोषित रूप से एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा छिन गया. विडंबना यह है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार के उस मंत्रिमंडल ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के लिए संशोधन को मंजूरी दी थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल थे. यह संशोधन सदन के पटल पर लाया गया था लेकिन इसके पारित होने से पहले ही जनता पार्टी की सरकार गिर गई. 1981 में कांग्रेस सरकार ने एएमयू एक्ट में संशोधन कर दिया. इन संशोधनों से 1967 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पलट दिया गया और 1920 के मूल एक्ट की प्रस्तावना में भी बदलाव कर दिया गया. 1920 के एक्ट में दी गई यूनिवर्सिटी की परिभाषा को भी इस संशोधन के जरिए बदल दिया गया. मूल एक्ट में लिखा गया था, यूनिवर्सिटी मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. लेकिन 1981 में इसे संशोधित कर लिखा गया, यूनिवर्सिटी मतलब भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया शैक्षिक संस्थान, जिसका जन्म मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के रूप में हुआ था और जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया.1981 के संशोधन का किसी भी दल ने विरोध नहीं किया था. तब जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन किया था. उस दौर में भाजपा के उपाध्यक्ष रहे राम जेठमलानी और जनता पार्टी के सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी भी संशोधनों के समर्थन में थे. वर्ष 2005 में एएमयू के एक फैसले ने फिर से विवाद गरमा दिया. एएमयू ने 2005 से मेडिकल के पोस्ट ग्रैजुएट पाठ्यक्रमों में मुस्लिम छात्रों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था कर दी. एएमयू के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. अक्टूबर 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा फिर खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के 1967 के फैसले को सही करार देते हुए 1981 के संशोधनों को असंवैधानिक करार दे दिया. 50 प्रतिशत मुस्लिम छात्रों को आरक्षण देने के फैसले पर भी रोक लगा दी गई. केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सरकार ने इस फैसले के विरोध में अपील दाखिल की. लेकिन हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पूर्व के फैसले को सही ठहराया और माना कि एएमयू की स्थापना मुस्लिम समुदाय ने नहीं, बल्कि तत्कालीन सरकार ने की थी, लिहाजा उसे अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता. इस फैसले के खिलाफ भी तत्कालीन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की, जो अभी लंबित है. मौजूदा केंद्र सरकार ने उस अपील को वापस लेने का फैसला किया है, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला ही मान्य रहेगा. भाजपानीत केंद्र सरकार का यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक है. स्वाभाविक है कि केंद्र के इस फैसले से साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण होगा, लेकिन इस बार के साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण का जाल अकादमिक है और सोची-समझी रणनीति से बुना गया है.

नक्सलियों के निशाने पर माननीय

सुनील सौरभ

बिहार में राजनीति को सशक्त बनाने में जितना योगदान मगध का है, उससे कहीं ज्यादा योगदान प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के फलने-फूलने के लिए अवसर प्रदान करने का भी है. संयुक्त बिहार में मगध क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठनों ने सत्तर के दशक में जब अपने पांव फैलाने शुरू किए थे, तब लोगों को इसका अंदाजा नहीं था कि यह क्षेत्र नक्सलियों की मजबूत शरणस्थली बन जाएगा. लेकिन सामाजिक असमानता व राजनीतिज्ञों की स्वार्थ भरी राजनीति ने मगध क्षेत्र में नक्सलियों को फलने-फूलने का पूरा मौका दिया. इसी का नतीजा है कि प्रतिबंधित नक्सली संगठनों ने मगध क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाकर जब जो चाहा, सो किया. मामला चाहे बड़े किसानों की भूमि पर लाल झंडा गाड़ने का हो या पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाकर किसी की हत्या करना या फिर विकास कार्यों में लेवी वसूलना या फिर खिलाफ में बयान देने वाले राजनेताओं को टारगेट कर हत्या करने का हो, सभी में नक्सली सफल रहे हैं.

इन मामलों में नक्सलियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने की बात भी सामने आती रही है. इन दिनों पुन: नक्सली संगठनों ने मगध क्षेत्र व इससे बाहर के कई सांसदों और राजनेताओं को चेतावनी दी है कि नक्सलियों के खिलाफ बयानबाजी कम करें, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. उन्होंने नक्सलियों पर कड़ी कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों को भी चेतावनी दी है. नक्सलियों की धमकी से कई राजनेताओं में दहशत है. उनमें से कइयों ने बिहार सरकार से सुरक्षा की मांग की है. कारण यह है कि पूर्व में नक्सली कई राजनेताओं और पुलिसकर्मियों की हत्या कर चुके हैं.

1992 में गया के तत्कालीन सांसद ईश्वर चौधरी की हत्या नक्सलियों ने चुनाव प्रचार के दौरान कोंच विधानसभा क्षेत्र के कठोतिया गांव में कर दी थी. इसी प्रकार 2005 में इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद राजेश कुमार और उनके सहयोगी की हत्या डुमरिया के मैगरा में नक्सलियों ने कर दी थी. इसके अलावा इमामगंज, टिकारी, पैरा समेत कई थानों पर हमला कर नक्सली दर्जनों पुलिसकर्मियों की हत्या कर चुके हैं. हाल में सम्पन्न हुए पंचायत चुनाव में गया जिले के डुमरिया प्रखंड में लोजपा नेता सुदेश पासवान और उनके चचेरे भाई सुनील पासवान की नक्सलियों ने हत्या कर दी. इस घटना के बाद जब राजनेताओं ने नक्सलियों की निंदा की और पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की तो नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर इन सभी को धमकी देना शुरू कर दिया. इसी प्रकार औरंगाबाद में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी करने का आरोप लगाकर एक लकड़हारे की हत्या कर दी. तब मृतक की पत्नी ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि दो नक्सली नेता प्राय: घर आकर उसके साथ दुष्कर्म करते थे. उसने बताया कि मेरे पति ने जब इसका विरोध किया तो उनकी हत्या कर दी गयी. औरंगाबाद के सांसद और वहां के एक विधान पार्षद ने जब मृतक की पत्नी से सहानुभूति जतायी तो नक्सलियों ने इन दोनों के साथ-साथ वहां के एसपी बाबूराम को भी अपने निशाने पर ले लिया. डुमरिया में लोजपा नेता की हत्या के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, लोजपा सांसद चिराग पासवान, पूर्व विधान पार्षद अनुज कुमार सिंह ने इस हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी. नक्सलियों को नेताओं का बयान नागवार लगा. नक्सलियों ने नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि वे घड़ियाली आंसू न बहाएं, अन्यथा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. इस मामले में महत्वपूर्ण है कि पूर्व मुख्यमंत्री और इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक जीतनराम मांझी और लोजपा के सांसद चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है. जबकि पूर्व विधान पार्षद अनुज कुमार सिंह की सुरक्षा वापस ले ली गई है और उन्हें सिर्फ दो सुरक्षाकर्मी मिले हैं. अनुज कुमार सिंह बहुत पहले से नक्सलियों के निशाने पर रहे हैं. इनका घर डुमरिया प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है और इनका राजनीतिक क्षेत्र भी मगध प्रमंडल का ग्रामीण क्षेत्र है. ग्रामीण क्षेत्रों में इनका अक्सर आना-जाना होता है. अनुज सिंह ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भी अपनी सुरक्षा के संबंध में लिखा था. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार को निर्देश दिया था कि अनुज सिंह की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उन्हें मुकम्मल सुरक्षा दी जाये. लेकिन अभी तक उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है और नक्सलियों की ओर से उन्हें बराबर धमकी भी दी जा रही है. इस बात की सूचना गया जिला प्रशासन को भी है. औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह, विधान पार्षद राजन कुमार सिंह तथा औरंगाबाद के एसपी बाबूराम भी नक्सलियों के निशाने पर हैं. नक्सलियों ने औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना के पचरुखिया निवासी अवधेश भोक्ता एवं देव प्रखंड के उप प्रमुख मनोज कुमार सिंह की हत्या पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर कर दी थी. इसके बाद पुलिस ने नक्सलियों का सहयोग करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इन घटनाओं पर औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह और एमएलसी राजन कुमार सिंह ने बयान दिया तो नक्सली भड़क उठे. भाकपा माओवादी ने एक पर्चा में सांसद सुशील कुमार सिंह तथा एमएलसी राजन कुमार सिंह और औरंगाबाद के एसपी बाबूराम को सबक सिखाने की चेतावनी दी है. प्रतिबंधित नक्सली संगठन सामना होने पर ही लाचारी में पुलिस से मुठभेड़ करते हैं.

नक्सली संगठनों ने अबतक गुरिल्ला युद्ध की तरह ही अपने टारगेट पर कार्रवाई की है या फिर बारुदी सुरंग लगाकर हिंसक कार्रवाई को अंजाम दिया है. इन्हीं सब घटनाओं और स्थितियों को देखते हुए मगध क्षेत्र के राजनेता नक्सलियों से भयभीत हैं. विशेषकर झारखंड की सीमा से लगे बिहार के क्षेत्रों में राजनीति करने वाले लोगों को नक्सली प्राय: डराते-धमकाते रहते हैं. यही स्थिति झारखंड की सीमा से लगे बिहार के थाने में पदस्थापित पुलिसकर्मियों का है. सच कहा जाये तो ये पुलिसकर्मी भी नक्सलियों के रहमोकरम पर ही अपनी सुरक्षा कर पाते हैं. यही कारण है कि अर्द्धसैनिक बलों के तमाम प्रयासों के बाद भी नक्सलियों के खिलाफ कारगर कार्रवाई नहीं हो पाती है. स्थानीय थानों से अर्द्धसैनिक बलों को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है. स्थानीय स्तर पर थानों को किसी भी नक्सली या अपराधियों के संबंध में पूरी जानकारी होती है. यही कारण है कि नक्सली मगध क्षेत्र में पुलिस और राजनेताओं को अपने निशाने पर लेकर धमकाने में लगे हैं. ■

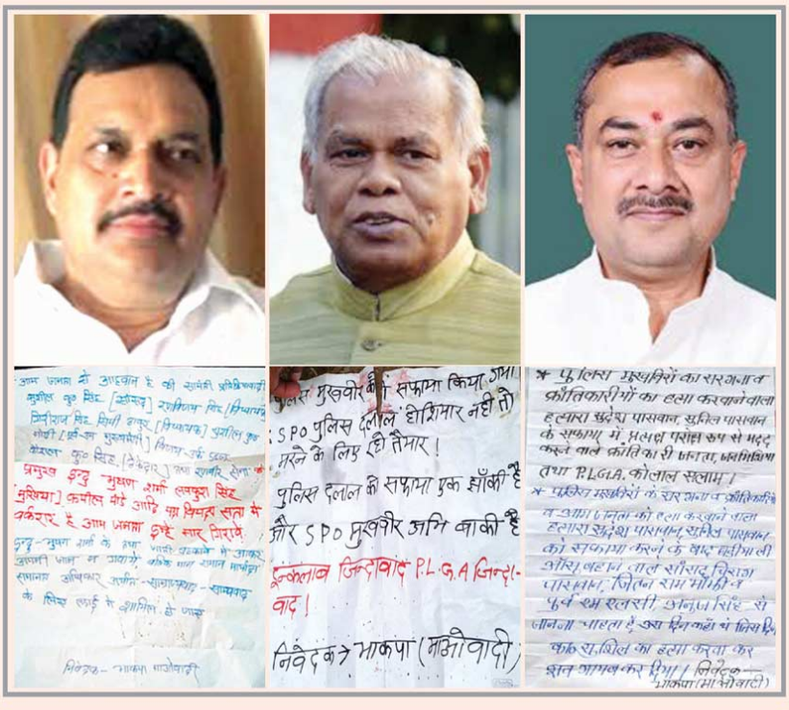

> नक्सली संगठनों ने अबतक गुरिल्ला युद्ध की तरह ही अपने टारगेट पर कार्रवाई की है या फिर बारुदी सुरंग लगाकर हिंसक कार्रवाई को अंजाम दिया है. इन्हीं सब घटनाओं और स्थितियों को देखते हुए मगध क्षेत्र के राजनेता नक्सलियों से भयभीत हैं. विशेषकर झारखंड की सीमा से लगे बिहार के क्षेत्रों में राजनीति करने वाले लोगों को नक्सली प्राय: डराते-धमकाते रहते हैं.

> इन घटनाओं पर औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह और एमएलसी राजन कुमार सिंह ने बयान दिया तो नक्सली भड़क उठे. भाकपा माओवादी ने एक पर्चा में सांसद सुशील कुमार सिंह तथा एमएलसी राजन कुमार सिंह और औरंगाबाद के एसपी बाबूराम को सबक सिखाने की चेतावनी दी है. प्रतिबंधित नक्सली संगठन सामना होने पर ही लाचारी में पुलिस से मुठभेड़ करते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

डीआरडीओ का प्रताड़ित व्हिसिलब्लोअर

भारत में व्हिसिलब्लोअर के साथ कितना क्रूर व्यवहार होता है, यह कोई नई और अनोखी बात नहीं है. हरियाणा के आईएस अधिकारी अशोक खेमका और भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी का उदाहरण अब भी लोगों की स्मृति में ताजा है. अब एक और व्हिसिलब्लोअर की खबर आई है कि कैसे मोदी सरकार के अच्छे दिन में भी इस अधिकारी को प्रताड़ित किया जा रहा है. इस अधिकारी का नाम प्रकाश सिंह है, जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं. प्रकाश सिंह को उनके वरिष्ठों द्वारा बार-बार तबादला कर परेशान किया जा रहा है. उनकी गलती यह है कि उन्होंने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) के प्रयोगशाला और डीआरडीओ मुख्यालय में होने वाली अनियमितता और अवैध कार्यों के बारे में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से शिकायत की है. साल 2008 की बात है. सिंह की शिकायत की वजह से ही एक वरिष्ठ डीआरडीओ वैज्ञानिक पर आरोप पत्र दाखिल किया गया था और एक महिला वैज्ञानिक की सेवा रद्द कर दी गई थी. यही वजह है कि उसके बाद से इस अधिकारी का उत्पीड़न शुरू हो गया था. उन पर आरोप पत्र दाखिल किया गया था और 2012 में 49 साल की उम्र में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया. हालांकि, तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी के हस्तक्षेप के बाद वे फिर बहाल हो पाने में कामयाब हुए. वर्तमान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी सिंह के खिलाफ दायर आरोप पत्र को खारिज कर दिया और आदेश दिया है कि उनकी सेवानिवृत्ति अवधि को ड्यूटी अवधि के रूप में माना जाए. हैरानी की बात यह है कि पर्रिकर के आदेश के बावजूद सिंह की दुर्दशा में ज्यादा अंतर नहीं आया है. हालांकि, मंत्री ने डीआरडीओ से कहा कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने सिंह को परेशान किया है. लेकिन, इस दिशा में भी प्रगति संतोषजनक नहीं है. ■

रॉ के पूर्व बाबू पर आरोप

यह अच्छी बात है कि अति गोपनीय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ), देश की विदेशी खुफिया एजेंसी, अक्सर खबरों में नहीं आती है. हालांकि, मध्य प्रदेश कैडर और 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी एके धस्माना के नाम की चर्चा अगले रॉ चीफ के रूप में होनी शुरू हो गई है. मौजूदा रॉ चीफ राजिंदर खन्ना की जगह उनका नाम सामने आ रहा है. खन्ना का कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है. इस बीच, सीबीआई की विशेष अदालत ने एजेंसी को रॉ के पूर्व प्रमुख एके वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है. वर्मा पर सीक्रेट सर्विस के लिए आवंटित धन में हेराफेरी करने और व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप है. आरोपों की गंभीरता का इसी से पता चलता है कि शिकायतकर्ता आरके यादव खुद रॉ के पूर्व अधिकारी हैं और मजबूती से 2009 से मामले को आगे बढ़ा रहे हैं. यादव ने वर्मा पर आरोप लगाया है कि 1987-1990 के बीच अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने गबन और पद का दुरुपयोग किया. वर्मा ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि यादव एक असंतुष्ट अधिकारी है जिसे उसके कार्यकाल के दौरान सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और केवल बदले की भावना से वह ऐसा कर रहा है. सच तो शायद तब सामने आएगा जब तीन महीने बाद सीबीआई जांच का निष्कर्ष सामने आएगा. ■

राजन का महत्व

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन द्वारा सितंबर में अपने कार्यकाल के अंत में पद से हटने के फैसले की पृष्ठभूमि में यह एक महत्वपूर्ण खबर आई है. आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एचआर खान के उत्तराधिकारी की खोज के लिए एक पैनल कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में बनाया गया है. पहले ऐसा पैनल रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में बनता था. हालांकि राजन अब भी चयन समिति के एक सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे. लेकिन प्रेक्षकों का कहना है कि चयन पैनल में राजन की राय को ज्यादा महत्व शायद ही दिया जाए. प्रेक्षक इसके लिए एक पिछला उदाहरण देते है. सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा के उत्तराधिकारी की तलाश के लिए बने पैनल की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव ने की थी और सदस्य के रूप में आर्थिक मामलों के सचिव थे. ■

यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था का सच और सपा की प्राथमिकता उजागर

असामाजिकों से समाजवादियों का मेल

दीनबंधु कबीर

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले जो-जो होना चाहिए, वह हो रहा है. चुनाव के पहले राजनीतिक दल नैतिकता-सिद्धांत को बिल्कुल बेशर्मी से ताक पर रख देंगे, वह हो रहा है. चुनाव के पहले इधर का पाला छोड़ कर उधर जाने और उधर का खेमा छोड़ कर इधर भागने का सिलसिला भी तेज हो रहा है. चुनाव के पहले आरोप-प्रत्यारोप के हथकंडे बेधड़क इस्तेमाल में आएंगे, वह भी जारी है. भारतीय लोकतंत्र का यही असली फिल्म है, जिसका नाम है 'कटुसत्य', बाकी सब जो दिखाया जाता है, वह सब सत्य के नाम पर 'राम नाम सत्य है'.

उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बदहाली का सत्य लोगों को पता चल गया, जब कुख्यात अपराधी सरगना मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया गया. समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता क्या है, इसका लोगों को एहसास हो गया. मुख्तार अंसारी को सपा में शामिल करने और उसके कौमी एकता दल का सपा में विलय कराने के मुलायम के फैसले को लेकर पार्टी में नौटंकी भी खूब दिखाई गई. अखिलेश नाराज होते दिखे, अपने मंत्रिमंडल से वरिष्ठ मंत्री बलराम यादव को निष्कासित करने का प्रहसन भी खेला, लेकिन लोगों को यह अच्छी तरह समझ में आया कि यह राजनीतिक-नौटंकी दरअसल प्रदेश की जनता के साथ खेली जा रही है. जो लोग सपा को नजदीक से जानते हैं, उनके मन में इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने जो फैसला ले लिया, उसे वे खुद बदल सकते हैं, दूसरा कोई भी उसे बदल नहीं सकता. अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री पद भी मुलायम के उसी अटल फैसले का प्रतिफल है, जिसमें किसी दूसरे की एक भी नहीं चली, चाहे शिवपाल यादव नाराज होते रहें या आजम खान खफा होते रहें. तो सत्य यही है कि सारा प्रहसन यूं ही खेला जाता रहेगा और अखिलेश मान भी जाएंगे और मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी के बैनर से विधानसभा चुनाव होने तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक सह आपराधिक ध्रुवीकरण का अपना एकसूत्री अभियान जारी रखेंगे. सपा के ही एक नेता ने कहा कि मुख्तार अंसारी की पार्टी के सपा में विलय को लेकर अखिलेश यादव इतने ही नाखुश थे तो इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया?

मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी में शामिल करने की वकालत करने वाले अखिलेश कैबिनेट के शिक्षा मंत्री बलराम यादव मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए गए, लेकिन उन्होंने बड़े भावुक और नपे-तुले अंदाज से मुलायम के प्रति वफादारी और अखिलेश के प्रति चाटुकारी के शब्द गढ़े. बलराम ने कहा, 'समाजवादी पार्टी, नेता जी और मेरे रिश्ते अपरिवर्तनीय हैं.' मुख्तार को सपा में शामिल करने की हिमायत में शिवपाल सिंह यादव भी शामिल थे, लेकिन निष्कासन के प्रहसन से शिवपाल को अलग रखा गया, क्योंकि शिवपाल पर वह प्रहसन चलता भी नहीं. मुख्तार अंसारी का कौमी एकता दल पूर्वांचल में अपना अलग किस्म का प्रभाव रखता है. माफिया सरगना मुख्तार मऊ से और उनके रिश्तेदार सिबकतुल्ला अंसारी मुहम्मदाबाद सीट से विधायक हैं. मुख्तार भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या समेत कई संगीन अपराधों में पिछले कई साल से जेल में हैं. विलय के बीच ही मुख्तार को आगरा जेल से लखनऊ जेल शिफ्ट किया गया. जबकि मुख्तार को एक अप्रैल 2016 को ही लखनऊ जेल से आगरा सेंट्रल जेल ट्रांसफर किया गया था.

विलय के बाद अब कौमी एकता दल समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन चुका है. विलय के पहले कौमी एकता दल के अध्यक्ष और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने शिवपाल यादव से मुलाकात की थी और वहीं सारी रणनीति तय हुई थी. शिवपाल ने सार्वजनिक तौर पर कहा भी कि अंसारी की समाजवादी पार्टी में 'घर वापसी' हुई है. शिवपाल बोले कि मुख्तार और अफजाल की वजह से सपा मजबूत होगी. मुख्तार और अफजाल का सपा में स्वागत है. यह चुनावी मौसम का असर है कि अपराधी सरगना और माफिया समाजवादी पार्टी को मजबूती पहुंचाने लगा है. शिवपाल ने 21 जून को बाकायदा मीडिया के समक्ष यह ऐलान किया कि कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हो चुका है. शिवपाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी भी मौजूद थे. विलय के समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जौनपुर गए थे. उनके लौटकर आने से पहले ही विलय हो चुका था. यह सब पहले से तय-नाटक (स्टेज्ड-ड्रामा) था. जब बलराम यादव एमएलसी चुनाव लड़ने के दौरान कौमी एकता दल के दो विधायकों का वोट लेने के लिए सक्रिय थे, उस समय अखिलेश ने क्यों नहीं मना किया था? राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को कौमी एकता दल के दोनों विधायकों ने खुलकर वोट दिया था, उस समय अखिलेश यादव का नैतिक-बल क्यों नहीं ठाठे मार रहा था? यह सवाल सपा कार्यकर्ताओं के ही हैं, जो मुखर तो नहीं हैं लेकिन प्रखर जरूर हैं और चुनाव में अपनी प्रखरता दिखाएंगे. ■

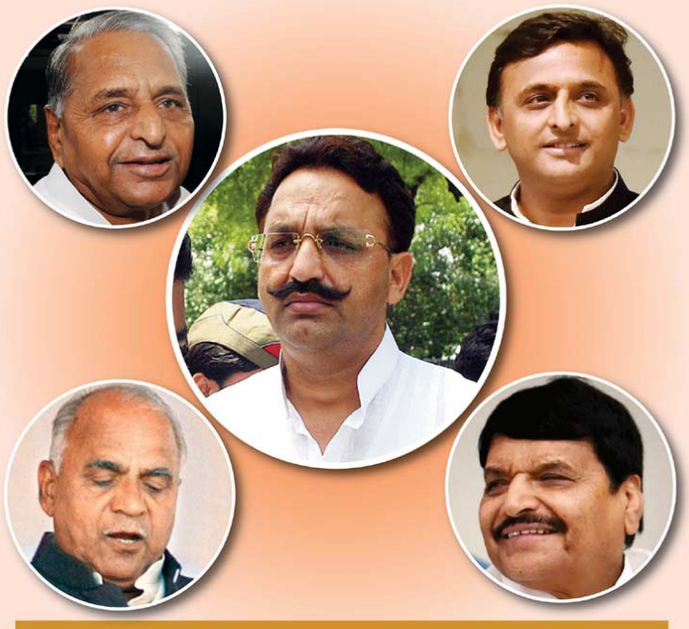

फिर नरम क्यों पड़ गए अखिलेश?

जो मसला नैतिकता से इतना जुड़ा था कि मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य को निष्कासित कर देना पड़ा, उस मसले पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अचानक नरम क्यों पड़ गए? अखिलेश ने खुद ही कहा कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है. जो पार्टी का फैसला होगा वो सभी मानेंगे. समाजवादी पार्टी के संसदीय बोर्ड की 25 जून को बैठक होने वाली है. अखिलेश के ताजा रुख से मुख्तार की पार्टी के विलय को संसदीय बोर्ड से मंजूरी मिल ही जाएगी, अखिलेश की नरमी देख कर यही कयास लगाए जा रहे हैं. इसके साथ ही अखिलेश ने बसपा छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की जमकर तारीफ की और कहा कि मौर्य अच्छे और मजबूत नेता हैं, लेकिन गलत दल में थे. उधर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताते रहे और सपा में शामिल होने की उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते रहे.

बहुजन समाज पार्टी में मची भगदड़, मौर्य के बाद कई और लाइन में

मायावती के खिलाफ मौर्य का शौर्य

एक तरफ समाजवादी पार्टी में माफिया सरगना की पार्टी का विलय हो रहा था तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुजन समाज पार्टी से विरह हो रहा था. मौर्य और मायावती के विरह में भारी तिक्तता थी. मौर्य मायावती के खिलाफ बयानबाजी का शौर्य दिखा रहे थे, तो मायावती भी अपने अंदाज में स्वामी प्रसाद मौर्य के अस्तित्व को खारिज कर रही थीं. समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों तरफ की राजनीतिक रामलीला चरम पर रही.

बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती पर टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाते हुए 22 जून को पार्टी से इस्तीफा दे दिया. मौर्य ने कहा कि मायावती के भीतर पैसे की हवस पैदा हो गई है. विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मौर्य ने मायावती पर करारा प्रहार किया. मौर्य ने कहा कि मनुवादी व्यवस्था में चौथे पायदान पर रहने वाले दलितों के उत्थान के लिए कांशीराम ने बसपा बनाई थी. इस पार्टी ने जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी की मूल भावना से काम करते हुए समाज में एक स्थान बनाया और दलित आंदोलन को गति दी, लेकिन मायावती धन के लालच और मनुवादियों के मोह में फंसकर कांशीराम के सपनों का सौदा कर रही हैं. मौर्य ने कहा, इसलिए मैंने पत्र लिखकर मायावती को अपना इस्तीफा भेज दिया है. मौर्य ने बसपा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और उन्हें दलित महापुरुषों से जुड़े कार्यक्रमों में जाने से रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे विचार रखने से रोका गया. विचारों की आजादी छीनने की कोशिश हुई. ऐसे में पार्टी में घुटन हो रही थी. इस्तीफा देकर अब हल्का महसूस कर रहा हूं. मौर्य ने यह भी कहा कि मैं विधायक रहूंगा या नहीं, यह पड़रौना की जनता को तय करने का हक है. मायावती यह नहीं तय करेंगी. मौर्य ने मायावती पर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का आरोप लगाया और कहा कि मैं दलितों और पिछड़ों के हितों के लिए काम करता रहूंगा. स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि मायावती दलित की नहीं दौलत की बेटी हैं. वे आगामी चुनाव के लिए टिकट बेच रही हैं. यह मान्यवर काशीराम और बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान है. बसपा नीलामी का बाजार बन गई है. मायावती ने अंबेडकर के विचारों की हत्या की है. बसपा के कार्यकर्ता हताश हैं, इस पार्टी में दलितों के लिए जगह नहीं रह गई है. मौर्या ने कहा कि बाबा साहेब के सपनों को मायावती ने बर्बाद कर दिया है. उल्लेखनीय है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पूर्वांचल में बसपा के बड़े नेता के रूप में पहचान रही है. 2009 में पडरौना विधानसभा के लिए हुए एक उपचुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने मौर्य को पार्टी का उम्मीदवार बनाया था. उस चुनाव में मौर्य ने केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह की मां को हराकर सबको चौंका दिया था. इस जीत के साथ मौर्य ने 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के आरपीएन सिंह के हाथों मिली पराजय का बदला भी ले लिया था.

मौर्य के इस्तीफे और आरोप के जवाब में मायावती ने कहा कि हम मौर्य को खुद ही पार्टी से निकालने वाले थे. पार्टी छोड़कर मौर्या ने बहुजन समाज पार्टी पर बड़ा उपकार किया है. मायावती ने कहा कि मौर्या पहले से मुलायम के साथ थे. मौर्य को परिवारवाद का मोह है. मैंने मौर्य के बेटे बेटी को भी टिकट दिया. लोकसभा चुनाव में भी बेटी को टिकट दिया था. लेकिन उनमें परिवारवाद का व्यामोह पार्टी प्राथमिकताओं से अधिक हावी हो गया था. मायावती ने कहा कि मैंने अपने भाई बहन सभी को राजनीति से दूर रखा. परिवारवाद का विरोध हमारी पार्टी के मूल विचार हैं. लेकिन इसके विपरीत मौर्य लगातार अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे. मैं परिवारवाद की सख्त विरोधी हूं. टिकट बेचने के मौर्य के आरोप को मायावती ने पूरी तरह नकार दिया और कहा कि बसपा मुलायम सिंह यादव की पार्टी नहीं है, जहां पहले परिवार को टिकट बांटे जाते हैं, पार्टी के सदस्यों का नम्बर बाद में आता है. पार्टी छोड़कर जाने वाले लोग यही बोलते हैं कि मायावती दलित नहीं दौलत की बेटी है, लेकिन वे सही वजह नहीं बताते हैं. पैसा लेकर टिकट बेचने के आरोपों पर मायावती ने मौर्य से पूछा, 2012 में उन्होंने अपने बेटे-बेटी के टिकट के लिए कितना पैसा दिया था? स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरफ मायावती के आरोपों का जवाब भी देते हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के भी मौर्य जाति का होने के प्रति अपनी चिंता जाहिर कर देते हैं. मौर्य ने कहा कि वह परिवारवाद के सख्त खिलाफ हैं, इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को बच्चा बताना भी नहीं भूलते. ■

बसपा के खिलाफ बिगुल फूंकने का क्रम जारी

बहुजन समाज पार्टी में तकरीबन विद्रोह की ही स्थिति है. केवल स्वामी प्रसाद मौर्य ही क्यों, बसपा छोड़ने का क्रम तो पहले से जारी है. डॉ. अखिलेश दास, जुगल किशोर, फतेह बहादुर सिंह, राजेश त्रिपाठी जैसे कई नाम हैं, जो बसपा के खास थे, लेकिन उन्हें पार्टी छोड़ने पर विवश होना पड़ा. इनमें से करीब-करीब सबों ने मायावती पर यही आरोप लगाया कि वे पैसे लेकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव का टिकट बांटती हैं या भारी धन लेकर किसी को राज्यसभा के लिए मनोनीत करती हैं. सपा की लहर में भी बसपा से चिल्लूपार जैसी सीट जीतने वाले विधायक और पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी को बसपा छोड़नी पड़ी. पता चला कि मायावती राजेश को ही दरकिनार कर हरिशंकर तिवारी के किसी रिश्तेदार को विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में थीं. इसकी भनक लगते ही राजेश ने बसपा से किनारा कर लिया. बसपा के राज्यसभा सदस्य डॉ. अखिलेश दास गुप्ता के इस्तीफे की कहानी से तो लोग परिचित हैं ही. मायावती ने डॉ. अखिलेश दास गुप्ता को राज्यसभा का टिकट दोबारा देने से मना कर दिया था. इस पर डॉ. दास ने यह आरोप लगाया था कि राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने के लिए मायावती सौ-सौ करोड़ रुपये मांगती हैं. इसी तरह राज्यसभा के लिए चयनित नहीं होने का गुस्सा पूर्व सांसद ब्रजेश पाठक में भी है. हालांकि उन्होंने अभी पार्टी नहीं छोड़ी है. लेकिन चर्चा है कि मायावती के सतीश चंद्र मिश्र से एकल-ब्राह्मण प्रेम के कारण ब्राह्मण समुदाय के कई नेता जल्दी ही बसपा को 'नमस्ते सदा वत्सले' कर देंगे. मायावती ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में जिस आईपीएस अफसर को सबसे अधिक तरजीह दी थी, वही बृजलाल रिटायरमेंट के बाद भाजपा में शरीक हो गए. बृजलाल के बारे में सबको यही लग रहा था कि वे बसपा में जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी मायावती को झटका दे दिया. मायावती ने सारे नियम-कानून और सीनियॉरिटी को ताक पर रख कर अक्टूबर 2011 में बृजलाल को प्रदेश का डीजीपी बनाया था. जबकि उस वक्त बृजलाल गाजियाबाद कोर्ट में एक मुकदमा भी झेल रहे थे. 2012 में यूपी के विधान सभा चुनाव होने थे. चुनाव से ठीक पहले बृजलाल को राज्य का पुलिस प्रमुख बनाए जाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी. तब आयोग के आदेश पर बृजलाल को पीएसी के डीजी पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था. बृजलाल को वर्दी वाला बसपाई तक कहा जाने लगा था. बसपाई बृजलाल के भाजपाई होने के बाद बसपा के राज्यसभा सदस्य जुगल किशोर और मायाकालीन मंत्री फतेह बहादुर सिंह के सपरिवार भाजपा में शामिल होने का कदम भी मायावती के लिए बड़ा झटका था. जुगल किशोर और फतेहबहादुर के परिवार के सदस्यों के साथ-साथ खासी संख्या में बसपाइयों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी. उनमें राज्यसभा सांसद जुगल किशोर की पत्नी दमयंती किशोर और उनके पुत्र सौरभ सिंह व फतेह बहादुर सिंह की पत्नी साधना सिंह और उनके समर्थक शामिल थे. फतेह बहादुर सिंह लंबे समय तक प्रदेश की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे थे. उनके पिता वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. कैंपियरगंज इनकी परंपरागत सीट है. इसके अलावा पूर्व विधायक सुरेंद्र मिश्र, विधान परिषद सदस्य हरगोविंद मिश्र, आजमगढ़ के बसपा नेता अमित तिवारी और बॉबी अवस्थी ने भी बसपा छोड़ कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी.

लीचीपुरम से पूर्वी चंपारण को मिली पहचान

लीची में लाचार नहीं...

लीची के मंजर से तैयार शहद सबसे बेहतर और स्वादिष्ट होता है. वर्तमान में केवल पूर्वी चम्पारण में 5 हजार टन शहद का उत्पादन लीची के मंजर से होता है. वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार मधुमक्खियों की कमी के कारण लीची के मंजर का 80 प्रतिशत मधु बर्बाद हो जाता है. अगर मधुमक्खियों की संख्या 10 गुणा बढ़ा दी जाए तो शहद का उत्पादन 50 हजार टन से भी ज्यादा हो सकता है. इतना ही नहीं मधुमक्खियों की संख्या बढ़ने से लीची के मंजर का परागन भी ज्यादा होगा जिससे लीची उत्पादन भी 10 गुणा तक बढ़ सकता है और लीची व्यवसाय का आंकड़ा 500 करोड़ से बढ़ सकता है. 2011 में राज्य सरकार ने लीची के बागों की जुताई एवं रंगाई कराई, इसके बावजूद कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई.

राकेश कुमार

बिहार की शाही लीची का स्वाद जिसने एक बार चखा, वह इसका दीवाना हो गया. देश ही नहीं, विदेशों में भी शाही लीची के चाहने वालों की कमी नहीं. लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार की उदासीनता के कारण विश्व बाजार में शाही लीची अपना स्थान नहीं बना पाई है. अगर सरकार शाही लीची के उत्पादन एवं निर्यात में सहयोग करती, तो आज विश्व बाजार में हमारी तूती बोलती. लीची उत्पादन पर ही हमारा शहद उद्योग भी आधारित है. शाही लीची का उत्पादन बढ़ाकर हम शहद के व्यापार में भी अहम भागीदारी निभा सकते हैं.

2008 तक लीची उत्पादक क्षेत्र के रूप में मुजफ्फरपुर की पहचान पूरे देश में थी. तब राज्य सरकार के लीची उत्पादन मैप पर सूबे के तीन जिले मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं वैशाली ही शामिल थे. सबसे बड़ा लीची उत्पादक जिला होने के बावजूद पूर्वी चम्पारण का नाम इसमें शामिल नहीं था. यह क्षेत्र लीची के उत्पादन और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है. 2004 में पूर्वी चम्पारण के मेहसी निवासी पत्रकार सुदिष्ट नारायण ठाकुर ने तत्कालीन जिलाधिकारी एस शिवकुमार को एक प्रतिवेदन सौंप कर बताया कि यह सूबे का सबसे बड़ा लीची उत्पादक जिला है. इसके बाद जब डीएम शिवकुमार ने बागवानी विभाग से रिपोर्ट मांगी, तो वे आश्चर्यचकित रह गये. रिपोर्ट के अनुसार 2004 में मुजफ्फरपुर में 8.5 हजार हेक्टेयर में लीची की खेती की गई थी जबकि पूर्वी चम्पारण में 11.5 हजार हेक्टेयर में लीची की बागवानी की गई थी. 2008 में तत्कालीन डीएम नर्मदेश्वर लाल ने इस सपने को साकार किया. 4 जून 2008 को लीचीपुरम उत्सव का मंच सजा. इस उत्सव को अपने उद्देश्य में सफलता मिली और उसी वर्ष लीची उत्पादन जिलों में पूर्वी चम्पारण को शामिल कर लिया गया. इसके बाद 2009 में शिवहर, सीतामढ़ी और पश्चिमी चम्पारण जिले को सूची में जगह मिली. इसके बावजूद केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा लीची व लीची उत्पादकों के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

2016 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले के 11.5 हजार हेक्टेयर में लीची की बागवानी की गई. जबकि पूर्वी चम्पारण में 14.5 हजार हेक्टेयर में लीची का उत्पादन हुआ, जिसमें केवल मेहसी प्रखण्ड में ही 11.5 हजार हेक्टेयर में लीची की बागवानी की गई. मेहसी के अतिरिक्त चकिया, कल्याणपुर, केसरिया, मधुबन, तेतरिया, मोतिहारी, पकड़ीदयाल, पताहीं, पीपराकोठी, तुरकौलिया और हरसिद्धि प्रखण्डों में लीची का उत्पादन होता है. वहीं मुजफ्फरपुर के मुशहरी, कुढ़नी, कांटी, गायघाट, बोचहां, मोतीपुर, साहेबगंज और मीनापुर लीची उत्पादक प्रखण्ड हैं. लीचीपुरम उत्सव की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2008 में पूर्वी चम्पारण में 8 करोड़ का लीची व्यापार होता था, जो 2016 में बढ़कर 60 करोड़ पार कर गया है. लेकिन सरकारी उदासीनता, वैज्ञानिक खेती की जानकारी के अभाव एवं संसाधनों की कमी के कारण लीची उत्पादन क्षमता से काफी कम होता है या यूं कहें नाम मात्र होता है.

विश्व बाजार में छाई चीन की लीची

वैज्ञानिकों के अनुसार यहां लीची का फल पेड़ में लगे मंजर का मात्र .01 प्रतिशत ही हो पाता है. जबकि चीन में इसके मंजर से फल बनने का प्रतिशत 7 से 10 है. विश्व में लीची उत्पादन में चीन की भागेदारी मात्र 17 प्रतिशत है, जबकि विश्व बाजार में उसका कब्जा 43 प्रतिशत है. वहीं भारत विश्व उत्पादन में 37.8 की भागेदारी के बावजूद विश्व बाजार में 4.7 प्रतिशत ही कब्जा जमा पाया है. भारत में लीची के अलावा छिलका, बीज आदि का कोई प्रयोग नहीं किया जाता जिससे लीची उत्पादकों को इसका विशेष लाभ नहीं मिल पाता है. वहीं चीन में लीची के छिलका से दवा और उसके अवशिष्ट से सनमाइका एवं अन्य सामानों का उत्पादन होता है. लीची के गूदा से खाद्य उत्पाद बनाये जाते हैं. इसमें भरपूर मात्रा में खनिज, प्रोटीन, विटामिन एवं लवण पाया जाता है. इससे सैकड़ों प्रकार की दवाइयां बनाई जाती है. वहीं लीची के बीज से दवा और टेलकम पावडर का निर्माण होता है जो सर्वाधिक महंगा उत्पाद है. विडंबना है कि सबसे बड़ा लीची उत्पादक देश होते हुए भी लीची के अवशिष्टों से भारत में कोई भी बाई-प्रोडक्ट तैयार करने पर ध्यान नहीं दिया जाता है.

> केन्द्रीय कृषि मंत्री का संसदीय क्षेत्र मोतिहारी होने के बावजूद यह क्षेत्र विश्व बाजार में अपनी पहचान नहीं बना सका है. हालांकि उनके प्रयास से ही क्षेत्र में लीची अनुसंधान केन्द्र का निर्माण हुआ है. देश में जिस प्रकार हर्बल पदार्थों का ट्रेन्ड बढ़ा है, वैसे अगर खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियां यहां आकर शहद और लीची का कारोबार करें तो दस हजार युवकों को साल भर रोजगार मिल सकता है.

प्रथम लीचीपुरम महोत्सव का उद्घाटन करते तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीष कुमार

लीची के मंजर से तैयार शहद सबसे बेहतर और स्वादिष्ट होता है. वर्तमान में केवल पूर्वी चम्पारण में 5 हजार टन शहद का उत्पादन लीची के मंजर से होता है. वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार मधुमक्खियों की कमी के कारण लीची के मंजर का 80 प्रतिशत मधु बर्बाद हो जाता है. अगर मधुमक्खियों की संख्या 10 गुणा बढ़ा दी जाए तो शहद का उत्पादन 50 हजार टन से भी ज्यादा हो सकता है. इतना ही नहीं मधुमक्खियों की संख्या बढ़ने से लीची के मंजर का परागन भी ज्यादा होगा जिससे लीची उत्पादन भी 10 गुणा तक बढ़ सकता है और लीची व्यवसाय का आंकड़ा 500 करोड़ से बढ़ सकता है. 2011 में राज्य सरकार ने लीची के बागों की जुताई एवं रंगाई कराई, इसके बावजूद कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई.

केन्द्रीय कृषि मंत्री का संसदीय क्षेत्र मोतिहारी होने के बावजूद यह क्षेत्र विश्व बाजार में अपनी पहचान नहीं बना सका है. हालांकि उनके प्रयास से ही क्षेत्र में लीची अनुसंधान केन्द्र का निर्माण हुआ है. देश में जिस प्रकार हर्बल पदार्थों का ट्रेन्ड बढ़ा है, वैसे अगर खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियां यहां आकर शहद और लीची का कारोबार करें तो दस हजार युवकों को साल भर रोजगार मिल सकता है.

लीचीपुरम उत्सव को मूर्त रूप देने वाले तत्कालीन जिलाधिकारी नर्मदेश्वर लाल वर्तमान में कृषि विभाग, बिहार सरकार में सचिव हैं. इस संदर्भ में उन्होंने जानकारी दी कि लीची व उसके अन्य उत्पादों के विकास के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

माधुरी दीक्षित को साक्षी रख कर अपने अभियान में जुटा एक नायाब शख्स

पर्यावरण की हिफाजत में लगा माधुरी का दीवाना

पप्पू सरदार पर्यावरण और माधुरी दीक्षित के दीवाने ही नहीं, बल्कि परमार्थ कार्यों के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं. देश के किसी भी कोने में आने वाली प्राकृतिक विपदा में मदद के लिए वे जी-जान से जुट पड़ते हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में उन्होंने गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने में मदद की.

संतोष देव गिरि

झारखंड में बॉलीवुड की धक-धक गर्ल का एक दीवाना माधुरी दीक्षित के नाम पर पर्यावरण संरक्षण और परमार्थ कार्यों में जी-जान से जुटा है. पप्पू सरदार ने इस साल पर्यावरण बचाने और आगामी पीढ़ी के लिए सहेजकर रखने का अभियान चला रखा है. हालांकि उनका पूरा जीवन परमार्थ और पर्यावरण हितों को लेकर समर्पित है. इसके पीछे उनका उद्देश्य है लोगों में पर्यावरण को बचाने का सार्थक संदेश देना और उन्हें इस अभियान से जोड़ना. पप्पू सरदार ने माधुरी दीक्षित के नाम पर पर्यावरण संरक्षण की मुहिम चला रखी है. उनके इस मुहिम में आम लोगों का भी जोरदार समर्थन मिल रहा है.

झारखंड की लौह नगरी जमशेदपुर के निवासी पप्पू सरदार आजीविका के लिए चाट की दुकान चलाते हैं. लेकिन वे अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना नहीं भूलते. उनके इस विचार से प्रभावित होकर लोग शहर को हरा-भरा रखने का संकल्प ले रहे हैं. पप्पू सरदार मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के फैन हैं. वे शहर में कोई भी सेवा कार्य माधुरी दीक्षित के नाम को आगे रखकर करते हैं. बीस वर्षों से माधुरी दीक्षित के नाम पर सेवा कार्य कर रहे पप्पू सरदार की इस प्रतिबद्धता के चर्चे अब शहर में लोगों की जुबान पर हैं. शहरवासी पप्पू के सामाजिक कार्यों पर नाज करते हैं. माधुरी का यह दीवाना मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग व बेसहारा बच्चों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहता है. इनके लिए पप्पू सरदार ने एक खास दिन चुन रखा है, वह दिन है 15 मई. इस दिन माधुरी दीक्षित का जन्मदिन होता है. पप्पू सरदार पिछले दो दशक से माधुरी दीक्षित का जन्मदिन सेवाभाव और परमार्थ कार्यों के लिए समर्पित करते चले आ रहे हैं. इस वर्ष माधुरी के नाम पर उन्होंने जन्म-माह मनाने का संकल्प लिया. इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर अभियान चलाया. 15 मई से 15 जून तक पप्पू सरदार ने शहर में प्रमुख स्थानों पर पौधरोपण का अभियान चलाया. उन्होंने इस अभियान में शहर के लोगों को भी जोड़ने का प्रयास किया. उन्होंने लोगों के बीच हजारों पौधों का वितरण कर उन्हें पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया. वे चाट की दुकान पर आने वाले ग्राहकों को पर्यावरण बचाओ का संदेश देने के साथ ही विभिन्न प्रकार के फल व सुंदरता बिखेरने वाले फूलों के पौधे निःशुल्क बांटते हैं. इतना ही नहीं, पप्पू रमजान के पाक महीने में रोजेदारों को साथ लेकर घर-घर जाकर लोगों के बीच हरियाली फैलाने का संदेश देते हैं. उनका लक्ष्य है कि हरियाली का संदेश हर वर्ग, हर धर्म, हर तबके तक पहुंचे और भविष्य के लिए भी धरती को हरा-भरा बनाकर रखा जा सके.

पप्पू सरदार पर्यावरण और माधुरी दीक्षित के दीवाने ही नहीं, बल्कि परमार्थ कार्यों के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं. देश के किसी भी कोने में आने वाली प्राकृतिक विपदा में मदद के लिए वे जी-जान से जुट पड़ते हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में उन्होंने गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने में मदद की. वे झारखंड में आदिवासियों और गरीबों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं.■

मणिपुर

सत्ता पाने और बचाने के बीच जनता के मुद्दे गायब

एस. बिजेन सिंह

हाल में मणिपुर के दो विधानसभा क्षेत्र इंफाल वेस्ट और इंफाल ईस्ट के म्यूनिस्पल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए. इंफाल म्यूनिस्पल कॉरपोरेशन वेस्ट इंफाल से 20 वार्ड और ईस्ट इंफाल से सात वार्डों का समूह है. 27 सीट के इस चुनाव में सत्ता पक्ष कांग्रेस ने 12 सीटें जीतीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें और पांच निर्दलीय. यह चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच शक्ति परीक्षण जैसा था. इस जीत से कांग्रेस को लगता है कि अब भी आम जनता कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है. कांग्रेस पार्टी, मणिपुर के अध्यक्ष टीएन हाउकिप को विश्वास है कि इस जीत के बाद कांग्रेस पार्टी को 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी लोगों का समर्थन मिलेगा और जीत उन्हीं की होगी. लेकिन हकीकत इससे कहीं कोसों दूर है. कांग्रेस को लेकर आम लोगों में असंतोष है. जनता की सोच है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और कुशासन कांग्रेस की नियति बन गई है. कांग्रेस आम जनता की जान–माल की रक्षा नहीं कर पा रही है. कांग्रेस सरकार पर लगातार प्रदेश में एनकाउंटर कराने के आरोप लगते रहे हैं, जिसे हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है. हर मोर्चे पर कांग्रेस सरकार विफल साबित हो रही है. इनर लाइन परमिट को लेकर एक महीने से ज्यादा समय तक स्कूली बच्चे सड़क पर प्रदर्शन करते रहे. उनपर लाठियां गोलियां और पानी की बौछारें की गईं. कई छात्र घायल हुए फिर भी सरकार चुपचाप तमाशा देखते रही. जब राजनीतिक पार्टियां सामाजिक मुद्दों पर चुप रहेंगी, तब जनता का मुखर होना स्वाभाविक है. वही हाल मणिपुर का है. जिस मुद्दे पर सरकार, पार्टियों और नेताओं को आगे आना था, उसके लिए आम जनता को प्रदर्शन करना पड़ रहा है. सड़क पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं. इन मामलों पर चाहे कोई भी नेता किसी भी पार्टी का क्यों न हो, उनकी ओर से न कोई बयान आया और न ही लोगों के बीच जाकर उन्होंने अपनी बातें रखीं. दूसरा, इरोम शर्मिला 15 साल से भूख हड़ताल पर हैं. कांग्रेस सरकार का कोई नेता या मंत्री आजतक शर्मिला से मिलने नहीं गया.

ये अलग बात है कि कांग्रेस 15 साल से शासन कर रही है, इसलिए उसकी पैठ अब भी प्रदेश के कोने–कोने में है. पार्टी के कार्यकर्ता आम लोगों की बात सुनने तक को तैयार नहीं हैं. मणिपुर में चाहे नेशनल पार्टी हो या स्थानीय पार्टी, सभी यहां की समस्याओं को सुलझाने में विफल रहे हैं. कांग्रेस पार्टी भूमिगत संगठनों से शांति वार्ता कर अपनी वाहवाही लूटने में मगन है, तो वहीं अफस्पा को लेकर सरकार अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है.

मणिपुर की राजनीतिक तस्वीर

पूर्वोत्तर भारत का राज्य मणिपुर एक अशांत प्रदेश है, जिसकी आबादी 22 लाख है. अगले साल 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं. राज्य के कुल 60 विधानसभा सीटों में से 20 विधानसभा सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं. यानी पहाड़ी क्षेत्र के राजनेता ही इन 20 सीटों पर खड़े हो सकते हैं. असम विधानसभा चुनाव होने के बाद राष्ट्रीय पार्टियां अब मणिपुर पर नजर गड़ाए हैं. राज्य में मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार पिछले 15 सालों से है. मणिपुर की मुख्य राजनीतिक पार्टियों में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय जनता दल एवं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हैं. प्रमुख स्थानीय पार्टियों में मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी, लोक जन शक्ति पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, मणिपुर पीपुल्स पार्टी, फेडरल पार्टी ऑफ मणिपुर, नगा पीपुल्स फ्रंट, निखिल मणिपुरी महासभा आदि हैं. मणिपुर में दो लोकसभा सीट हैं. इनर और आउटर. आउटर लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है. इनर लोकसभा के अंदर 32 विधानसभा सीट है और आउटर में 28 विधानसभा सीट.

दूसरी तरफ, भाजपा ने भी लोकसभा चुनाव के पहले अफस्पा को मुद्दा बनाया था, लेकिन केंद्र में सरकार आने के बाद हाथ खड़े कर दिए. एमपीपी (मणिपुर पीपुल्स पार्टी) एक स्थानीय पार्टी है. इस पार्टी से लोगों को बहुत उम्मीदें थीं. लेकिन यह पार्टी भी दूसरी पार्टियों की तरह साबित हुई. मणिपुर की स्थानीय समस्याओं पर अपनी आवाज बुलंद करने के बजाय कार्यकर्ता चुपचाप आंख–कान बंद कर बैठे हैं.

प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अभी से चुनावी रणनीति की तैयारी शुरू कर दी है. सबसे पहले राज्य के अध्यक्ष टीएच चाउबा सिंह को बदला गया. चाउबा सिंह ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोकसभा में सांसद रह चुके हैं. 1999 में वे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कल्चर, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्री थे. चाउबा प्रदेश में एक मजबूत भाजपा नेता हैं, इसके बावजूद उनकी जगह पर आरएसएस कार्यकर्ता केशव भवानंद को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया. चाउबा को राज्य चुनाव प्रबंधन कमेटी का संयोजक बनाया गया है. भवानंद एक दशक पहले 1995 में भाजपा में शामिल हुए थे. पहले वे संघ प्रचारक के तौर पर राज्य में काम कर रहे थे. भवानंद प्रदेश भाजपा में कोषाध्यक्ष, महासचिव और उपाध्यक्ष आदि पद पर कार्य करते रहे हैं.

केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद पूर्वोत्तर खास कर मणिपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है. भाजपा मणिपुर में सोशल मीडिया के जरिए कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है. भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश में जगह–जगह घूमकर पार्टी का प्रचार करते देखे जा रहे हैं, वहीं वे स्थानीय समस्याओं पर भी लोगों की मदद कर रहे हैं. पिछले साल जब प्रदेश में बाढ़ आई थी, तब सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी से अधिक बाढ़ पीड़ित परिवारों की मदद भाजपा कार्यकर्ताओं ने की. असम चुनाव की जीत के बाद भाजपा की उम्मीदें और बढ़ गई हैं.

बहरहाल, राज्य की प्राथमिकता है अशांत राजनीतिक और सामाजिक माहौल को बदलना, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना और बिजली, पानी, सड़क व शिक्षा की समस्या को दूर करना. इस दिशा में कांग्रेस विफल रही है. शेष भारत से जोड़ने वाली सड़क नेशनल हाईवे 53 के बंद होने से मणिपुरियों की रोजी–रोटी छिन जाती है. इस हाईवे की स्थिति दयनीय हो चुकी है. बारिश के मौसम में यहां अक्सर लैंड स्लाइड होता है, जिससे राहगीरों को आने–जाने में बाधा होती है. लूट–खसोट, यात्रियों को जान से मारना, नगा चरमपंथियों की मांगें पूरी नहीं करने पर ड्राइवरों को मारना–पीटना, लोगों को धमकी देना यहां आम बात है. इसे दूर करने के लिए हाईवे फोर्स रखने की जरूरत है. यहां बिजली–पानी की समस्याएं भी गंभीर हैं. प्रदेश में आज भी लोगों के पास पीने का पानी नहीं है. 80 प्रतिशत लोग तालाब का पानी पीने को मजबूर हैं. गांवों में बिजली दो से चार घंटे ही मिल पाती है. शिक्षा के क्षेत्र में भी हाल बेहाल है. अशांत माहौल के चलते प्रदेश में अक्सर बंद की स्थिति रहती है. इस वजह से साल में छह महीने ही स्कूल, कॉलेज खुल पाते हैं. बच्चे शिक्षा से वंचित होने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ रहे हैं. राज्य के अलग–अलग संप्रदाय के लोगों में हमेशा तनाव का माहौल रहता है. पहाड़ बनाम घाटी के मुद्दे पर हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है. इस टकराव को राजनीतिक पार्टियां अपने निहित स्वार्थ के लिए और भी खाद–पानी देती रहती हैं. इसका समाधान तभी संभव है, जब प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक शांति कायम हो. इसके लिए हर राजनीतिक पार्टियों में राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है. अपने हित छोड़कर काम करने पर ही इन समस्याओं का समाधान होगा. राज्य में राजनीतिक टक्कर कांग्रेस और भाजपा में ही है. देखना है कि इस टक्कर में जनता की समस्याओं का कितना समाधान निकल पाता है. ■

sbijensngh@gmail.com

बांग्लादेश के जरिए बंगाल और पूर्वोत्तर पर साधा जा रहा निशाना

बेमानी हिंसा की बेशर्म वजहें

सूफी यायावर

बांग्लादेश के रामकृष्ण मिशन आश्रम मठ को आईएसआईएस की तरफ से मिली धमकी को केंद्र सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है. ढाका स्थित रामकृष्ण मिशन मठ के संन्यासियों की हत्या करने की धमकी भारत में बेलूर मठ स्थित आश्रम के मुख्यालय भेजी गई है. इस वजह से भी इसे अधिक गंभीरता से लिया गया है. भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश सरकार को इस बारे में सतर्क किया है और मठ की सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त करने की ताकीद की है. आईएसआईएस के नाम पर बांग्लादेश में पसरती जा रही हिंसा को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में खास तौर पर सतर्कता बरती जा रही है. केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और सीमा की निगरानी के लिए लगे अर्ध सैनिक बलों और सैन्य इकाइयों को राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय बना कर काम करने को कहा गया है. बांग्लादेश के घटनाक्रम पर सतर्क निगाह रखी जा रही है.

इस्लामिक स्टेट पिछले कुछ समय से लगातार भारत को निशाना बनाने के अपने इरादे जाहिर करता रहा है और इसके लिए तरह–तरह के वीडियो बना कर उसे भी सोशल मीडिया साइटस पर डाल रहा है. पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार इसके प्रति काफी सतर्कता बरत रही है और इसे रोकने के कई कारगर कदम उठाने जा रही है. इसी सिलसिले में कुछ दिनों पहले सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को दिल्ली बुलाकर इस्लामिक स्टेट के खतरे को रोकने की योजना पर विस्तृत चर्चा की गई थी. देश के पूर्वोत्तर राज्यों और खास तौर पर असम में आईएसआईएस से जुड़ा कोई बड़ा मामला तो सामने नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों पहले यह खुलासा हुआ था कि असम में बड़ी संख्या में लोग आईएसआईएस के बारे में इंटरनेट से जानकारी जुटा रहे हैं. असम के पुलिस महानिदेशक ने यह आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था और केंद्र सरकार को इसका पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराया था. असम में आईएसआईएस के बारे में इंटरनेट पर जानकारियां खोजने के मामले जम्मू कश्मीर से भी अधिक पाए गए. असम में हालिया विधानसभा चुनाव के बाद बदली राजनीतिक स्थितियों में इस तरह की गतिविधियां थमी हैं.

बांग्लादेश और मालदीव में आईएसआईएस के नाम पर बढ़ती साम्प्रदायिक कट्टरता से भारत की चिंता बढ़ी है. बांग्लादेश और मालदीव में हुए कई हमले यही बता रहे हैं. बांग्लादेश में सख्त सुरक्षा वाले राजनयिक इलाके में इतालवी राहत कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, या प्रगतिशील लेखकों का गला घोंट दिया जाता है, या हिंदू पुजारियों की सरेआम हत्या कर दी जाती है और उसकी जिम्मेदारी फौरन आईएसआईएस के तथाकथित गुर्गे ले लेते हैं, यह आम होता जा रहा है. हाल यह है कि पश्चिमी देशों के कई दूतावासों ने बांग्लादेश और मालदीव में अपने राजनयिकों की गतिविधियां कम कर दी हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) भी कह चुकी है कि आईएसआईएस आने वाले समय में भारत विरोधी आतंकी समूहों से रिश्ते बढ़ा कर हमलों को अंजाम दे सकता है.

अभी कुछ ही अर्से में बांग्लादेश में धड़ाधड़ कई हत्याएं हुईं, जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया. बांग्लादेश के उत्तरी पंचागढ़ स्थित हिंदू मंदिर में घुसकर 50 साल के पुजारी जनेश्वर राय की हत्या कर दी गई. इस पर प्रसिद्ध लेखिका तसलीमा नसरीन ने लिखा कि कट्टर इस्लामिस्ट बांग्लादेश में हिंदुओं को रहने नहीं देंगे. सुन्नी बहुल बांग्लादेश में हाल के महीनों में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर सुनियोजित हमलों में दो विदेशियों सहित दर्जनों लोगों की मौत हुई है. मरने वाले विदेशियों में इतालवी नागरिक सीजर तावेला और जापानी नागरिक कुनीयो होशी शामिल हैं. इन सभी हत्याओं की आईएसआईएस ने जिम्मेदारी ली. बांग्लादेश के राजशाही यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर रेजौल करीम सिद्दीकी की सरेआम गला रेत कर की गई. इस हत्या ने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया. आईएस ने इसकी भी जिम्मेदारी ली और बड़ी बेशर्मी से कहा कि प्रो. सिद्दीकी नास्तिकता के समर्थक थे, इसलिए उनकी हत्या की गई. इसी दरम्यान पश्चिमी बांग्लादेश के कुश्तिया में डॉक्टर सनाउर रहमान की हत्या कर दी गई. इस तरह बांग्लादेश में इस्लामी चरमपंथियों द्वारा धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यकों की लगातार हत्याएं की जा रही हैं. कई प्रसिद्ध लेखकों की बांग्लादेश में हुई हत्याएं दुनियाभर के अखबारों में सुर्खियों में रही हैं. 60 साल के संन्यासी नित्यरंजन पांडेय की हत्या भी इसी की कड़ी है. पांडेय पिछले 40 साल से अनुकूलचंद्र सत्संग परमतीर्थ केमायतपुरधाम आश्रम में स्वयंसेवी के तौर पर काम कर रहे थे. हमलावरों ने उनका गला काट डाला. आश्रम एक प्रसिद्ध हिन्दू संत के नाम पर है और वहां पूरे बांग्लादेश और भारत के श्रद्धालु भी आते हैं. पांडेय की हत्या से कुछ ही दिनों पहले एक हिन्दू पुजारी, एक ईसाई और एक आतंकवाद निरोधक पुलिस अधिकारी की पत्नी की हत्या कर दी गई थी. यह खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश का आतंकी संगठन जमीयतुल मुजाहिदीन आईएसआईएस के नाम पर हिंसा फैला रहा है. हिंदुओं, ईसाइयों समेत अल्पसंख्यकों और धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं पर हुए ज्यादातर हमलों में इसी संगठन का हाथ है. बांग्लादेश के हालात पर न केवल भारत बल्कि अमेरिका भी चिंता जाहिर कर चुका है. ■

बंगाल और पूर्वोत्तर में जहर फैलाने की कोशिश में अल कायदा

कुछ अर्सा पहले अल कायदा के मुखिया अयमान अल जवाहिरी ने भारत के खिलाफ बड़ी साजिश के संकेत दिए थे. इसके कुछ दिन बाद ही पश्चिम बंगाल में खुफिया एजेंसियों को मिले कुछ पैंफलेट इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अल कायदा ने भारत में पैर पसारने की पुरजोर कोशिश शुरू भी कर दी है. इसके लिए अल कायदा बांग्लादेश को जरिया बना रहा है.

अल कायदा बांग्लादेश में खलीफाशाही स्थापित करने के नाम पर मुस्लिमों को भड़का रहा है. इसके पीछे इरादा है बांग्लादेश को सीरिया और इराक की तरह तबाह करना ताकि उसके बाद भारत में जेहाद की जंग आसान हो जाए. भारत के खिलाफ अल कायदा का बड़ा गेम प्लान पश्चिम बंगाल और असम में खुला, जिसने खुफिया एजेंसियों को सतर्क किया. खुफिया एजेंसियों के हाथ पश्चिम बंगाल और असम में बांटे जा रहे सात पन्नों का ऐसा पर्चा मिला जिसमें अल कायदा की साजिश का जिक्र है. अल कायदा आईएसआईएस की तर्ज पर बांग्लादेश में खलीफाशाही की स्थापना करना चाहता है और वहां की सरकार को हटाकर शरिया का कानून थोपना चाहता है. इन सात पन्नों में लिखा है कि अगर हम बांग्लादेश में सीरिया जैसे हालात पैदा करने में कामयाब हो गए तो असम, आराकान (म्यांमार) और पश्चिम बंगाल के मुसलमान भी यहां हिजरत करने आ सकेंगे, इसके साथ–साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी विद्रोह की स्थिति पैदा कर सकेंगे. खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि पश्चिम बंगाल और असम में अलकायदा के मीडिया विंग की तरफ से जारी हुए पर्चों को बांटने में जमात का ही हाथ है. जमात इन पर्चों को बांग्लादेश से लाकर पूर्वोत्तर राज्यों में बांट रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

हास्यास्पद दावे करना बंद कीजिए

सुब्रमण्यम स्वामी ने यह निशानदेही कर देश की बड़ी सेवा की है कि दो लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन वे इतने बुद्धिमान नहीं हैं. बुद्धिमान होने के लिए आपको देश की वास्तविकताओं से अवगत होना पड़ेगा. आरबीआई के गवर्नर हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जो गरिमापूर्ण, ज्ञानी और अच्छे व्यक्तित्व वाले थे. रघुराम राजन ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हैं. मैं वैसे लोगों में से हूं जो समझते हैं कि किसी संस्था में कोई व्यक्ति आता है और चला जाता है लेकिन संस्थाएं स्थायी रहती हैं. यह भारत पर पूरी तरह से लागू होता है. हम वैसे बनाना रिपब्लिक नहीं हैं, जहां एक बदलाव से सारी चीज़ें बदल जाती हैं. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आज़ादी से पहले की संस्था है. अगर मैं गलत नहीं हूं तो रमन आरबीआई के 23 वें गवर्नर हैं. उनके बाद दूसरा गवर्नर बहाल होगा, यह किसी सार्वजनिक बहस का मुद्दा नहीं है. यह एक प्रशासनिक फैसला है जिसे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को लेना है. मुझे विश्वास है कि वे इस पद के लिए किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढ लेंगे, जो ज़रूरत के मुताबिक फैसला लेने में सक्षम हो.

मौजूदा केंद्र सरकार के दो साल बीत चुके हैं. व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार को जो करना चाहिए, उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया है. लेकिन, समस्या ये है कि कुछ मंत्री जिस तरह के दावे कर रहे हैं, वे गलत हैं और कुछ हद तक हास्यास्पद भी. पीयूष गोयल कहते आ रहे हैं कि उन सात हजार गांवों का विद्युतीकरण किया गया है, जहां आजादी के 67 साल के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी. वे कहना ये चाहते हैं कि छह लाख गांवों में से कुल 18 हजार गांव अभी तक बिना बिजली के थे. इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक कुल गांवों में से सिर्फ 3.3 प्रतिशत गांवों में बिजली नहीं थी. इसमें से करीब 7 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई गई. यानी, पिछले दो साल में ये सरकार सिर्फ 1.3 प्रतिशत गांवों तक ही बिजली पहुंचा सकी है. लेकिन ये कहना गलत है कि आज से पहले काम ही नहीं हुआ था और आज हम पिछले दो साल से सब काम कर रहे हैं. सच ये है कि इस सरकार के सत्ता में आने से पहले ही करीब 97 फीसदी गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है. चलिए, इससे भी कोई नुकसान नहीं है. इससे बड़ी समस्या ये है कि हमें कोई यह नहीं बता रहा है कि जितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ है, उनमें से कितने गांवों में बिजली मिल रही है. किन घरों को बिजली मिल रही है? शायद कुछ सरकारी भवनों में, कुछ अधिकारियों के घरों में. क्या गरीबों के घरों में भी बिजली पहुंच रही है? इन तथ्यों को लेकर अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है.

इसी तरह, जनधन योजना की बात करें तो करोड़ों की संख्या में बैंक खाते खुले. इनमें से कितने खातों में पैसा है? सरकार अपनी सुविधा से विश्व बैंक की इस रिपोर्ट को छुपा लेती है, जिसके मुताबिक करीब 43 फीसदी बैंक खाते निष्क्रिय हैं, उनमें पैसा ही नहीं है. यहां कोई गांव में जाता है, हस्ताक्षर करा लेता है और बैंक खाते खुल जाते हैं. जिसका बैंक खाता खुलता है, वह उसका कभी इस्तेमाल तक नहीं कर पा रहा है. आखिर ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, ये तो सरकार को ही निर्णय लेना है. लेकिन मैं मानता हूं कि जो भी कार्यक्रम चलाया जाए वो लक्षित और केंद्रित (फोकस्ड) हो. उसका कोई नतीजा निकलना चाहिए. सरकार की एक और योजना है शौचालय बनाने को लेकर. स्वच्छ भारत का स्वागत किया जाना चाहिए. लेकिन देश में करीब 15 लाख स्कूल हैं, जहां कम से कम तीस लाख शौचालय होने चाहिए. जिस बिंदु पर मैं यहां बात करना चाहता हूं वह यह है कि आपकी उपलब्धियां अच्छी हैं. लेकिन उन्हें उनके वास्तविक अनुपात में रखना चाहिए. आप यह दावा नहीं कर सकते हैं कि 67 साल से कुछ काम नहीं हुआ और दो साल में आपने सब कुछ ठीक कर दिया. एक सफेद झूठ होने के अलावा इसमें कोई सच्चाई नहीं है. इससे कोई प्रभावित नहीं होगा, यहां तक की गांव में रहने वाले लोग भी नहीं. स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने एक और पोर्टल बनाया है. देश के 25 करोड़ छात्रों में से एक लाख छह हज़ार का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उनमें से बीस हज़ार ने आवेदन दिया है. ऐसा क्यों हुआ? लिहाज़ा ये सारे बड़े-बड़े दावे केवल दावे ही हैं. सच्चाई यह है कि भारत एक सतत प्रगति की ओर अग्रसर इकाई की तरह है. चाहे वह विदेश नीति हो या प्रधानमंत्री का दौरा. कुछ लोग प्रधानमंत्री के विदेश दौरों की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन में ऐसे विचारों से सहमत नहीं हूं. वे अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं. लेकिन संघ के लोग कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया. दरअसल हम उन्हीं नीतियों को अपना रहे हैं जिन्हें जवाहरलाल नेहरू ने निर्धारित किया था. और ऐसा करना ठीक भी है. बेशक 1991 के बाद उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, जिसमें सोवियत ब्लॉक उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया था और हर किसी का झुकाव अमेरिका की तरफ हो गया. लेकिन जिस तरह यह सरकार काम कर रही है, उससे बहुत सावधान रहना चाहिए. आप अमेरीकन ब्लॉक में आंख मूंद कर नहीं जा सकते हैं, वरना भारत को दूसरा पाकिस्तान बनने में अधिक समय नहीं लगेगा.

हास्यास्पद बात यह है कि भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए जिन मुद्दों का विरोध किया, उसे अब सत्ता में आने के बाद लागू करना चाहती है और अब कांग्रेस ही उसका विरोध कर रही है. दोनों एक दूसरे को या खुद को कोई श्रेय नहीं देना चाहते. जब कांग्रेस रिटेल में एफडीआई लाना चाहती थी तो भाजपा उसका विरोध कर रही थी और अब भाजपा एफडीआई की बात कर रही है तो कांग्रेस विरोध में है. मनरेगा को लेकर भी यही सब हुआ.

सुब्रमण्यम स्वामी ने यह निशानदेही कर देश की बड़ी सेवा की है कि दो लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन वे इतने बुद्धिमान नहीं हैं. बुद्धिमान होने के लिए आपको देश की वास्तविकताओं से अवगत होना पड़ेगा. आरबीआई के गवर्नर हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जो गरिमापूर्ण, ज्ञानी और अच्छे व्यक्तित्व वाले थे. रघुराम राजन ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हैं. मैं वैसे लोगों में से हूं जो समझते हैं कि किसी संस्था में कोई व्यक्ति आता है और चला जाता है लेकिन संस्थाएं स्थायी रहती हैं. यह भारत पर पूरी तरह से लागू होता है. हम वैसे बनाना रिपब्लिक नहीं हैं, जहां एक बदलाव से सारी चीज़ें बदल जाती हैं. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आज़ादी से पहले की संस्था है. अगर मैं गलत नहीं हूं तो रमन आरबीआई के 23 वें गवर्नर हैं. उनके बाद दूसरा गवर्नर बहाल होगा, यह किसी सार्वजनिक बहस का मुद्दा नहीं है. यह एक प्रशासनिक फैसला है जिसे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को लेना है. मुझे विश्वास है कि वे इस पद के लिए किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढ लेंगे, जो ज़रूरत के मुताबिक फैसला लेने में सक्षम हो. मिसाल के तौर पर व्यापार जगत रघुराम राजन से नाराज था क्योंकि उन्होंने ब्याज दर में कटौती नहीं की. लेकिन यह कोई मापदंड नहीं होना चाहिए क्योंकि केवल ब्याज दर में कटौती मात्र से समस्या का समाधान नहीं हो सकता. दरअसल सरकार की आर्थिक नीति इस सिलसिले में कारगर साबित हो सकती है. सरकार की समग्र नीति क्या है, हमें मालूम नहीं है.

1991 के बाद जो धारणा बनी, वह यह थी कि आप आर्थिक क़ानूनों को गैर-आपराधिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं. फेरा को फेमा से बदल दिया गया, लाइसेंस परमिट राज का खात्मा कर दिया गया, आयकर दर घटा दिया गया. धारणा यह थी कि व्यापार में आसानी के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है. पिछले दो साल से हम क्या देख रहे हैं? हर एक क़ानून में गिरफ्तारी का प्रावधान रखा जा रहा है, हर क़ानून में अपराध की धारा जोड़ी जा रही है. मैं इसके खिलाफ नहीं हूं क्योंकि यह समाजवादी विचार से मेल खाता है. लेकिन आप दोनों हाथ में लड्डू नहीं रख सकते. आप अपना मन बना लीजिए कि आप विदेशी निवेश चाहते हैं. विदेशी निवेशक सबसे पहले यह देखते हैं कि आपका बुनियादी ढांचा कैसा है? बुनियादी ढांचे से यहां आशय क़ानूनी ढांचे से है. क्या उनके साथ मुनासिब व्यवहार होगा. अगर आपके सांसद को अपनी गर्दन बचाने के लिए भागकर लंदन जाना पड़ रहा है तो विदेशी यहां व्यापार करने क्यों आएंगे? उनके पास भारत के नजदीक फिलीपींस जैसे बहुत सारे विकल्प हैं. लिहाज़ा मैं समझता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है. मुझे नहीं मालूम कि इसमें रघुराम राजन की क्या भूमिका हो सकती थी. प्रधानमंत्री केपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विचारशील और बुद्धिमान हैं और जो यह पता लगा सकते हैं कि व्यापार के वातावरण को कैसे सुधारा जा सकता है. सुब्रमण्यम स्वामी उनमें से एक हैं. उनके विचार बहुत अलग होते हैं, जिनसे मैं सहमत नहीं हो सकता, जैसे वे चाहते हैं कि आयकर समाप्त कर दिया जाए. फिलहाल उन्होंने अरविंद सुब्रमण्यन पर हमला बोला है. मैं इनको नहीं जानता हूं. मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि उचित तरीके से इस पूरे हालात का जायजा लें. आप बिजनेस करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप विदेशी निवेश चाहते हैं या नहीं चाहते हैं. आप अपना मन बनाइए.

हास्यास्पद बात यह है कि भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए जिन मुद्दों का विरोध किया, उसे अब सत्ता में आने के बाद लागू करना चाहती है और अब कांग्रेस ही उसका विरोध कर रही है. दोनों एक दूसरे को या खुद को कोई श्रेय नहीं देना चाहते. जब कांग्रेस रिटेल में एफडीआई लाना चाहती थी तो भाजपा उसका विरोध कर रही थी और अब भाजपा एफडीआई की बात कर रही है तो कांग्रेस विरोध में है. मनरेगा को लेकर भी यही सब हुआ. भाजपा मनरेगा को कांग्रेस की असफलता का स्मारक बताती थी, इसे भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली योजना बताती थी, लेकिन अब भाजपा के पास मनरेगा को प्रोत्साहन देने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि यही एकमात्र योजना है जो गरीबों को सीधे राहत पहुंचाने का काम कर रही है, गरीबों से जुड़ी हुई है. मैं समझता हूं कि इस पर गहन सोच-विचार की जरूरत है. सरकार रोज-रोज कुछ न कुछ ऐसे निर्णय ले रही है जिससे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है. इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला है.■

feedback@chauthiduniya.com

ईयू से अलग हुआ ब्रिटेन
कैमरन का इस्तीफा

चौथी दुनिया ब्यूरो

यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के मुद्दे पर जनमत संग्रह का फैसला आने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है. कैमरन ब्रिटेन के ईयू में बने रहने के पक्षधर थे. उन्होंने पिछले साल आम चुनाव में भारी जीत के बाद जनमत संग्रह कराने पर हामी भरी थी. 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर नम आंखों से भर्राई आवाज में उन्होंने घोषणा की, मैं अक्टूबर तक इस्तीफा दे दूंगा. मुझे नहीं लगता कि देश जिस अगले पड़ाव पर जा रहा है, उसकी कमान अब मुझे संभालनी चाहिए. कंजर्वेटिव पार्टी को नया नेता चुन लेना चाहिए.

कैमरन ने कहा कि जहां तक उनकी समझ रही, उन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया. ब्रिटेन यूरोपीय संघ में शामिल नहीं होने के बाद भी आगे बढ़ने का माद्दा रखता है. हमें ब्रिटिश जनमत संग्रह का सम्मान करना चाहिए. उनके इस्तीफा देने की घोषणा के बाद ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कहा कि निजी तौर पर वे डेविड कैमरन के लिए बेहद आहत महसूस कर रहे हैं.

ब्रिटेन के ईयू से बाहर होने का फैसला आने के बाद से ही कैमरन पर पद छोड़ने को लेकर काफी दबाव था. ईयू से अलग होने को लेकर अभियान चलाने वाले नाइजल फरागे ने कहा कि 23 जून 2016 को ब्रिटेन के इतिहास में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना चाहिए. ये बड़े-बड़े बैंकों और औद्योगिक घरानों के खिलाफ आम लोगों की जीत है. अब ब्रिटेन में ब्रेग्जिट सरकार को आना चाहिए. इससे पूर्व अभियान के दौरान उन्होंने कहा था कि ईयू हर रोज मर रहा है. ब्रिटेन की सरकार को बदलने की जरूरत है. गौरतलब है कि जनमत संग्रह में 52 प्रतिशत लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में मुहर लगाई थी, जबकि 48 प्रतिशत यूरोपीय संघ के साथ बने रहना चाहते थे. इंग्लैंड और वेल्स के लोगों ने ईयू से बाहर निकलने के पक्ष में वोट डाला, जबकि नॉर्दर्न आयरलैंड व स्कॉटलैंड ने ईयू में बने रहने के पक्ष में वोट दिया. कह सकते हैं कि इन परिणामों को लेकर पूरा ब्रिटेन दो हिस्सों में बंट गया था.

हालांकि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के फैसले से यूरोपीय संघ के अन्य देश हतप्रभ हैं. यह यूरोपीय संघ के लिए एक भयंकर सपने के सच होने जैसा है. अभी तक किसी भी सदस्य देश ने संघ से अलग होने का फैसला नहीं किया था. हालांकि यूरोपीय युनियन ट्रीटी में आर्टिकल 50 में ऐसा प्रावधान है कि जो देश युनियन से अलग होना चाहता है, वह इस संगठन से बाहर जा सकता है. लेकिन इससे पूर्व संघ छोड़ने वाले देश को इसकी वजह बतानी होती है, जिसपर अन्य सदस्य देश विचार करते हैं. इसके साथ ही भविष्य में उस देश के साथ संबंधों को भी तय किया जाता है. इसका फैसला परिषद को करना होता है, जिसमें अन्य सदस्य देशों की मंजूरी लेनी होती है. इस बैठक में वह देश हिस्सा नहीं लेता है, जिसने संघ छोड़ने का फैसला किया हो. हालांकि डिपार्चर ट्रीटी पर ईयू के अन्य बचे 27 देशों का दस्तखत होने तक ब्रिटेन यूरोपीय संघ का सदस्य बना रहेगा.

उम्मीद है कि यूरोपीय संघ के प्रमुख डोनाल्ड टस्क अगले सप्ताह एक सम्मलेन की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें वे ईयू गवर्निंग बॉडी के प्रतिनिधि के तौर पर ब्रिटेन के अलग होने के मुद्दे पर आधिकारिक बयान जारी करेंगे. ईयू का वार्षिक बजट 145 बिलियन यूरो का है, जिसमें ब्रिटेन का योगदान 7 बिलियन यूरो का है. अब ईयू की चिंता इस बजट की कमी को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने की भी होगी.

जनमत संग्रह का फैसला आने के बाद से ही विश्व बाजार में पाउंड लड़खड़ा गया है. फैसला आने के पूर्व पाउंड 1.51 डॉलर पर चल रहा था, जो नतीजे की घोषणा के बाद 1.41 डॉलर तक आ गया. ब्रिटिश कारोबारियों का कहना है कि 2008 के बाद पहली बार उन्होंने पाउंड को इस स्तर पर नीचे गिरता देखा है. इसका असर ईयू के अलावा ब्रिटेन के अन्य सहयोगी देशों पर भी पड़ना तय है.

भारत का ब्रिटेन के साथ ईयू के साथ भी व्यापारिक संबंध रहा है, जो आने वाले दिनों में प्रभावित हो सकता है. भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली और आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन लगातार इस ऐतिहासिक घटनाक्रम पर नजर रखे हैं. अरुण जेटली ने कहा कि ब्रिटेन, यूरोप और दुनिया के बाकी अन्य देशों पर इस घटनाक्रम का क्या असर होगा, अभी कहना मुश्किल है. सभी देशों को इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा. वहीं रघुराम राजन ने कहा कि आरबीआई हर तरह की आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है. जरूरत पड़ने पर हम मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करेंगे.

हालांकि ईयू से ब्रिटेन के अलग होने के फैसले के बाद दुनिया भर के बाजारों में गिरावट का रुख दिख रहा है. कुछ आर्थिक विश्लेषक आशंका जता रहे हैं कि ईयू से अलग होने पर ब्रिटेन आर्थिक रूप से एक कमजोर देश साबित होगा, जिससे उसका विश्व राजनीति और व्यापार पर दबदबा भी कम हो जाएगा. वहीं कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि अभी कुछ और देश ईयू से अलग होने की घोषणा कर सकते हैं. ये देश ईयू से अलग होने के बाद ब्रिटेन की परिस्थितियों की समीक्षा कर रहे हैं. नीदरलैंड में भी जनमत संग्रह कराने की मांग उठने लगी है. हालांकि ईयू के अध्यक्ष टस्क ने कहा कि यूरोपीय युनियन के बाकी सभी 27 देश एकजुट हैं. वे अलग नहीं होंगे. अब देखना है कि ईयू से ब्रिटेन जैसे मजबूत देश के अलग होने के बाद ईयू कमजोर होता है या अन्य देशों को एकजुट रख पाने में सफल रहता है. कैमरन की विदाई से ज्यादा महत्वपूर्ण ब्रिटिश नागरिकों के हित हैं, जिसपर जनता ने मुहर लगाई है. फिलहाल ब्रिटेन के सामने महत्वपूर्ण चुनौती है कि वह ईयू से अलग होने के बाद भी विश्व बाजार पर अपना दबदबा बनाए रखे.■

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

चौंकाने वाला होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव

उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव सर पर हैं. संभवत:, दिसंबर में चुनाव होने की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश में अनुमान के विपरीत राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं. किसी को अंदाजा नहीं था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में इस तरह की हलचल होगी, जो लोगों को चौंका देगी.

समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता पार्टी की स्थिति को लेकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह से मिलकर उन्हें समझा रहे थे कि पार्टी को गतिमान और चलायमान करने की जरूरत है. मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल को उत्तर प्रदेश चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी. उन्हें चुनाव के बारे में कोई भी फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया. शिवपाल यादव को मिली इस नई जिम्मेदारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह की एक लहर फूंकी. शिवपाल सिंह यादव ने सबसे पहले बेनीप्रसाद वर्मा को कांग्रेस से तोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल किया और उन्हें राज्यसभा भेजा. उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुर्मी समाज को ये संदेश दिया कि उनके सबसे बड़े नेता को समाजवादी पार्टी में पुन: शामिल करने से कुर्मी समाज बेहिचक समाजवादी पार्टी में अपनी हिस्सेदारी तलाश सकता है. शिवपाल यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती से टक्कर लेने के लिए अजीत सिंह से हाथ मिलाना चाहते थे लेकिन शायद अजीत सिंह की जल्दबाजी या शायद उनके फैसले लेने में गलत आकलन की वजह से बातचीत टूट गई. अब भी अजीत सिंह समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं, इसकी संभावना अखबारों के जरिए बार-बार राजनीतिक पटल पर दी जा रही है. शिवपाल यादव मायावती का मुकाबला करने के लिए शायद नीतीश कुमार से भी संपर्क कर सकते हैं, जिनके पीछे उत्तर प्रदेश का संपूर्ण कुर्मी समाज जाता हुआ दिख रहा है.

बहुजन समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य का अचानक इस्तीफा सामने आया. मौर्य बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं, इसकी कल्पना दूर-दूर तक किसी को नहीं थी. वे मायावती के विश्वासपात्र लोगों में भी माने जाते थे. लेकिन, स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा और उनका इस आरोप को दोहराना कि मायावती पैसे लेकर टिकट देती हैं, ये बताता है कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को ये एहसास हो गया था कि आने वाले कुछ महीनों में, चुनाव से पहले, उन्हें पार्टी से निकाला जा सकता है. दरअसल, बहुजन समाज पार्टी के भीतर षड्यंत्रों का सिलसिला लगातार चलता रहता है और कौन बसपा अध्यक्ष मायावती के करीब है, इसकी लड़ाई छद्म तरीके से चलती रहती है. स्वामी प्रसाद मौर्य के बसपा से बाहर आने का सबसे बड़ा फायदा नसीमुद्दीन सिद्दीकी को होने वाला है. मायावती इस बार को आसानी से झेल लेंगी, ऐसा नहीं लगता. वे पूरी कोशिश करेंगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी तरह से विजयी होकर उत्तर प्रदेश विधान सभा में न पहुंच पाएं.

समाजवादी पार्टी में ये अफवाह बहुत ज्यादा फैली है कि पार्टी को लेकर मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव की एक राय है और अखिलेश यादव व रामगोपाल यादव की राय दूसरी है. अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव पर ज्यादा विश्वास करते हैं और मुलायम सिंह पार्टी के मसलों पर शिवपाल सिंह यादव पर ज्यादा भरोसा करते हैं. इस द्वंद्व में अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक यादव और उनकी पत्नी भी हैं, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे ऐन मौके पर समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ लाकर न खड़ा कर दें. इन दिनों उनके गहरे रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के साथ बन रहे हैं. हो सकता है कि सच्चाई ऐसी न हो और रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, प्रतीक यादव और खुद मुलायम सिंह यादव के बीच में कहीं, कोई मतभेद न हो. पर समाजवादी पार्टी के सूत्र जिन घटनाओं का जिक्र करते हैं, उनसे ये लगता है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है. शिवपाल यादव को उत्तर प्रदेश चुनाव में पार्टी की कमान सौंपने का फैसला शायद न तो अखिलेश यादव को समझ में आया और न ही रामगोपाल यादव को. मुलायम सिंह यादव के पास जब रामगोपाल यादव जाते हैं तो अपने जैसा फैसला करा लेते हैं, जिसका उदाहरण बिहार में चुनाव से पहले विपक्षी दलों की एकता का खात्मा माना जाता है. सभी लोगों ने जिनमें लालू यादव, नीतीश कुमार, देवगौड़ा, ओमप्रकाश चौटाला, कमल मोरारका जैसे नेता शामिल थे सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम सिंह यादव को अपना अध्यक्ष मान लिया था. उनके चुनाव चिन्ह को अपना चुनाव

बहुजन समाज पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी अध्यक्ष मायावती के ऊपर निर्भर है. मायावती पिछले चार साल से शांत बैठी हुई हैं. वे राजनीति में हैं सिर्फ इसके लिए उन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. उन्होंने बहुत होशियारी के साथ चार साल खामोशी में काट दिए और इस चार साल की खामोशी का फायदा उन्हें अगले चुनाव में मिलता दिख रहा है.

चिन्ह मान लिया था और पार्टी का नाम भी समाजवादी जनता दल रखना लगभग तय कर लिया था. सार्वजनिक रूप से माला पहनाते हुए नीतीश कुमार, लालू यादव, देवगौड़ा और ओमप्रकाश चौटाला सहित कमल मोरारका इस राय से सहमत थे कि अब विपक्ष की एक पार्टी बननी चाहिए, जो पूरे देश के लोगों की भावनाओं को सामने रखकर नया राजनीतिक अभियान छेड़े, पर ऐसा नहीं हुआ.

अब कुछ फैसले शिवपाल यादव लेते हैं, तो अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव उन्हें मुलायम सिंह से वापस करा देते हैं और कुछ फैसले चुनाव से जुड़े हुए जो शिवपाल यादव लेते हैं उन्हें भी अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव अपने पक्ष में नहीं मानते हैं. हो सकता है कि थोड़े दिनों में समाजवादी पार्टी की कमान राष्ट्रपति जैसी व्यवस्था के तहत सीधे मुलायम सिंह यादव के हाथों में चली जाए. मुलायम सिंह यादव पार्टी कार्यकर्ताओं के प्यारे हैं, लेकिन चुनाव का मुकाबला करने की स्थिति में दस साल पुरानी ऊर्जा वे स्वयं में कैसे पैदा करेंगे यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है.

बहुजन समाज पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी अध्यक्ष मायावती के ऊपर निर्भर है. मायावती पिछले चार साल से शांत बैठी हुई हैं. वे राजनीति में हैं सिर्फ इसके लिए उन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. उन्होंने बहुत होशियारी के साथ चार साल खामोशी में काट दिए और इस चार साल की खामोशी का फायदा उन्हें अगले चुनाव में मिलता दिख रहा है.

आगामी चुनाव बुनियादी तौर पर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच होने वाला है. देखना सिर्फ यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी कमजोरियों को ताक पर रखकर क्या इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बनाम बहुजन समाज पार्टी बना सकती है या भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी बना सकती है या नहीं. अगर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को सीधी टक्कर में नहीं बदल पाती तो उसके दूसरे या तीसरे नंबर के संघर्ष में पड़ने की संभावना बढ़ जाती है. कांग्रेस अभी बीच में खड़ी है, नीतीश कुमार शुरुआत कर रहे हैं. चुनावी दौड़ में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे से आगे-पीछे चल रही है, पर जिस तरह की तोड़-फोड़ शुरू हुई है उससे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश का यह चुनाव पिछले साठ सालों में सर्वाधिक आश्चर्यचकित करने वाला चुनाव होगा. इस चुनाव के मुख्य खिलाड़ी नंबर एक शिवपाल यादव, नंबर दो राजनाथ सिंह, नंबर तीन मायावती और नंबर चार कांग्रेस का कोई भी नेता होगा. नीतीश कुमार को अभी तय करना है कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी का चेहरा कौन होगा, उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी की कमान कौन संभालेगा और वे किस वर्ग को अपने साथ लेकर अपने को प्रासंगिक साबित करेंगे.■

editor@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा के आसार

मेघनाद देसाई

2016 में हुए चुनाव के नतीजों को अभी पूरी तरह से समझा भी नहीं गया था कि अगले साल के चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है. यह चुनाव किसी छोटे राज्य में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जहां 403 विधानसभा और 80 लोकसभा सीटें हैं. बिहार के साथ यह राज्य देश की राजनीति पर हावी होने की क्षमता रखता है. दरअसल कांग्रेस ने इन दो राज्यों पर क़ब्ज़ा कर पूरे देश पर लंबे समय तक शासन किया है.

लेकिन कांग्रेस ने सियासी चाल के तहत देश के दो सबसे बड़े राज्यों को पिछड़ा बनाए रखा. यदि जातिवाद बिहार व उत्तर प्रदेश में राजनीति का अहम हिस्सा है तो इसकी वजह यह है कि ये राज्य पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की गतिशीलता को नहीं पा सके हैं. जब कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों को सत्ता सौंपी तो अन्य पार्टियों ने भी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को और मजबूती देने का ही काम किया. बिहार इन मायनों में सौभाग्यशाली है कि उसे दस साल का एनडीए का कार्यकाल मिला. अब बिहार भी पुराने जातिवादी राजनीति शैली में चला गया है. जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो बारी-बारी से सत्ता संभालने वाली भाजपा, सपा और बसपा यहां के किसी समस्या का समाधान करने में विफल रही है. अब चार बीमारू राज्यों पर गौर करें तो केवल उत्तर प्रदेश में ही विकास कार्य नहीं हुए हैं.

चाहे मुजफ्फरनगर हो, दादरी या फिर आजमगढ़, उत्तर प्रदेश आज भी ऐसा राज्य है, जहां किसी भी मुद्दे पर साम्प्रदायिक हिंसा भड़क उठती है. बेहतर ज़िन्दगी की तलाश में हजारों लोगों ने यहां से पलायन किया है. अपराध के मामले में भी यहां भयावह स्थिति है. दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार यदि प्रति व्यक्ति आय के मामले में राष्ट्रीय औसत को पा लें तो भारत दुनिया में आय के मामले में कई पायदान ऊपर चला जाएगा.

आगामी चुनाव भाजपा के लिए बहुत उम्मीदों भरे नहीं हैं. भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने को विजेता के रूप में प्रोजेक्ट कर पा रही है क्योंकि उसने 2014 के आम चुनाव में राज्य के 80 लोक सभा सीटों में से 71 पर अपना क़ब्ज़ा जमा लिया था. लेकिन आम मतदाता राज्य के चुनाव में अलग तरीकों से सोचता और वोट देता है और लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर. हाल में बिहार और दिल्ली के चुनावों ने भी इसे साबित किया है. अन्य पार्टियों की तरह भाजपा भी यहां जाति और बिरादरी का गठजोड़ बिठाकर जीतने का फॉर्मूला तलाश रही है. कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश में आमूल-चूल बदलाव की बात नहीं कर रही है. कोई भी दल यहां सामाजिक संरचना को आधुनिकता की तरफ ले जाने और यहां की आय को राष्ट्रीय औसत तक ले जाने की बात नहीं कर रहा है. सभी दल अपने निजी स्वार्थ की इच्छापूर्ति के लिए सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं.

चूंकि इस चुनाव में किसी नए विचार या किसी नई नीति की घोषणा नहीं होगी (और यदि होती भी है तो उसे लागू नहीं किया जाएगा), कोई भी अनमने ढंग से ही जीतने वाले की निशानदेही करेगा. इस राज्य में सपा, बसपा और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा. कांग्रेस सत्ता पाने की कोशिश में जुटी है, पर नाकाम रहेगी. उसी तरह जदयू भी उत्तरप्रदेश में अपना दायरा नहीं बढ़ा पाएगी.

चूंकि इन दलों की बुनियादी सोच में कोई खास वैचारिक अंतर नहीं है, इसलिए यहां व्यक्तिवाद और जातिवाद का बोलबाला रहना तय है. अगर इस चुनाव के संदर्भ में कोई भविष्यवाणी करनी हो तो यह कहा जा सकता है कि यहां किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा. लेकिन सरकार बनाने के लिए तीन मुख्य दावेदारों में से किसी दो को मिलकर गठबंधन बनाना ही एकमात्र विकल्प होगा. पिछले कुछ चुनावों से सपा और बसपा बारी-बारी से सत्ता में रही है. भाजपा इन चुनावों में अहम दावेदारी पेश करने की उम्मीद कर रही है. यह तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है. अब दांव इस पर लगना तय है कि सपा और बसपा में से कौन भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएगा.

यह बहुत दुखद स्थिति है. इस चुनावी प्रकिया से अधिक उम्मीद नहीं रखी जा सकती है. दरअसल भारतीय राजनीति ने उत्तर प्रदेश को हमेशा पीछे धकेला है. यह राज्य लंबे समय तक अलग-अलग पार्टियों के कुशासन का शिकार रहा है. दूसरी बात यह कि यह एक बहुत बड़ा राज्य है. इसे दो हिस्सों में बांट देना चाहिए, जैसा कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी 1955 की रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की थी. यहां उत्तराखंड को छोड़कर किसी भी क्षेत्र को अलग पहचान देने की कोशिश नहीं की गई. हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल, छत्तीसगढ़ की तरह बेहतर विकास कर सकते हैं.

लेकिन उन 80 लोकसभा सीटों के आकर्षण की वजह से यूपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है. इतने बड़े इनाम को कोई भी राजनीतिक दल महज सुशासन के लिए कैसे छोड़ सकता है?■

आगामी चुनाव भाजपा के लिए बहुत उम्मीदों भरे नहीं हैं. भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने को विजेता के रूप में प्रोजेक्ट कर पा रही है क्योंकि उसने 2014 के आम चुनाव में राज्य के 80 लोक सभा सीटों में से 71 पर अपना क़ब्ज़ा जमा लिया था. लेकिन आम मतदाता राज्य के चुनाव में अलग तरीकों से सोचता और वोट देता है और लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर. हाल में बिहार और दिल्ली के चुनावों ने भी इसे साबित किया है. अन्य पार्टियों की तरह भाजपा भी यहां जाति और बिरादरी का गठजोड़ बिठाकर जीतने का फॉर्मूला तलाश रही है. कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश में आमूल-चूल बदलाव की बात नहीं कर रही है. कोई भी दल यहां सामाजिक संरचना को आधुनिकता की तरफ ले जाने और यहां की आय को राष्ट्रीय औसत तक ले जाने की बात नहीं कर रहा है. सभी दल अपने निजी स्वार्थ की इच्छापूर्ति के लिए सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही

अज्ञात बीमारी से मर रहे नौनिहाल

स्वास्थ्य समिति के कार्यकारी निदेशक जितेंद्र श्रीवास्तव यह कहकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं कि मृत बच्चों के मामले की जांच चल रही है. उनका कहना है कि उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की जांच से पता चला है कि अधिकतर पूराने मामले हैं और अज्ञात बीमारी से मरने वाले बच्चों की संख्या कम है. बावजूद इसके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती इस बारे में कुछ जनाकारी देना संभव नहीं है. सवाल ये है कि जब स्वास्थ्य विभाग को इस बारे में जानकारी थी कि अज्ञात बीमारी की वजह से बच्चों की मौत हो रही है, तो इस मामले की जांच क्यों नहीं की गई? अज्ञात बीमारी की चपेट में आए महादलित बस्ती कुबौल को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध कराई गईं?

राजेश सिन्हा

स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लाख दावे कर लिए जाएं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है. कहने के लिए जिला मुख्यालय से लेकर गांवों तक अस्पतालों का जाल बिछा दिया गया है. इन अस्पतालों में कहीं डॉक्टर हैं तो दवा नहीं, दवा है तो डॉक्टर नहीं. और कहीं दवा और डॉक्टर दोनों हैं, लेकिन ये डॉक्टर न मानवता और न ही अपने चिकित्सकीय धर्म का पालन करते हैं. महादलित, अशिक्षित समाज के साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थापित किए गए अस्पतालों की हालत खराब है. जिला मुख्यालय से दूर गावों में स्थापित अस्पतालों का ताला कब खुलता है और कब बंद होता है, शायद इसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों को भी नहीं होगी. दरभंगा जिले का महादलित गांव कुबौल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रहा है. इस गांव में अज़ात बीमारी की वजह से कई दर्जन बच्चों की मौत हो चुकी है और इन बच्चों की माताएं सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं. राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यकारी निदेशक

जो बच्चियां अपने पैरों पर ठीक से खड़ी नहीं हो सकतीं और न अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोच सकती हैं, उनकी कच्ची उम्र में ही शादी कर दी जाती है. अधितकतर बच्चियां शादी के बाद गर्भवती हो जाती हैं और प्रसव के दौरान उनकी और उनके बच्चे की मौत हो जाती है. अशिक्षा और गरीबी से लाचार महादलित परिवार अपनी बेटियों की महज 13 से 14 वर्ष की उम्र में ही शादी करने के लिए मजबूर हैं. समाजसेवी नंदकिशोर पाडेय का कहना है कि कुबौल गांव में प्रसव के दौरान कब किसकी मौत हो जाए, यह कहना कठिन है.

जितेंद्र श्रीवास्तव यह कहकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं कि मृत बच्चों के मामले की जांच चल रही है. उनका कहना है कि उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की जांच से पता चला है कि अधिकतर पूराने मामले हैं और अज़ात बीमारी से मरने वाले बच्चों की संख्या कम है. बावजूद इसके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती इस बारे में कुछ जनाकारी देना संभव नहीं है. सवाल ये है कि जब स्वास्थ्य विभाग को इस बारे में जानकारी थी कि अज़ात बीमारी की वजह से बच्चों की मौत हो रही है, तो इस मामले की जांच क्यों नहीं की गई? अज़ात बीमारी की चपेट में आए महादलित बस्ती कुबौल को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध कराई गईं?

इस बस्ती की फुलिया देवी, तारा देवी, यशोदा देवी, गुलबिया देवी, घुथरी देवी, जिंबो देवी और तुला देवी समेत अनेक महिलाएं चीख-चीख कर कह रही हैं कि बच्चों की मौत हो रही और स्वास्थ्य विभाग और सरकार सो रही है. इस गांव की लगभग 80 महिलाओं की गोंद सुनी हो चुकी है. अगर प्रसव के दौरान 17 बच्चों की मौत को दरकिनार कर दिया जाए, तो 24 बच्चों की मौत की वजह अज़ात बीमारी और 32 बच्चों की मौत की वजह काला ज्वर बताया जा रहा है. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रारंभिक तौर पर तेज बुखार की वजह से 15, निमोनिया से छह, चिकन पॉक्स से पांच, बॉडी इरैगुलैरिटी से 15

एवं तीन बच्चों की मौत सांप के काटने की वजह से हुई है. इस बस्ती के बच्चों में कुपोषण का पाया जाना आम बात है. बच्चों के जरूरत से अधिक बड़े सिर कुपोषण का प्रमाण है. ग्रामीण चिकित्सकों द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चों में काला ज्वर और निमानिया का भी प्रकोप है. बीमारी की वजह इस बस्ती में गंदगी भी है, क्योंकि इस बस्ती में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है. इस बस्ती में रह रहे लोगों का गरीबी की वजह से अपना और अपने बच्चों का भूख मिटाना भी मुश्किल हो गया है. सरकारी अनाज उनके भोजन का मुख्य साधन है. कुबौल गांव के नजदीक न ही कोई स्वास्थ्य केंद्र है और न ही आंगनबाड़ी केंद्र. यहां के लोगों को इलाज के लिए पांच किलोमीटर दूर स्थिति स्वास्थ्य केंद्र पर जाना पड़ता है और वहां पहुंचने पर अधिकतर समय स्वास्थ्य केंद्र में ताला बंद मिलता है. इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह निजी अस्पताल में इलाज करा सकें. अगर परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है, तो उसे वह पैसा न होने की वजह से अस्पताल नहीं ले जाते. अस्पताल उस स्थिति में ले जाते हैं जब तबीयत अधिक खराब हो जाती है. महादलितों की स्थिति क्या है इसकी जानकारी के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की टीम ने एक सर्वे किया. टीम की सदस्य अतिशि मिश्रा का कहना था कि कुबौल गांव के सर्वे के दौरान यह तथ्य सामने आया कि गांव की कुल 130 महिलाओं में से 80 महिलाओं के बच्चों की किसी न किसी वजह से मौत हो चुकी है. स्थानीय स्वयंसेवी संस्था मिथिला ग्राम विकास परिषद के सचिव नारायणजी चौधरी द्वारा 2015 में उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर अतिशि मिश्रा का यह भी कहना था कि सर्वे की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद कुछ और रहस्यों से पर्दा उठेगा. अगर महादलितों की स्थिति ऐसी ही बनी रही, तो उनकी बच्चों की मौत का न केवल अंतहीन सिलसिला जारी रहेगा, बल्कि नीतीश सरकार का दामन भी दागदार होगा.

बाल विवाह के लिए भी चर्चित है कुबौल: दर्जनों महादलित बच्चों की मौत की गवाही दे रहे दरभंगा जिले का कुबौल गांव भले ही स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से अभी सुर्खियों में आया हो, लेकिन कुबौल बाल विवाह को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है. जो बच्चियां अपने पैरों पर ठीक से खड़ी नहीं हो सकतीं और न अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोच सकती हैं, उनकी कच्ची उम्र में ही शादी कर दी जाती है. अधितकतर बच्चियां शादी के बाद गर्भवती हो जाती हैं और प्रसव के दौरान उनकी और उनके बच्चे की मौत हो जाती है. अशिक्षा और गरीबी से लाचार महादलित परिवार अपनी बेटियों की महज 13 से 14 वर्ष की उम्र में ही शादी करने के लिए मजबूर हैं. समाजसेवी नंदकिशोर पांडेय का कहना है कि कुबौल गांव में प्रसव के दौरान कब किसकी मौत हो जाए, यह कहना कठिन है. प्रसव के दौरान जच्चे-बच्चे की मौत का मामला अक्सर सामने आता रहा है. लेकिन इस समय बच्चों की मौत की वजह चिंता का विषय है. उनका कहना है कि इस अशिक्षित समाज में जागरूकता फैला कर ही बाल विवाह और विभिन्न वजहों से हो रही बच्चों की मौत को रोका जा सकता है. विकलांगता भी इस गांव के लिए अभिशाप बन चुका है. इस महादलित बस्ती में किशोरावस्था आते-आते कई बच्चे विकलांग भी हो जाते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

Mob. : 9386745004, 9204791696 www.iiher.org, Email : anilsulabh6@gmail.com

INDIAN INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION & RESEARCH

Health Institute Rd, Beur (Near Central Jail), Patna -2.

(Recongnised by Govt. of Bihar, RCI, Govt. of India, IAP & ISPO)

AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

POST GRADUATE COURSES :

Name of Courses		Eligibility	Duration
MPT	Master of Physiotherapy	BPT	2yrs.
MOT	Master of Occupational Therapy	BOT	2yrs.
DEGREE COURSES			
BPT	Bachelor of Physiotherapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BOT	Bachelor of Occupational Therapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BPO	Bachelor of Prosthetic & Orthotic	I.Sc	4yrs.+6 Months of Internship
BASLP	Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology	I.Sc	3yrs.+1 year of Internship
BMLT	Bachelor of Medical Laboratory Technology	I.Sc	3yr.+6 Months of Internship
BMRIT	Bachelor of Radio Imaging Technology	I.Sc	3yrs.+6 Months of Internship
B.Ophth.	Bachelor of Ophthalmology	I.Sc	4yr.+6 Months of Internship
B.Ed.	(Special Education)	Graduate	1yr.
1 YEAR ABRIDGED DEGREE FOR DPT / DOT			
DIPLOMA COURSES :			
DPT	Diploma In Physiotherapy	I.Sc (Bio)	3yrs.+6 Month of Internship
D-X-Ray	Diploma In X-Ray Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DMLT	Diploma In Medical Laboratory Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DECG	Diploma In E.C.G.	I.Sc (Bio)	2yr.
DOTA	Diploma In O.T. Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DHM	Diploma In Hospital Management	Graduate	1yr.
CMD	Certificate in Medical Derssing	Matirc with Science & English	1yr.

ADMISSION OPEN

Form & Prospectus - Can be obtained from the office against a payment of Rs. 500/-. only by cash. Send a DD of Rs. 550/- only in the favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna, for postal delivery.

डॉ. अनिल सुलभ
निदेशक प्रमुख

बिहार में औद्योगिक विकास पर ग्रहण

दो दशक से उत्तर बिहार की औद्योगिक विकास की गति मंद पड़ने लगी है. राजनीतिक दलों द्वारा की गई घोषणाएं महज एक चुनावी जुमला बनकर रह गई हैं. दशकों से स्थापित औद्योगिक इकाईयां बंद होती जा रही हैं या बंद होने के कगार पर हैं. नई इकाईयों की स्थापना सत्ता संग्राम और राजनीति की वजह से नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से बेरोजगारी और अपराध बढ़ता जा रहा है. राजनीतिक दल के नेता जनता से किए गए अपने वादों को भूल गए हैं. वर्तमान समय में विकास का मतलब केवल वैसी योजनाओं पर काम होना है जिसमें कमीशनखोरी और लूट की गुंजाइश हो....

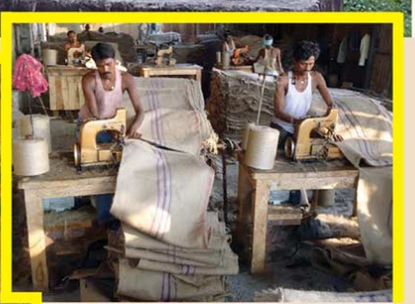

विकास / अमृता

बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है, जिसके दामन में एक ओर गौरवपूर्ण अतीत तो दूसरी ओर बाढ़, सुखाड़, नक्सलवाद और अपराध जैसे कई धब्बे भी हैं. बिहार को राजनीतिक स्तर पर देश में अपनी पहचान कायम करने वाले कई नेताओं की कर्मस्थली होने का भी गौरव भी प्राप्त है. लेकिन बिहार की जो वर्तमान स्थिति है वो उसके गौरवपूर्ण अतीत पर एक धब्बे की तरह है. झारखंड बंटवारे के बाद से बिहार में शुरू सत्ता संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है. चुनावों में पूर्ण बहुमत अब कोई मायने नहीं रखता है. वजह यह है कि बिहार में गठबंधन की सरकारें किसी प्रकार से अपने कार्यकाल को पूरा कर ले रही हैं. अगर विकास की बात करें, तो वह केवल चुनावी भाषण भर बन कर रह गया है. सरकार बनते ही केंद्र व राज्य सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है. प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है. किसानों की समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है. अपराध पर काबू पाना सरकार के लिए चुनौती साबित हो रही है. इसके बावजूद सरकार द्वारा ऑल इज वेल का रट लगाया जा रहा है. अब एक नजर बिहार की औद्योगिक इकाईयों की स्थिति पर डालते हैं.

भारत और नेपाल के सीमावर्ती जिले सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, पुर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर व समस्तीपुर और अन्य जिलों में औद्योगिक विकास नेताओं का नारा और जनता का एक सपना बन कर रह गया है. नए औद्योगिक इकाईयों की स्थापना तो दूर पुराने को बचाने की दिशा में भी कारगर पहल शून्य साबित हो रही है. सीतामढ़ी जिले में वर्तमान में एकमात्र औद्योगिक इकाई रीगा चीनी मिल मौजूद है, जबकि दशकों पूर्व बिहार राज्य वस्त्र निगम द्वारा जूट फैक्ट्री की स्थापना को लेकर औद्योगिक क्षेत्र में भवन निर्माण तक की कवायद की गई, लेकिन किन्हीं वजहों से उक्त योजनाएं धरी की धरी रह गईं और सरकारी कोष से लाखों रुपये खर्च कर भवन निर्माण करा कर छोड़ दिया गया.

जानकारों का कहना है कि कर्मियों की बहाली तक कर ली गई थी, जिन्हें उक्त फैक्ट्री न खुलने की वजह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया. शहर के गोपाल चौक स्थित पेपर मिल की स्थापना को लेकर कवायद की गई, लेकिन यह भी योजना किन्हीं कारणों से कागजों तक सिमट कर रह गई.

सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन परिसर में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव ने स्लीपर कोच फैक्ट्री का शिलान्यास किया था, लेकिन राजनीतिक उथल-पुथल की वजह से यह योजना भी धरी की धरी रह गई. अगर हम देखें, तो रीगा चीनी मिल को छोड़कर कोई दूसरी औद्योगिक इकाई की स्थापना अब तक नहीं की जा सकी है.

पूर्व मंत्री रघुनाथ झा की पहल पर सीतामढ़ी से शिवहर को अलग कर स्वतंत्र जिले का दर्जा दे दिया गया, लेकिन अब तक शिवहर जिले में एक भी औद्योगिक इकाई की स्थापना नहीं हुई है. सीतामढ़ी जिला जहां दशकों तक बागमती व अघवारा समेत कई नदियों की बाढ़ से आने वाली तबाही को झेलता रहा है, तो वहीं शिवहर जिले में बागमती नदी दशकों तक तबाही मचाती रही है. नतीजतन तिरहुत प्रमंडल के इन दोनों ही जिलों में किसानों की स्थिति अब भी दयनीय बनी हुई है. रोजगार का कोई साधन न होने की वजह से लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है. आर्थिक परिशानियों से तंग आकर युवा अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे सरकार और सरकारी तंत्र अंजान बना हुआ है. तिरहुत प्रमंडल के ही मुजफ्फरपुर जिले में केंद्र सरकार की भारत बैगन रेल इकाई और कांटी थर्मल पावर मौजूद है, तो वहीं मोतीपुर में एक चीनी मिल भी है. दरभंगा प्रमंडल के दरभंगा, मधुबनी व समस्तीपुर जिले का हाल भी औद्योगिक विकास की लिहाज से अच्छा नहीं है. मधुबनी व दरभंगा जिले में औद्योगिक इकाईयों की दरकार है. वहीं समस्तीपुर जिले में स्थापित इकाईयों पर ग्रहण लगा हुआ है. समस्तीपुर में दशकों पूर्व दो चीनी मिल की स्थापना की गई थी. एक समस्तीपुर शहर, तो दूसरा हसनपुर में. समस्तीपुर की चीनी मिल लगभग दो दशक पहले से बंद पड़ी है, जबकि हसनपुर की चीनी मिल अभी चल रही है. वहीं समस्तीपुर शहर के समीप जितवारपुर की अशोक पेपर मिल भी किन्हीं कारणों से दशकों पहले बंद कर दी गई, जिसका अब अस्तित्व भी समाप्त हो चुका है. अब केवल औद्योगिक इकाई रामेश्वर जूट मिल मुक्तापुर कैसे भी चल रही है जिसमें बताया जाता है कि लगभग साढ़े चार हजार श्रमिक काम करते हैं. इस जिले में केंद्र सरकार की एक इकाई रेल कारखाना भी मौजूद है, जबकि अन्य औद्योगिक इकाईयां जिले में बंद हो चुकी हैं या बंद होने की कगार पर हैं. पूर्वी चंपारण जिले की मोतिहारी व सुगौली चीनी मिले वर्षों से बंद पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से नजदीकी जिले के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

कुल मिलाकर अब बिहार में औद्योगिक इकाईयों के विकास और विस्तार की जरूरत है. अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में न केवल संबंधित क्षेत्र के लोगों की आर्थिक तंगी पर रोक लगेगी, बल्कि अपराध और बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी. इसलिए सभी राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति और जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर आगे आना होगा. जब तक औद्योगिक विकास में क्रांति नहीं लाई जाएगी, तब तक विकास के दावे का कोई मतलब नहीं है. केवल सड़क, नाला, पुल व पुलिया के निर्माण से बिहार के विकास का पैमाना तय नहीं किया जा सकता. इसलिए केंद्र और राज्य की सरकार को राजनीति को भुलाकर औद्योगिक विकास पर लगे ग्रहण को दूर करना होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

बरौनी रिफाइनरी राजनीति का शिकार

सुरेश चौहान

मोदी सरकार दो साल पूरे होने पर पूरे देश में 'विकास पर्व' मना रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास कहीं दिख नहीं रहा है. बिहार का गौरव देश का दूसरा तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी विकास को तरस रहा है. यह कारखाना विकास की बात तो दूर, अपने मानक से भी पिछड़ रहा है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान की सारी घोषणाएं हवा-हवाई साबित हो रही हैं. प्रधान ने जितनी भी घोषणाएं की थीं, उसमें से एक भी पूरी नहीं हुई. धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की थी कि बरौनी रिफाइनरी की शोधन क्षमता का विस्तार किया जाएगा. युवाओं को आत्मनिर्भर एवं कुशल बनाने के लिए कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी, जहां पर विभिन्न ट्रेड की जानकारी दी जाएगी एवं उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके साथ ही महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा. उन्होंने एक अतिमहत्वपूर्ण घोषणा की थी कि बरौनी रिफाइनरी पर आधारित यहां पेट्रोकेमिकल उद्योग कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी. साथ ही प्रधान ने यह भी कहा था कि बरौनी रिफाईनरी की शोधन क्षमता 6 मिलियन टन से बढ़ाकर 9 मिलियन टन की जाएगी. केंद्र में भाजपा की सरकार बनते ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बरौनी रिफाइनरी का दौरा किया था. बरौनी रिफाइनरी कारखाने का निरीक्षण करने के बाद आयोजित एक समारोह में धर्मेंद्र प्रधान ने ये सारी घोषणाएं की थीं. तालियों की गड़गड़ाहट के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी घोषणा की थी कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही यहां आकर इन उपक्रमों का शिलान्यास करेंगे. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने की बात तो दूर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा की गई एक भी घोषणाएं मोदी सरकार के दो साल बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हुईं. क्या धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये सारी घोषणाएं की थीं और बिहार चुनाव में करारी हार के बाद की गई सारी घोषणाएं मोदी सरकार भूल गई?

पेट्रोलियम मंत्री की उक्त घोषणाओं से न सिर्फ बेगूसराय बल्कि बिहार वासियों में विकास की आशा का संचार हुआ था कि बरौनी रिफाइनरी के साथ-साथ उनके भी अच्छे दिन आएंगे. लेकिन पेट्रोलियम मंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं को मोदी सरकार के द्वारा भूल जाने के बाद बिहार की जनता में घोर निराशा है. लोकसभा चुनाव में मिले अपार समर्थन से उत्साहित धर्मेंद्र प्रधान ने उपरोक्त घोषणाएं की थी. इन घोषणाओं के पीछे राजनीतिक उद्देश्य था कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को लोकसभा चुनाव जैसी ही सफलता मिलेगी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई. बेगूसराय जिले की विधानसभा की सभी सातों सीट पर भाजपा की करारी हार हुई. इस चुनाव परिणाम का खामियाजा बरौनी रिफाइनरी को भुगतना पड़ रहा है. धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया एक भी वादा पूरा नहीं हुआ. गौरतलब है कि जिस समय धर्मेंद्र प्रधान बरौनी रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने की बात करे रहे थे, उस समय बरौनी रिफाइनरी अपनी निर्धारित क्षमता 6 मिलियन टन से अधिक 6.75 मिलियन टन उत्पादन कर रही थी.

रिफाइनरी के इंजीनियरों का कहना है कि बरौनी रिफाइनरी के पास जो उपलब्ध संसाधन है उसी का थोड़ा सा विस्तार कर दिया जाए, तो घोषित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है. बरौनी रिफाइनरी असम के बाद देश की दूसरी रिफाइनरी है. बरौनी रिफाइनरी के बाद भारत में जितनी भी रिफाइनरीज स्थापित हुईं, सभी की शोधन क्षमता का दो से तीन गुना विस्तार हुआ.

रिफाइनरी के इंजीनियरों का कहना है कि बरौनी रिफाइनरी के पास जो उपलब्ध संसाधन है उसी का थोड़ा सा विस्तार कर दिया जाए, तो घोषित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है. बरौनी रिफाइनरी असम के बाद देश की दूसरी रिफाइनरी है. बरौनी रिफाइनरी के बाद भारत में जितनी भी रिफाइनरीज स्थापित हुईं, सभी की शोधन क्षमता का दो से तीन गुना विस्तार हुआ. एक रिफाइनरी की घोषित क्षमता का विस्तार तो उसके उद्घाटन होने से पहले ही कर दिया गया, क्योंकि वह पेट्रोलियम मंत्री के क्षेत्र की रिफाइनरी है. बरौनी रिफाइनरी के बाद स्थापित सभी रिफाइनरीज में पेट्रोकेमिकल उद्योग कम्प्लेक्स की स्थापना हुई, लेकिन बरौनी रिफाइनरी राजनीतिक द्वेष का खामियाजा भुगत रही है. जिस समय केंद्र में मोदी सरकार आई उसके पहले वित्तीय वर्ष में (डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में) बरौनी रिफाइनरी को 474 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था, जबकि वित्तीय वर्ष 2015-16 में बरौनी रिफाइनरी को 150 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. वित्तीय वर्ष 2015-16 में बरौनी रिफाइनरी का शानदार रिकॉर्ड रहा है. उसने अनेक क्षेत्रों में पारितोषिक प्राप्त किया है. लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद बरौनी रिफाइनरी को वर्ष 2015-16 में 150 करोड़ रुपये का घाटा हुआ. राजनीति एवं क्षेत्रवाद की दोहरी पाट के बीच पीसती बरौनी रिफाइनरी के अच्छे दिन कब आएंगे? क्या अगामी लोकसभा चुनाव के समय फिर एक बार बरौनी रिफाइनरी चुनावी मुद्दा बनेगी? यह आने वाला समय ही बताएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

मसूढ़ा शोथ (जिंजीवाइटिस) से बचें
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

Dr.Yasir Habib
दन्त रोग चिकित्सक

डॉ यासिर हबीब पटना के राजा बाजार के डेन्टल जोन से मसूढ़ा शोथ अर्थात जेंजीवाइटिस के बारे में बात करते हुए लोगों को इससे बचने की सलाह दी। डॉ हबीब ने बताया कि जिंजीवाइटिस एक संक्रमण है जो मसूढ़ों की बीमारी का प्रारंभिक लक्षण है।

उन्होंने बताया कि जब दांतों और मसूढ़ों के बीच प्लाक जम जाती है तब यह पैदा होता है। प्लाक एक ऐसी परत है जो भोजन, कीटाणु और बलगम से दांतो पर चिपक जाती है। कालान्तर में ये जमा व मसूढ़ों में संक्रमण पैदा कर सकता है। कई बार जिंजीवाइटिस की वजह से मसूढ़ों में दर्द नहीं होती है पर इसका इलाज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिंजीवाइटिस सामान्यतः उनलोगों को अधिक होता है जो अक्सर ब्रश या दांतों की सफाई (फ्लॉस) नहीं करते। यदि इसका इलाज नहीं किया जाता है तो यह संक्रमण फिर से हो जाता है और इसके कारण मसूढ़ों का गंभीर रोग पैदा हो सकता है या दाँत गिर सकते हैं।

लक्षण- 1) लाल और सूजे हुए मसूढ़े 2) जब आप ब्रश या फ्लांस करते हैं तो मसूढ़ों से आसानी से खून निकल जाता है 3) ऐसे मसूढ़े जो छूने पर दर्द करते है। 4) मसूढ़ो का सिकुड़ना। 5) मुंह में से आने वाली बदबू। देखभाल - यदि आपको रोज सुबह ब्रश करते वक्त आपके मसूढ़ों से खून आने की शिकायत है तो आपको 1) सही तरीके से ब्रश करना ब्रश करते वक्त मसूढ़ों पर ज्यादा कस कर या दवाब न डालें आपका ब्रश नाजुक होना चाहिए जिससे मसूढ़ों कटे छिले नहीं ।ब्रश को मुंह के अंदर 45 डिग्री के एंगल में घुमाकर ब्रशिंग करें जिससे मसूढ़ों पर ज्यादा दबाव न पड़े। 2) मसूढ़े की मसाज करें -मसाज करने से खून का दौरान बढ़ जाता है जिससे मसूढ़े स्वस्थ रहते हैं। 3)दंत चिकित्सक से मिलिए वह प्लांक निकाल देंगे और आप हर छह महीने में अवश्य सम्पर्क करें। 4) माउथवास जरूरी है क्योंकि फ्लांस करने के बाद आपको माउथवॉश से रोजाना अपने मुंह को साफ रखना पड़ेगा। यह एक प्रकार का एंटीसेप्टिक होता है जो मुंह में पनप रहे बैक्टीरिया का नाश करके मुंह में से आने वाली बदबू का सफाया करेगा। 5)चीनी का सेवन कम करें-आप जो चीनी खाते हैं वह मुंह में जाकर बैक्टीरिया के साथ मिल कर दांतों की सड़न पैदा करती है। इससे मसूढ़ों से खून आने लगता है। आपके दांत आपके जीवन भर साथ रहे इसके लिए आवश्यक है नशे से जूड़ी आदतों से दूर रहें और नियमित दाँतों की देखभाल करें साथ ही।■ भारती

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.
A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil
Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg
Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

उत्तराखंड आपदा के अधूरे सबक

चंदन राय

जून 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा के तीन वर्ष पूरे होने के बाद भी सरकार की कुंभकर्णी नींद अभी नहीं खुली है. पर्यावरण मानकों की अनदेखी कर क्षेत्र में पुनर्विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं. पर्यावरणविदों की बार-बार चेतावनी के बाद भी सरकार प्राकृतिक आपदाओं के पीछे बड़े बांधों की भूमिका स्वीकार करने को तैयार नहीं है. ऐसे में अब बेबस जनता प्राकृतिक आपदा को नियति का खेल मान विनाश लीला को झेलने के लिए मजबूर है.

भारी बारिश और ग्लेशियर के पिघलने को इस भीषण आपदा के लिए एकमात्र कारण बताना वाजिब मुद्दों से मुंह चुराना होगा. सच तो ये है कि नदियों के प्राकृतिक रास्ते में मानव निर्मित अवरोध पैदा कर लगातार उनका रास्ता बदलने का प्रयास किया जा रहा है. ऐसे में नदियों पर बड़े-बड़े बांधों के निर्माण ने अब प्राकृतिक आपदा के स्केल को कई गुना बढ़ा दिया है. ऐसा नहीं है कि जून 2013 की आपदा के पहले प्रकृति ने कोई चेतावनी नहीं दी थी. इससे पूर्व 2012 के अगस्त व सितंबर माह में अस्सीगंगा और केदारघाटी में बादल फटने से भीषण तबाही हुई थी. जून 2013 की आपदा का एक स्याह पक्ष यह भी है कि अलकनंदा नदी पर बना विष्णुप्रयाग बांध का दरवाजा नहीं खोलने से दो किलोमीटर लंबी झील का निर्माण हुआ था. इसके बाद पानी के दबाव से एक दरवाजा टूट गया और लामबगड़, विनायक चट्टी, पाण्डुकेश्वर आदि गांवों की ओर पानी तेजी से बढ़ा. पानी के तेज प्रवाह में कई गांव, पुल व बाजार बह गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते विष्णुप्रयाग बांध का दरवाजा खोल दिया जाता तो इस भीषण आपदा के प्रकोप को कम किया जा सकता था. देवप्रयाग से तीस किलोमीटर ऊपर श्रीनगर जल विद्युत परियोजना ने भी आपदा की विभीषिका को बढ़ाने का ही काम किया. जून 2013 की आपदा के पूर्व बांध के गेट आधे खुले थे, उनको पूरा बंद कर दिया गया, जिससे बांध की झील का जलस्तर तेजी से बढ़ा. बाद में जब बांध के गेट पर पानी का दबाव बढ़ने लगा तो तट के समीप रहने वाले निवासियों

को बिना चेतावनी दिए आनन-फानन में गेट खोल दिया गया. पानी के साथ नदी के तीन तटों पर बांध कंपनी द्वारा रखे गए मक भी तेजी से नीचे की ओर बढ़े, जिससे नदी की मारक क्षमता और विनाशकारी साबित हुई. मंदाकिनी नदी में भी फाटा ब्यौंग व सिंगोली भटवाड़ी जैसी कई छोटी-बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं संचालित हो रही हैं. बांध के निर्माण में विस्फोटकों का प्रयोग, सुरंग और पहाड़ के अंदर बने विद्युत गृह व अन्य निर्माण कार्यों का मलबा अब स्थानीय लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है. एक अनुमान के मुताबिक बांध परियोजनाओं का 150 लाख घनमीटर मलबा नदियों में बहा है, जिससे इन क्षेत्रों में नदियां प्रलयंकारी बन भीषण आपदा ला रही हैं.

रवि चोपड़ा समिति की रिपोर्ट में बड़े बांधों को मानव जाति के लिए विनाशकारी बताया गया था. समिति ने अपनी रिपोर्ट में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय व उत्तराखंड सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया था कि उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक किसी भी जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति न दे. गौरतलब है कि अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तराखंड में चल रहे 23 हाइड्रो पावर प्रोजेक्टस बंद करने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद प्राकृतिक आपदा से कोई सबक न लेते हुए सरकार ने पर्यावरण मानकों की उपेक्षा करते हुए विष्णुगाड पीपलकोटी व लखवार परियोजनाओं को मंजूरी दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जल्द रवि चोपड़ा समिति की रिपोर्ट पेश करने को कहा. सरकार ने रवि चोपड़ा समिति का कड़ा रुख देख बांध कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक और नई समिति का गठन कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर कहा कि जब तक कोई समिति उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्टस को हरी झंडी नहीं दे देती, क्या तब तक आप नई समिति बनाते रहेंगे. हालांकि इससे पूर्व दिसंबर 2014 में पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह स्वीकार किया था कि उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्टस के कारण जून 2013 में आई आपदा की भीषणता बढ़ी थी. अब हालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दोनों समितियों की रिपोर्ट दाखिल की गई है और बांध कंपनियों ने भी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी हैं. सरकार और बांध कंपनियों की साठगांठ के कारण यह मुद्दा कानूनी दाव-पेंच में उलझकर रह गया है. लेकिन सरकार को यह देखना होगा कि बांधों के समर्थन और विरोध से ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तराखंड व यहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा है.

विकास व ऊर्जा के नाम पर लूट

बड़े बांधों के विरोध में जनांदोलन शुरू होते ही सरकार तुरंत जाग जाती है. हालांकि हर सरकार की यही सोच होती है कि पर्यावरणविदों की मांग व जनांदोलनों के कारण कहीं बांध का काम न रुक जाए. वहीं पर्यावरण मानकों की उपेक्षा करने वाली बांध निर्माण कंपनियां भी बांध पर हुए खर्च का रोना रोने लगती हैं. पहले तो बांध कंपनियां जनहितों को दरकिनार कर बांध निर्माण पर जोर देती हैं, बाद में जब स्थानीय लोग पर्यावरण संरक्षण एवं अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं, तो उन्हें विकास विरोधी बताया जाता है. विकास और ऊर्जा के नाम पर पहले तो प्रकृति का खुलकर दोहन किया जाता है, बाद में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जनता को असहाय छोड़ सरकार हाथ खड़े कर देती है. फिर शुरू होता है पुनर्विकास के नाम पर पैसों का खेल, जिसमें फिर नए ठेके दिए जाते हैं और पैसों की लूट में बंदरबांट होता है. इसमें आम जनता की भूमिका सिर्फ तमाशबीन की होती है, जो सरकार व बांध कंपनियों की मिलीभगत को समझ कर भी ठगा महसूस करती है.

इस हाथ लो, उस हाथ दो

हालांकि अब बांध कंपनियों ने स्थानीय लोगों के विरोध को दबाने का एक अनूठा तरीका ढूंढ निकाला है. अब वे बांध निर्माण में स्थानीय लोगों को छोटे-छोटे ठेके देने लगी हैं. इसका असर यह हुआ है कि अब प्राकृतिक आपदा झेलने के बाद भी स्थानीय लोग विरोध के लिए सामने नहीं आते हैं. छोटे ठेकों का लॉलीपॉप थमाकर बांध के विरोध को दबा देना बांध कंपनियों की बड़ी जीत है.■

थाने में गुंडागर्दी कर रहे सपाइयों पर पुलिस ने बरती सख्ती

तो सीएम ने एसएसपी को सस्पेंड कर दिया

शत्रुंजय सिंह रैकवार

गोरखपुर के कैंट थानान्तर्गत इंदिरा-नगर गोपालपुर मोहल्ले में 13 जून की आधी रात लोग गोलियों की तड़तड़ाहट से उठ बैठते हैं. गोलीबारी में दो लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं. घटना से चूंकि सत्ता के नशे में चूर सपाई जुड़े थे, तो पुलिस तत्परता दिखाते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कैंट थाने ले आती है. सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल यादव के पुत्र गौरव यादव जो खुद भी सपा के पदाधिकारी हैं, थाने में ही विरोधियों से भिड़ जाते हैं.

पुलिस गौरव को समझाती है तो दारोगाओं की वर्दी उतरवा लेने की धमकियां थाने में ही उछाली जाती हैं. इससे भी मन नहीं भरता तो पुलिस वालों को मां-बहन की गालियां दी जाती हैं. तब तक कैंट के क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंच जाते हैं. पुलिस गौरव के साथ सख्ती से पेश आती है, इस पर सपाई नारे लगाते हैं, मामला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंचता है और यादव-रहनुमा मुख्यमंत्री गोरखपुर के एसएसपी अनंतदेव और कैन्ट थाने की तीन चौकियों के प्रभारियों को

निलंबित करने का फरमान जारी कर देते हैं. संयोग यह है कि 14 जून को मुख्यमंत्री गोरखपुर में ही मौजूद हैं, वहां जनता के हित की तमाम सियासी तकरीरें पढ़ते हैं और वहीं पर एक कर्मठ एसएसपी के निलंबन की जन-विरोधी पटकथा लिख देते हैं. छह महीने पहले ही गगहां थाने के बासूडीहा में दलितों और ठाकुरों के बीच हुए बवाल पर जब तत्कालीन एसएसपी प्रदीप यादव ने महिलाओं और बुजुर्गों पर कहर बरपाया था, तब वह मुख्यमंत्री को नहीं दिखा था. यहां तक कि इस समय सपा के ही विधान परिषद सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह की एसएसपी के खिलाफ शिकायत नहीं सुनी गई थी और विवश होकर सपा नेता को धरना पर बैठना पड़ा था. सपा के जातिवादी उन्माद में पगे होने का आरोप लगा कर देवेन्द्र प्रताप सिंह को सपा छोड़ देनी पड़ी. बाद में प्रदीप यादव का तबादला हुआ और लव कुमार गोरखपुर के एसएसपी बनाए गए. लेकिन सपा सरकार को लव कुमार की कार्यशैली भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि लव कुमार को असामाजिक तत्वों से चिढ़ थी और सपा सरकार को ऐसे तत्वों से लव है. लिहाजा, लव कुमार को चार महीने में ही गोरखपुर से रुखसत कर दिया गया. फिर अनंतदेव की पोस्टिंग हुई. स्पेशल टास्क फोर्स में रहते हुए अनंतदेव कई उल्लेखनीय टास्क पूरा करने का रिकार्ड कायम कर चुके हैं. लेकिन सपाइयों ने इन्हें भी निपटा दिया.

उल्लेखनीय है कि 13 जून की आधी रात को कैंट थाने के इंदिरा नगर गोपलापुर निवासी रामनयन यादव और चन्द्रजीत यादव के बीच जमीन पर कब्जे को लेकर अंधाधुंध गोलियां चलीं. इसमें रामनयन व चन्द्रजीत घायल हो गए. पुलिस ने इस मामले में सपा के जिला सचिव गौरव यादव समेत दोनों पक्षों के चार लोगों को हिरासत में ले लिया. दोनों ही पक्ष थाने में ही मारपीट करने लगे. पुलिस ने दोनों पक्षों के साथ सख्ती की तो सपाइयों ने बवाल मचाया. इसमें सपा के मौजूदा जिलाध्यक्ष मोहसिन खान ने एसएसपी के खिलाफ कुछ अधिक ही विरोध दिखाया, जबकि एसएसपी मौके पर मौजूद भी नहीं थे. आखिरकार एसएसपी और पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री से निलंबित करवा कर ही सपाई शांत हुए. मुख्यमंत्री के इस रवैये की चारों तरफ जबरदस्त निंदा हो रही है. निलंबित होने वाले अधिकारियों में एसएसपी अनंतदेव के अलावा मोहद्दीपुर चौकी इंचार्ज नरेंद्र प्रताप राय, बेतियाहाता चौकी इंचार्ज दिनेश तिवारी, जटेपुर चौकी इंचार्ज मृत्युंजय सिंह और सिपाही योगेश सिंह शामिल हैं. गोरखपुर के एसएसपी को इस तरह अमर्यादित तौर-तरीके से निलंबित किए जाने के मसले पर गोरखपुर के सांसद और गोरक्षधाम पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की जगह अपराध का बोलबाला है. मुख्यमंत्री की भी यही प्राथमिकता है. मथुरा और कैराना इसका जीता-जागता उदाहरण है. प्रदेश में आए दिन दुष्कर्म, लूट और हत्या की खबरें अलग-अलग इलाकों से आती रहती हैं. प्रदेश में सड़क पर चल रहे व्यक्ति की हत्या कब हो जाए यह किसी को नहीं पता. अनंतदेव जैसे आईपीएस अधिकारी का निलंबन कर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या संदेश देना चाहते हैं, यह तो वही जानें, लेकिन आम जनता का यही कहना है कि मुख्यमंत्री के लिए जातिवाद और असामाजिक तत्वों को संरक्षण देना ही प्राथमिकता पर है.■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश में क़ानून व्यवस्था की यही है असलियत

क़ानून हमारी मुट्ठी में

इसरार पठान

मथुरा कांड को लेकर खूब बवाल हुआ. विपक्षियों ने इस मामले में सरकार को कसूरवार ठहराते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की. विपक्ष की इस मांग पर सरकार ने इस पूरे प्रकरण में अपनी संलिप्तता और सरगना रामवृक्ष यादव को किसी भी प्रकार का संरक्षण दिए जाने से साफ इन्कार कर दिया. सरकार का दावा है कि वह सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सजग है और उन लोगों को लेकर सख्त है जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं. लेकिन यह दावा सरकार का सफेद झूठ है. कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की कथित संजीदगी धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रही. सरकार को यह बात समझ में नहीं आ रही कि कानून व्यवस्था बेमानी बयानबाजी से नहीं चलती. आज प्रदेश के हर गली कूचे में ऐसे हालात हैं जो प्रदेश की कानून व्यवस्था की ऐसी-तैसी कर रहे हैं. आम लोगों की सुरक्षा रामभरोसे ही रह गई है.

बीते दिनों बुंदेलखंड के महोबा जनपद में सत्तामद में चूर कुछ दबंग लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में एक दलित युवक और दो पत्रकारों को मार-मार कर यही साबित किया कि वे यादव हैं, इसलिए यूपी में उनका राज है. दोनों पत्रकारों और दलित युवक को सरेआम दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया. पुलिस आई तो पुलिस के सामने भी उन्हें पीटा गया. पुलिस को गालियां दी गईं, लेकिन पुलिस का स्वैया ऐसा रहा कि उसे हिजड़ा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हिजड़े भी अपने स्वाभिमान को सरेआम रौंदे जाना स्वीकार नहीं करते. इस घटना ने यह साफ कर दिया कि सूबे में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है.

पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. प्रदेश का हर शहर, कस्बा और गांव गुंडों और दबंगों के दबाव में है. बुंदेलखंड इससे अछूता नहीं. यहां सत्तामद में चूर मुख्यमंत्री के सजातियों ने मनमानी और गुंडागर्दी के सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं. इनकी नजर में न कानून के कोई मायने हैं और न ही

दलित युवक को कीचड़ में घसीट-घसीट कर मारा

पत्रकारों को भी पीट-पीट कर अधमरा कर दिया

उन्हें सरकार की धूमिल होती छवि से कोई सरोकार है. एक जाति विशेष के लोगों की बेजा हरकतें सरकार की छवि पर बट्टा लगा रही हैं. बुंदेलखंड में इस जाति विशेष के रुतबे और हैसियत को परखने के लिए बीते दिनों महोबा में घटी उस घटना पर नजर डालनी होगी जिसके शिकार एक दलित युवक और दो पत्रकार हुए. घटना 18 जून की है. दैनिक अखबार के दो पत्रकार मोहम्मद अकील और मूरतध्वज राजपूत देर शाम मुख्यालय से अपने घर के लिए रवाना हुए. अभी वे कुलपहाड़ कस्बे से कुछ आगे ही पहुंचे थे कि उनकी नजर सुंगिरा गांव में सड़क के किनारे लगी लोगों की भीड़ पर पड़ी. दोनों पत्रकार पेशेगत उत्सुकतावश गाड़ी से उतरकर वहां पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति को बुरी तरह पीट रहे हैं. उन्होंने जब वहां खड़ी भीड़ से जानकारी ली तो पता चला कि पिटने वाला एक गरीब दलित है और उसे मार रहे लोग यादव जाति के दबंग लोग हैं. कारण पूछने पर लोगों ने बताया कि दलित का कसूर यह था कि उसने एक सूखे पेड़ की कुछ लकड़ी काट ली थी. इस वजह से उसे बेरहमी से पीटा जा रहा है. लोगों ने बताया कि पीटने वालों में वन विभाग का एक वॉचर भी है. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पत्रकार अकील ने कुलपहाड़ कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक का सीयूजी नम्बर डायल किया, पर कई बार घंटी जाने के बाद भी फोन नहीं उठा. वैसे भी पुलिसवाले किसी आम आदमी का फोन मुश्किल से ही उठाते हैं. दारोगा का फोन नहीं उठने पर पत्रकार ने घटना की फोटो खींचने के लिए कैमरा निकाला. उसने जैसे ही क्लिक की, दबंगों ने पत्रकारों पर हमला बोल दिया. सत्ता और शराब के नशे में चूर दर्जनभर लोगों ने दलित युवक सहित दोनों खबरनवीसों को लाठी-डंडों से तब तक मारा जब तक वह तीनों बेदम नहीं हो गए. दबंगों ने उन्हें मार-मार कर अधमरा कर दिया और उनके पैसे, मोबाइल, चेन और अंगूठी वगैरह छीन ली. राहगीरों की सूचना पर काफी देर बाद वहां पहुंची पुलिस के सामने हमलावरों ने फिर पत्रकारों को पीटा और पुलिस को भी भद्दी गालियां दीं. पुलिस ने मुंह तक नहीं खोला. दबंगों ने पुलिस को भी ललकारा, लेकिन पुलिस खामोश रही और घायलों को ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराने की औपचारिकता पूरी कर दी.

दबंगों के सामने भीगी बिल्ली बने पुलिस वाले कोतवाली में आते ही बदल गए और पूरा तेवर दिखाते हुए दबंगों से समझौता करने के लिए दबाव बनाने लगे. कोतवाली का प्रभार संभाले एसआई वीरेंद्र यादव ने अस्पताल से मरहमपट्टी करा कर थाने पहुंचे दलित रामकिशुन श्रीवास को धमकाकर भगा दिया, लेकिन पत्रकारों के सामने उसकी नहीं चल सकी. घटना की सूचना पर कुलपहाड़ कस्बे के सारे पत्रकार अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने इसकी सूचना मुख्यालय के पत्रकारों को भी कर दी. घायलों को जिला अस्पताल रेफर किए जाने की सूचना पाकर मुख्यालय के प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार वहां जमा हो गए. जिला चिकित्सालय में साथी पत्रकारों का हाल देखकर प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय मिश्रा समेत कई अन्य पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह को मामले से अवगत कराते हुए दबंगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की. एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया तथा रात में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस को दलित की तहरीर पर भी मुकदमा लिखना पड़ा. फिलहाल इस घटना के तीन नामजद आरोपी बहादुर यादव, राजेश व वीर सिंह यादव जेल भेज दिए गए हैं, लेकिन अज्ञात हमलावरों की तलाश को लेकर कोतवाली पुलिस अभी भी उदासीनता बरत रही है. इस घटनाक्रम में पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह की कार्यशैली काबिले तारीफ तो थी, लेकिन उन्होंने एसआई वीरेन्द्र सिंह यादव पर कोई एक्शन नहीं लिया, इसको लेकर लोगों में चर्चा है. सार्वजनिक तौर पर लोग यह कहते मिल जाएंगे कि यादव दारोगा पर एसपी कार्रवाई कैसे कर सकता है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पंगा लेना है क्या?

पुलिस गालियां सुनती रही और गुंडई देखती रही

सुंगिरा गांव के बहादुर यादव ने किया नंगा नाच

बहरहाल, पत्रकारों पर हो रहे सिलसिलेवार हमलों को लेकर महोबा सहित पूरे बुंदेलखंड के पत्रकार गुस्से में हैं. महोबा में आल्हा चौक स्थित अम्बेडकर पार्क में बड़ी संख्या में पत्रकारों ने बैठक कर पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की और उसके उपरान्त सड़क पर बाइक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया. पत्रकारों ने जिलाधिकारी वीरेश्वर सिंह को ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कठोर कदम उठाए जाने की मांग भी की. बाद में डीएम के आदेश पर हमले के आरोपी वन वॉचर बहादुर सिंह को प्रभागीय वनाधिकारी ने निलम्बित कर दिया. जनपद जालौन में भी उपजा के बैनर तले पत्रकारों ने विरोध जताया और जिलाधिकारी संदीप कौर को ज्ञापन सौंपा.

सरकार हमारी है, दारोगा तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा : महोबा कोतवाली का दारोगा जब वारंट तामील कराने एक आरोपी के घर गया तो उसने दारोगा के साथ जो सलूक किया, उसे सुनें तो आप यह समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में असामाजिक तत्वों और अपराधियों के मन में पुलिस का और कानून का कितना बाकी डर रह गया है. एसआई जब वारंट तामील कराने आरोपी के घर पहुंचा तो आरोपी अपने घर के सामने ही नशे में धुत्त हालत में कुर्सी पर पैर चढ़ाए बैठा था. एसआई ने उससे वारंट में दर्ज नाम वाले व्यक्ति से उसका मिलान किया तो उसने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, हां मैं ही हूं! दारोगा ने जब आरोपी को सलीके से बैठने की नसीहत दी तो उसने चिल्ला कर कहा, अभी हमारी सरकार छह महीने और है, जब तक सरकार है, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे. आरोपी ने दारोगा जी को वहां से चुपचाप चले जाने की धमकी भरी नसीहत दी और कहा, नहीं गए तो दारोगा तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा. दारोगा जी अपनी वर्दी संभालते वापस लौट गए और कानून व्यवस्था का अखिलेशी-दावा फिसड्डी होता दिख गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

अकादमी सचिव की 'ललित' कला

अनंत विजय

ललित कला अकादमी एक बार फिर से गलत वजहों से सुर्खियों में है. संस्कृति मंत्रालय ने ललित कला अकादमी के रिकॉर्ड रूम को सील कर दिया है. खबरों के मुताबिक जिस कमरे में फाइलें रखी जाती हैं उसमें सचिव सुधाकर शर्मा के सहयोगी को देखे जाने की शिकायत के बाद मंत्रालय ने ये कदम उठाया है. अकादमी से मंत्रालय को शिकायत मिली थी कि सुधाकर शर्मा के सहयोगी रिकॉर्ड रूम में जाकर दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर रहे हैं. दरअसल ललित कला अकादमी के विवादित सचिव सुधाकर शर्मा पर कई संगीन इल्जाम है और इनमें से कुछ मामले अदालत में चल रह हैं. आरोप है कि इन्हीं केसों से जुड़े दस्तावेजों से छेड़छाड़ की जा रही थी. सुधाकर शर्मा को ललित कला अकादमी के दो पूर्व चैयरमैन ने अलग-अलग समय पर बर्खास्त कर दिया था, बावजूद इसके वो बार-बार फिर से किसी ना किसी तरह अकादमी के सचिव पद पर आसीन हो जाते हैं. पहले अशोक वाजपेयी ने उनके खिलाफ फैसला लिया था और उनके बाद चेयरमैन बने के के चक्रवर्ती ने भी सचिव सुधाकर शर्मा को गड़बड़ियों के आरोप में बर्खास्त कर दिया था. चक्रवर्ती के फैसले के खिलाफ सुधाकर केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट में अपील में गए जिसने केंद्र सरकार को इस मामले पर विचार करने की सलाह दी. जब यह मामला चल रहा था और कैट का फैसला आया तबतक केंद्र में सरकार बदल चुकी थी. नए बने संस्कृति मंत्री महेश शर्मा के कार्यकाल में ललित कला अकादमी के सचिव सुधाकर शर्मा को दोबार बहाल कर दिया था. बेहद दिलचस्प घटनाक्रम में केंद्र सरकार ने के के चक्रवर्ती को चेयरमैन के पद से हटाते हुए ललित कला अकादमी का कंट्रोल अपने पास ले लिया था और संस्कृति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव को उसका प्रभार सौंप दिया गया था. इस बीच खबर आई कि सीएजी ने भी सुधाकर शर्मा को दिए गए वेतनमान पर आपत्ति उठाई है और अपनी सिफारिश में कहा है कि सुधाकर शर्मा को दिए गए अतिरिक्त भुगतान को उनसे वसूला जाए. इन सब प्रसंगों और घटनाक्रमों के बीच ललित कला अकादमी से बेहद मंहगी पेंटिंग्स गायब होने की जांच भी जारी थी.

दरअसल ललित कला अकादमी को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है. इस वजह से आप अगर देखें तो जब केंद्र सरकार ने अकादमी की स्वायत्ता को खत्म कर उसका नियंत्रण अपने हाथ में लिया तो उसपर ज्यादा विवाद नहीं हुआ. बात-बात पर अभिव्यक्ति की आजादी के खतरे में होने और सांस्कृतिक संगठनों पर भगवा झंडा फहराने का आरोप लगाने वाले वीर भी लगभग खामोश ही रहे. उन्हें मालूम था कि ललित कला अकादमी में किस तरह के खेल-खेले जा रहे हैं. दरअसल इन अकादमियों की स्वायत्ता की आड़ में अराजकता के खेल पर लगाम लगाने की जरूरत है. साहित्य और कला को लेकर जिस स्वायत्ता की कल्पना की गई थी उसको मूल रूप में स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए. अपने इस स्तंभ में मैंने अकादमियों के काम-काज पर कई बार टिप्पणी की है. इनके पुरस्कारों से लेकर विदेश यात्राओं तक में जिस तरह से बंदरबांट की जाती है उसपर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है. अकादमियों के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की अध्यक्षता वाली संसद की स्टैंडिंग समिति ने 17 अक्तूबर 2013 को राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट पेश की थी. इस रिपोर्ट को दोनों सदनों के पटल पर दो महीने बाद यानि 17 दिसबंर 2013 को पेश किया गया था. इस रिपोर्ट में अकादमियों के काम-काज को लेकर बेहद कठोर टिप्पणियां की गई थी. राष्ट्रीय अकादमियों और अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं का कार्यकरण- मुद्दे और चुनौतियों के नाम से तैयार की गई इस रिपोर्ट में साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के काम-काज का लेखा-जोखा तो प्रस्तुत किया ही था, साथ ही इन संस्थानों में सुधारों के बारे में सिफारिश भी की थी. दिसंबर 2013 के बाद तो पूरा देश चुनाव के मोड में चला गया था और चुनावी कोलाहल के बीच किसी को कला और संस्कृति की सुध लेने की फुरसत नहीं थी. संसद की इस रिपोर्ट के बाद एक हाईलेवल कमेटी भी बनी थी जिसने भी कुछ सुझाव आदि दिए थे लेकिन लगता है कि उनपर अमल नहीं हो पाया है. हाईलेवल कमेटी के सुझावों पर देशभर में गंभीर बहस की जरूरत है.

संसदीय समिति ने अपने प्रतिवेदन में माना था कि- यह अकादमियां हमेशा से विवादग्रस्त रही हैं. हमारे संस्थापकों ने संस्कृति को राजनीति से दूर रखने के लिए इन्हें स्वायत्ता दी परंतु आज ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति इनमें पिछले दरवाजे से गुपचुप तरीके से प्रवेश कर गई है. इन संस्थाओं

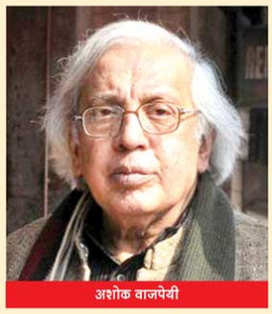
अशोक वाजपेयी

के संस्थापकों को लेखकों और कलाकारों के समुदाय की एकता पर दृढ विश्वास था और वे आज इन संस्थाओं को बाधित करनेवाली समस्याओं का पूर्वानुमान नहीं लगा पाए. इसके परिणामस्वरूप प्रक्रिया में पारदर्शिता और परिणाम के संबंध में जवाबदेही का आभाव है. वस्तुतः पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना उसकी स्वायत्ता एक दुधारी तलवार बन गई है जिसको कोई भी अपनी सुविधानुसार प्रयोग कर सकता है. अब अगर हम इस टिप्पणी के आलोक में ललित कला अकादमी और उसके सचिव का मामला देखें तो साफ हो जाता है कि इस पूरे मामले में ना केवल जमकर राजनीति हुई बल्कि स्वायत्ता के नाम पर भी तमाम तरह की गड़बड़ियों को अंजाम दिया गया. स्वायत्ता के नाम पर हर नियम का सुविधानुसार उपयोग किया गया. यूपीए सरकार के दौरान बनाए गए ललित कला अकादमी अध्यक्ष के उस फैसले को बदल दिया गया जिसमें उन्होंने सचिव सुधाकर शर्मा को बर्खास्त करने का आदेश दिया था. तब मंत्रालय ने तर्क दिया था कि इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं हुआ. अब उसी सरकार ने फिर से ललिता कला अकादमी के सचिव सुधाकर शर्मा के कामकाज की जांच का एलान किया है. अकादमी के कमरे को सील कर दिया है.

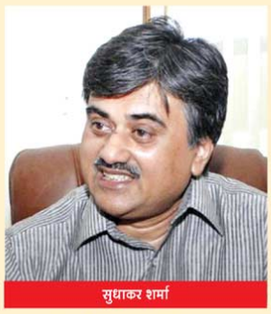
सुधाकर शर्मा

संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि अकादमियों और तमाम सांस्कृतिक संस्थानों के काम-काज पर नजर रखने के लिए एक नियंत्रक निकाय होना चाहिए. इस निकाय को यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए कि सभी अकादमियों और संगठनों के प्रशासन उनके लिए निर्धारित नियमों तथा संविधानों के अनुसार कार्य संचालित कर रहे या नहीं. इस कमेटी ने कला के क्षेत्र में प्रेस परिषद की तरह की संस्था बनाने का सुझाव भी दिया था और उसके सदस्यों का चुनाव भी उसी की तर्ज पर करने की सिफारिश की थी. दरअसल कमेटी की इस सिफारिश के पीछे ये मंशा थी कि लेखक या कलाकार अगर अकादमियों में हो रही गड़बड़ियों की शिकायत करना चाहे तो उसके पास एक प्लेटफ़ॉर्म हो. लेकिन इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं हो पाया और ये अकादमियां गड़बड़ियों का जीता जागता उदाहरण बनकर शान से काम कर रही हैं. ललित कला अकादमी के सचिव पर तमाम तरह की गड़बड़ियों के आरोप लगे, कई बार सस्पेंडसे लेकर बर्खास्त तक कर दिए गए लेकिन फिर से वो बहाल होते रहे. इस पूरे प्रकरण से यह साफ है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है. इस गड़बड़ी को दूर किए बिना इन अकादमियों को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है. ललित कला अकादमी देश में कला के उत्थान और उन्नयन के लिए काम करती है लेकिन उसके कामकाज का नियमित ऑडिट होना जरूरी है. इस बात का लेखा-जोखा लिया जाना चाहिए की जिस मूल उद्देश्य के लिए उसकी स्थापना कि गई थी उस दिशा में वो आगे बढ़ पा रही है या नहीं. ललित कला अकादमी में अध्यक्ष और सचिव के बीच बहुधा ठनी रहती है जिसका नुकसान कलाकारों से लेकर कला तक को हो रहा है.

ललित कला अकादमी के अलावा साहित्य अकादमी की सालों से चली आ रही नियमों को अपडेट करने की जरूरत है. जैसे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और साधारण सभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया बेहद दोषपूर्ण है. वहां हाथ उठाकर प्रत्याशियों का चयन कर लिया जाता है और बहुधा हर भाषा के लोग एक अलिखित समझौते के तहत अपनी भाषा के प्रतिनिधि का चुनाव कर देते हैं. इसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं होती है और एक खास गुट के लोगों का कब्जा बरकरार रहता है. गड़बड़ी यहीं से शुरू होती है. सरकार को इस दिशा में काम करने की जरूरत है. साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और उसकी साधारण सभा के सदस्यों का चुनाव या तो बैलेट से हो या फिर उसके लिए कोई ऐसी प्रक्रिया बनाई जाए जो पारदर्शी हो और उसमें मनमानी की गुंजाइश नहीं रहे. सवाल वही है कि क्या सरकार में इन संस्थाओं की स्वायत्ता को बरकार रखते हुए गड़बड़ियों को दूर करने की इच्छाशक्ति है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

आम

परिचय

आम भारतवर्ष एवं उष्णकटिबन्धी पूर्वी द्वीप समूह में मूलतः पाया जाने वाला वृक्ष है. यह ग्रीष्म जलवायु का वृक्ष है. हिमालय पर भूटान से उत्तराखंड तक इसके जंगली वृक्ष पाए जाते हैं. सम्पूर्ण भारतवर्ष में इसके वृक्ष लगाए जाते हैं और फलते-फूलते हैं. आम की अनेक किस्में पाई जाती हैं, जो पौधे गुठली से उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें देशी या बीजू आम और जो उन्नत जाति के आम के वृक्षों की शाखाओं पर कलम बांध कर तैयार किए जाते हैं, वे कलमी आम कहलाते हैं. इनके अतिरिक्त देश, स्थान, आकार, रंग, रूप भेद से इनकी अनेक किस्में मिलती हैं. देशी आम में रेशा होने से इसका रस पतला होता है, परन्तु कलमी आम में फल का गूदा अधिक होता है. औषधि प्रयोग हेतु कलमी की अपेक्षा, बीजू (देशी) आम ज्यादा गुणकारी होते हैं. भारतीयों को इसके गुणधर्मों का परिचय अति प्राचीन काल से था. प्राचीन आयुर्वेदीय-संहिताओं में इसका अत्यन्त वर्णन प्राप्त होता है. संस्कृत के आम्र और सहकार ये इसके दो नाम विशेष अर्थ बोधक है. पुष्प रहित फल वाले वृक्ष को आम्र, तथा फल-फूल दोनों से युक्त को सहकार कहते हैं. आम्रफल सबको प्यारा है राजा रंक सभी कोई इसे बड़े प्रेम से खाते हैं और इसे सब फलों में श्रेष्ठ मानते हैं. इसीलिए इसको नृपप्रिय, फलश्रेष्ठ, फलाधिराज कहते हैं. मनुष्यों के अतिरिक्त तोता, कोयल आदि पक्षियों को भी यह बहुत प्रिय होता है. अतः इसे पिकबल्लभ, पिकप्रिय, पिकमहोसत्व, कोकिल बन्धु, कोकिलावास आदि नाम दिए गए हैं. ठीक कहा जाता है कि जिस प्रकार स्वर्ग में अमृत है उसी प्रकार पृथ्वी में आम्रफल है. यह प्रायः सब फलों की अपेक्षा उत्तम एवं अधिक गुणकारी तथा अनेक रोगों का नाशक, समस्त इन्द्रियों को तृप्त करने वाला, बलदायक, अत्यन्त वृष्य, कामशक्तिवर्धक और मन को प्रिय लगने वाला होने से ही वास्तव में फलाधिराज है. कहा है-

सन्तर्पणो यः सकलेन्द्रियाणां बलप्रदो वृष्यतमश्च हृद्यः .
स्त्रीषु प्रहर्षं प्रचुरं ददाति फलाधिराजः सहकार एवं.. (योग रत्नाकर)

बाह्य-स्वरूप

इसका वृक्ष 10-20 मी तक उंचा, शाखा-प्रशाखायुक्त होता है. इसके पत्र 10-30 सेमी लम्बे, 2-9 सेमी चौड़े, चमकीले, हरे वर्ण के, लम्बे तथा नुकीले होते हैं, जिनके मसलने पर सुगंध आती है. इसके पुष्प छोटे हरित पीत, लम्बी मंजरी में आते हैं तथा पूरे वृक्ष को ढक लेते हैं, जिससे मादक सुगन्ध आती है. इसके रसीले अण्डिलफल अनके आकृति के, कच्चे में

हरे तथा पकने पर पीताभ या रक्ताभ हो जाते हैं. फल के भीतर बड़ी गुठली तथा उसके भीतर बीजमज्जा होती है. इसका पुष्पकाल फरवरी से मार्च तथा फलकाल मई से जून तक होता है.

आयुर्वेदीय गुण-कर्म एवं प्रभाव

- आम की बीज मज्जा-कफपित्त शामक, स्तंभक, मूत्र संग्रहणीय, रक्तरोधक तथा व्रणरोपण होती है.
- इसका कच्चाफल त्रिदोषकारक होता है.
- इसका फल दाह प्रशामक, रोचन, दीपन तथा रक्तपित्त हर होता है.
- पका फल वात-पित्त शामक, स्नेहन, अनुलोमन, सारक, शोणितस्थापन, वृष्य, बलकारक तथा बृंहण होता है.
- आम का बौर (फूल) शीतल, वातकारक, मलरोधक, अग्निदीपक, रुचिवर्धक, प्रमेह और कफशामक होता है.
- आम की जड़-कसैली, मलरोधक, ग्राही, सुगन्धित, रुचिकारक तथा वात-पित्त और कफ को हरने वाली है.
- आम की गुठली वमन, अतिसार और हृदय की पीड़ा को दूर करती है.
- आम की गुठली का तेल कसैला, स्वादिष्ट, रूखा, कड़वा तथा मुखरोग, कफ एवं वात-शामक होता है.
- आम का पत्र संग्राही, रक्तपित्त, दाह तथा तृष्णा का शमन करता है.
- पका हुआ आम कफकारक तथा शुक्रवर्धक होता है.
- आम का रस स्निग्ध तथा कफकारक होता है.
- इसकी काण्डत्वक् का ऐथेनॉल सार चूहों के मधुमेह रोग (Type 2 Diabetes) में शर्करा अवशोषण की दर को कम कर देता है.
- इसका सार अनॉक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

शिरो रोग :

- **केशकल्प-** आम की गुठलियों से सिद्ध तेल को लगाने से सफेद बाल काले हो जाते हैं. बाल झड़ना व रूसी में भी इससे लाभ होता है.
- **शिरःशूल-** आम की लकड़ी को जल में घिसकर या नीम की लकड़ी को ठंडे पानी में घिसकर मस्तक पर लेप करने से शिरःशूल का शमन होता है.
- आम्रफलमज्जा, आंवला, पिप्पली, काली मिरच तथा मिश्री को जल में पीसकर शिर पर लेप लगाने से शिरःशूल का शमन होता है.
- आम के कोमल पत्रों को पीसकर लगाने से बाल काले होते हैं. पत्तों के साथ कच्चे आम के छिल्कों को पीसकर तेल मिलाकर धूप में रख दें. इस तेल को लगाने से बालों का झड़ना रुक जाता है व बाल काले हो जाते हैं. ■

जारी...

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

इस संसार में ऐसे असंख्य लोग हैं, जो किसी गुरु को नहीं मानते

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

गुरु-कृपा पानेवाले का धर्म

सद्गुरु जब कृपा करते हैं, तो कृपा पाने वाले का क्या धर्म होना चाहिए?

सद्गुरु फ़कीर होते हैं अर्थात जो सब कुछ त्यागकर ईश्वर से ली लगाए रहते हैं. जब वे किसी पर कृपा करते हैं तो बदले में अपने लिये कुछ भी आशा नहीं करते. कोई भाषा-विलास, भाव-विलास या युक्ति- विलास से उन्हें प्रसन्न करना चाहे तो यह कभी न होगा. फ़कीर सिर्फ़ भक्ति के वश में हैं-

फकीर मेरा दीन-दयाला सब कुछ देता जाए,
ना कुछ मांगे ना कुछ बोले कृपा बरसाता जाए.

लेकिन एक बात निश्चित है कि जो प्राणी फकीर की कृपा से प्राप्त धन, समय एवं शक्ति का अपव्यय या दुरुपयोग करेगा, उसे उसका भुगतान अवश्य करना पड़ेगा. अतः सद्गुरु की कृपा से जो प्राप्त हो, कल्याणकारी कार्यों के लिए उसका सदुपयोग करना चाहिए.

सर्वत्र गुरु-कृपा

इस संसार में ऐसे असंख्य लोग हैं, जो किसी गुरु को नहीं मानते और न ही वे गुरु की महानता पर ध्यान देते हैं, जो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि गुरु उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहे?

नहीं, ऐसी बात नहीं है. वस्तुतः सद्गुरु के माध्यम से ईश्वर की कृपा-शक्ति सूर्य किरण की तरह चारों ओर फैली हुई है. सूर्य-किरण की प्रतिक्रिया सजीव प्राणी और पेड़ आदि पर भी है तथा निर्जीव पत्थर, नाल्लों आदि पर भी है. उसी प्रकार सद्गुरु की कृपा-शक्ति भी विश्व भर में फैली हुई है. कोई विश्वास करे या न करे इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता. गुरु-शक्ति को न मानने वाले व्यक्ति भी अपना नियत समय आने पर उस ओर चल देते हैं.

गुरु की अलौकिक कार्य-प्रणाली

यह कहा जाता है कि गुरु सूक्ष्म रूप से भी कार्य करते हैं. प्राणियों की आध्यात्मिक चेतना के विकास की दिशा में गुरु की सूक्ष्म शक्ति किस रूप में कार्य करती है?

गुरु की सूक्ष्म शक्ति इतने रूपों में कार्य करती है कि उसे समझ पाना आसान नहीं है. संक्षेप में यदि कहा जाए तो उस कार्य-विधि के विभिन्न स्तर या अवस्थाएं हैं. सर्वप्रथम गुरु अपनी ओर जीव को आकर्षित करते हैं. इस स्थिति में प्राणी उनके प्रभामंडल के घेरे में आता है. गुरु की आकर्षण-शक्ति का प्रभाव उसके अंतःस्थल को एक भाव-तरंग के रूप में छूता है, जिससे वह अभिभूत हो जाता है. इसको सालोक्य कहते हैं. उसी के परिणामस्वरूप धीरे-धीरे व्यक्ति के हृदय में शुद्धता आने लगती है. शुद्धता के प्रयास-शुद्धता से वह क्रमशः गुरु के समीप आने लगता है. उसी को समीप्य कहते हैं. फिर धीरे-धीरे गुरु की आंतरिक शक्ति शिष्य के भीतर आने से उसके रूप, भंगिमा, हाव-भाव, मुद्रा आदि में समानता आने लगती है. इसको सारूप्य कहते हैं. फिर होती है सौष्ठीय, जिसका अर्थ है कि इस अवस्था में गुरु की सूक्ष्म शक्ति शिष्य के माध्यम से कार्य करने लगती है. अंत में जब शिष्य संपूर्ण रूप से गुरु में समा जाता है, तो उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती और वे एक हो जाते हैं. इसे सायुज्य कहते हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

सायना की धमक

रियो में मिल सकता है बैडमिंटन में पदक

2014 में चाइना ओपन जीतकर पहली भारतीय विजेता होने का सायना ने गौरव हासिल किया. 2014 तक सायना की तूती पूरे विश्व बैडमिंटन जगत में बोलने लगी. 2015 में भी सायना का सिक्का चला. इस साल इंडियन ओपन के अलावा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता फाइनल में प्रवेश कर सायना पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं. इतना ही नहीं वह विश्व नम्बर एक खिलाड़ी भी बन गईं.

पीवी सिन्धु

किदाम्बी श्रीकांत

ज्वाला गुट्टा

अश्विनी पोनप्पा

सैय्यद मोहम्मद अब्बास

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल ओलम्पिक के लिए तैयार हैं. रियो का सपना देख रही सायना ने फिर गजब का फॉर्म दिखाया है. सायना ने अब चीनी दीवार को भेदने के लिए खास रणनीति बनाई है. उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज में चीनी दीवार को ध्वस्त करते हुए भारत का झंडा बुलन्द कर दिया है. भारत की सनसनी सायना ने चीन की सुन यू को 11-21, 21-14, 21-19 से पराजित कर इस साल का पहला खिताब जीता. यह खिताब कई मायनों में अहम माना जाएगा. ओलम्पिक में अब बेहद कम दिन रह गए हैं. ऐसे में यह जीत सायना के लिए टॉनिक का काम करेगी. बैडमिंटन में चीनी खिलाड़ियों का हमेशा दबदबा रहा है, लेकिन भारत के पास कई ऐसे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो चीन की दीवार लांघने में सक्षम हैं. हालांकि यह बात भी सत्य है कि कुछ खिलाड़ी अहम मौकों पर चूक जाते हैं. ओलम्पिक में पदक की दावेदारी को लेकर भारतीय टीम अपना दावा मजबूत कर रही है. पदकों की होड़ में चीनी खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा खतरा सायना नेहवाल से है. सायना भी लगातार चीनी खिलाड़ियों को पटखनी दे रही हैं. वहीं पीवी सिन्धु से लेकर ज्वाला भी पदक की कतार में शामिल हैं. ओलम्पिक को ध्यान में रखकर सायना लगातार पसीना बहा रही हैं. इस दौरान उन्होंने कोच भी बदला है. लन्दन ओलम्पिक में उनके कोच गोपीचंद हुआ करते थे, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है. गोपीचंद सायना के कोच नहीं हैं. हालांकि गोपीचंद रियो ओलम्पिक में भारतीय बैडमिंटन टीम के साथ जुड़े रहेंगे. गोपीचंद की कोचिंग में सायना ने कई इतिहास बनाए हैं. भारत की दिग्गज शटलर सायना नेहवाल का पूरा ध्यान इस समय ओलम्पिक पर लगा है. इस साल सायना की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. कई बड़े-बड़े टूर्नामेंट में सायना ने फीका प्रदर्शन किया है. कई टूर्नामेंट में उनकी गाड़ी सेमी फाइनल तक नहीं पहुंची लेकिन ऑस्ट्रेलियाई ओपन की जीत से सायना ने अपना खोया आत्मविश्वास फिर से हासिल कर लिया है.

भारत की प्रतिभावान खिलाड़ियों में एक सायना का करियर बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा है. एक खिलाड़ी के तौर पर उनका करियर बेहद शानदार रहा है. यह बहुत कम लोग जानते हैं कि सायना पहले कराटे के दाव-पेंच में माहिर थीं. दरअसल शुरुआती दिनों में वह कराटे में देश का मान बढ़ाना चाहती थीं. कराटे सीखने के लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी हासिल किया था. हालांकि बाद में सायना ने बैडमिंटन में अपना लोहा मनवाया. बैडमिंटन में अगर सायना आज इतना जलवा दिखा रही हैं तो इसमें उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान है. सायना के पिता हरवीर सिंह नेहवाल ने अपनी लाडली बेटी को बैडमिंटन क्वीन बनाने की ठान ली थी. उन्होंने बेटी के सपनों को उड़ान देने के लिए कई कुर्बानियां दीं. बैडमिंटन के अभ्यास के लिए सायना को घर से 25 किलोमीटर दूर लाल बहादुर स्टेडियम जाना पड़ता था. उनके पिता हरवीर सिंह अपनी बेटी की हर सफलता में कदम से कदम मिलाकर चले. सायना धीरे-धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगीं. राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाने के बाद अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी सायना ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी. 2006 में सायना फिलीपींस ओपन बैडमिंटन का खिताब जीतकर एकाएक सुर्खियों में आ गईं. इसके बाद तो सायना ने खिताबों की झड़ी लगा दी. बीजिंग ओलम्पिक के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर उन्होंने एक नया इतिहास बना डाला. बीजिंग ओलम्पिक के बाद सायना बेहद प्रचंड फॉर्म में थी. सायना ने 2009 और 2010 में इंडोनेशियाई ओपन जीतकर चीनी खिलाड़ियों के माथे पर बल ला दिया. उस दौर में चीनी खिलाड़ी सायना के खौफ से बचने की जुगत में रहते थे. उनकी कोशिश रहती थी कि उनकी सायना से लीग मैचों में भिड़ंत न हो. 2010 में सायना का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था. वे लगातार एक के बाद एक टूर्नामेंट में भारत का परचम बुलन्द कर रही थीं. इसी साल उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी धमाकेदार शुरुआत की. साल 2012 आते-आते सायना ने बेहद कम उम्र में कई खिताब अपनी झोली में डाल लिए थे. उनमें 2012 स्विस ओपन, थाइलैंड ओपन, इंडोनेशिया ओपन और सबसे महत्वपूर्ण लन्दन ओलम्पिक के महिला एकल में कांस्य पदक जीतना है. इतना ही नहीं, इसके बाद डेनमार्क ओपन खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया. 2014 में चाइना ओपन जीतकर पहली भारतीय विजेता होने का सायना ने गौरव हासिल किया. 2014 तक सायना की तूती पूरे विश्व बैडमिंटन जगत में बोलने लगी. 2015 में भी सायना का सिक्का चला. इस साल इंडियन ओपन के अलावा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता फाइनल में प्रवेश कर सायना पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं. इतना ही नहीं वह विश्व नम्बर एक खिलाड़ी भी बन गईं.

मौजूदा साल यानी 2016 हर एथलीट के लिए अहम माना जा रहा है. दरअसल रियो ओलम्पिक इसी साल होना है. ऐसे में दुनियाभर के खिलाड़ी लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं. बैडमिंटन स्टार सायना के लिए भी ओलम्पिक बेहद महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है. वह इसी को ध्यान में रखकर पसीना बहा रही हैं. इस साल खराब फॉर्म की वजह से उन्हें कई बड़े टूर्नामेंट में नाकामी भी झेलनी पड़ी. सायना टूर्नामेंट में लगातार हार रही थीं और उनकी फिटनेस भी जवाब दे रही थी. लेकिन उन्होंने साल का पहला टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीतकर खुद को साबित किया और ओलम्पिक में पदक की दावेदारी को और मजबूत भी कर दिया. इस बार रियो ओलम्पिक में खासकर बैडमिंटन में भारत के पदक जीतने की ज्यादा सम्भावना है. ■

रियो ओलम्पिक के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम की घोषणा कर दी गई है. टीम में सायना नेहवाल, पीवी सिन्धु, किदाम्बी श्रीकांत व ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा जैसे जुझारू खिलाड़ी शामिल हैं. पुरुष युगल के लिए मनु अत्री और बी सुमंत रेड्डी पहली बार ओलम्पिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे. इससे पूर्व लन्दन ओलम्पिक में पांच भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला था. इस बार पहले की तुलना में मजबूत टीम भेजी जा रही है. रियो में सायना के अलावा किसी और खिलाड़ी की बात की जाए तो उनमें सबसे प्रमुख हैं पीवी सिन्धु. रियो ओलम्पिक में भारत की तरफ से वे पदक की तगड़ी दावेदार हैं. भारत की अगली सायना के नाम से भी उन्हें पुकारा जाता है. दरअसल भारतीय बैडमिंटन अगर विश्व में चमक रहा है तो उसमें सायना और सिन्धु का नाम प्रमुख है. पीवी सिन्धु ओलम्पिक में पहली बार हिस्सा ले रही हैं. उनका प्रदर्शन भी तमाम उतार-चढ़ाव के बावजूद ठीक-ठाक कहा जा सकता है. अपने करियर में उन्होंने अब तक छह एकल खिताब अपने नाम किए हैं. 2011 में पहली बार इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जीतकर सुर्खियां बटोरी. इसके बाद मलेशिया ओपन बैडमिंटन में उन्होंने न सिर्फ खिताबी बल्कि लोगों का दिल भी जीता. इतना ही नहीं 2013, 2014, और 2015 में मकाऊ ओपन जीतकर खिताबी हैट्रिक लगाई. इस साल उन्होंने मलेशियाई मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया. किदाम्बी श्रीकांत का नाम भी पदकों की दौड़ में शामिल है. किदाम्बी श्रीकांत का करियर अभी शुरू हुआ है, लेकिन बैडमिंटन की दुनिया में उन्होंने बेहद कम समय में कामयाबी का स्वाद चखा है. श्रीकांत ने इंडिया सुपर सीरीज, स्विस ओपन ग्रांप्री गोल्ड खिताब जीते और सैयद मोदी ग्रांप्री गोल्ड के फाइनल में पहुंचकर सबको चौंका दिया था. इन सब प्रदर्शन की बदौलत वह दुनिया की तीसरे नम्बर की खिलाड़ी बनीं. रियो ओलम्पिक में श्रीकांत पर दबाव होगा क्योंकि वह कश्यप की गैरमौजूदगी में एकल में वह भारत का झंडा बुलंद करेंगी. ऐसा नहीं है कि केवल महिला खिलाड़ी की तूती बोलती है, पुरुष खिलाड़ियों में श्रीकांत भी उम्मीदों का बोझ उठा रहे हैं.

युगल की बात की जाए तो ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा भी ओलम्पिक में करिश्मा कर सकती हैं. हालांकि हाल में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. कनाडा ओपन जीतने वाली यह जोड़ी ओलम्पिक को ध्यान में रखकर दोबारा एक साथ खेल रही है. अश्विनी और ज्वाला लन्दन ओलिम्पिक से पहले 2012 में अलग हो गई थीं. लन्दन ओलिम्पिक के बाद फिर से जोड़ी बनाने के बाद यह उनका पहला खिताब है. यह जोड़ी पिछले कुछ समय से अलग-अलग अभ्यास करती रही है. पर रियो ओलम्पिक के करीब आ जाने पर दोनों ने एक साथ अभ्यास शुरू किया. अश्विनी बंगलुरु में राष्ट्रीय शिविर में यूसुफ और टॉम जॉन की निगरानी में अभ्यास करती रही हैं जबकि ज्वाला गुट्टा मोहम्मद आरिफ की देखरेख में पसीना बहाती हैं.

दुनिया की 20वें नम्बर पुरुष जोड़ी मनु अत्री और बी सुमंत रेड्डी को अभी काफी मेहनत करनी होगी. दोनों खिलाड़ी अनुभव में कच्चे हैं. ऐसे में उनसे उम्मीद लगाना थोड़ी जल्दीबाजी होगी. कुल मिलाकर रियो ओलम्पिक में अन्य खेलों की तरह इस बार बैडमिंटन में बेहतर सम्भावना दिख रही है. हाल में बैडमिंटन जगत में भारतीय खिलाड़ियों की धमक ज्यादा देखने को मिली है. देश में अब भी खेल प्रेमी भारतीय खिलाड़ियों से पदक की आस लगाए बैठे हैं. रियो ओलम्पिक में लंदन ओलम्पिक से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है. देखना है कि भारत रियो में कितना सफल हो पाता है. ■

फिर लौट रही हॉकी पटरी पर

एक वक्त था जब भारतीय हॉकी टीम की तूती पूरे विश्व में बोलती थी. दुनिया की हर टीम भारतीय हॉकी के आगे सिर झुकाने को मजबूर हो जाती थी. लेकिन बाद के दौर में भारतीय हॉकी का रुतबा नीचे गिर गया. उसका सुनहरा अतीत कहीं अंधकार में खो गया. कभी फेडरेशन की उठापटक तो कभी कोच का रोना भारतीय हॉकी पर भारी पड़ रहा था. लेकिन मौजूदा दौर में भारतीय हॉकी सम्भलती हुई दिख रही है. हाल में भारतीय हॉकी ने कुछ नाम कमाया है और रियो के खेल के लिए कुछ उम्मीदें भी बंधी हैं. इसका ताजा उदाहरण है चैम्पियन्स ट्रॉफी हॉकी में भारत का उम्दा प्रदर्शन. भारतीय हॉकी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार हॉकी खेली लेकिन विश्व चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विवादों भरे खिताबी मुकाबले में पेनाल्टी शूटआउट में 1-3 से पराजित होने के बाद उसे रजत पदक से सन्तोष करना पड़ा. यह प्रदर्शन ऐतिहासिक है क्योंकि भारत ने इससे पहले केवल 1982 में कांस्य पदक जीता था. इस तरह से छह टीमों की इस रोचक जंग में ऑस्ट्रेलिया अव्वल रहा, जबकि भारतीय टीम को दूसरा स्थान मिला और जर्मनी को तीसरे स्थान से सन्तोष करना पड़ा. इस बार की चैम्पियन्स ट्रॉफी लन्दन शहर में हो रही थी. यह वही शहर था जहां भारतीय हॉकी गर्त में चली गई थी. दरअसल लन्दन ओलम्पिक में भारतीय हॉकी ने बेहद शर्मनाक प्रदर्शन किया था और अन्तिम पायदान पर रही थी. लेकिन अब भारतीय टीम में आक्रामकता है, जीत की भूख है और जज्बा भी कूट-कूट कर भरा हुआ है.

इतिहास के पन्नों को पलटें तो इतना तो साफ हो गया था कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचन्द के दौर की हॉकी अब शीर्ष पर नहीं है. टीम में भी आए दिन बदलाव हुआ करते हैं. एक ओर यूरोपीय खिलाड़ी विश्व हॉकी पटल पर छाए थे, वहीं भारतीय हॉकी खिलाड़ी अपनी खराब फिटनेस के चलते लगातार गुमनामी की दुनिया में जी रहे थे. आलम तो यह था हॉकी के राष्ट्रीय खेल होने पर भी सवाल उठने लगे थे. 70 और 80 के दशक में भारतीय हॉकी का डंका बजता था, लेकिन 90 के दशक के बाद से भारतीय हॉकी लगातार पिछड़ रही थी. हार के कारणों को जानने से पहले हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हॉकी को कभी देश में प्रोत्साहन नहीं मिला, जितना क्रिकेट जैसे खेल को मिला. सुविधा के मामले में भी भारतीय हॉकी फिसड्डी रही है. कोचिंग का स्तर भी निम्नस्तर का था. खराब प्रदर्शन के बाद आए दिन कोच पर गाज गिरती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में भारतीय हॉकी ने विदेशी कोच का सहारा लिया. नतीजतन विदेशी कोच भारतीय खिलाड़ियों को मांजने में लग गए. कोच को लेकर हॉकी संघ के पदाधिकारी कई बार आमने-सामने आ चुके हैं. यह वह दौर था जब कोच के रूप में जोन्स ब्रास ने कमान सम्भाली थी. इसी को आगे माइकल नोब्स ने बढ़ाया. माइकल नोब्स ने भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशने का काम शुरू कर दिया था. इसी दौरान फिर भारतीय कोचिंग स्टाफ में काफी बदलाव किया गया. मौजूदा समय में ओल्टमंस ने भारतीय हॉकी को फिर से पटरी पर लाने का काम किया. कोच के रूप में वह भारतीय हॉकी टीम को रियो ओलम्पिक के लिए तैयार कर रहे हैं.

बात अगर चैम्पियन्स ट्रॉफी की हो तो भारत ने ब्रिटेन को 2-1 से धूल चटाई. इससे पहले जर्मनी के खिलाफ भी जोरदार प्रदर्शन करते हुए 3-3 से बराबरी का खेल खेला. हालांकि इस मुकाबले में भारतीय टीम एक समय 3-1 से आगे चल रही थी. इसके बाद दक्षिण कोरिया को 2-1 से पीटा. लीग

मैचों में कंगारुओं से भारतीय टीम हारी लेकिन फाइनल में भारत ने कंगारुओं के नाक में दम कर दिया. फाइनल से पहले लोग कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत आसानी से घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. कंगारुओं को खिताब के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी. आलम तो यह रहा कि निर्धारित समय में खेल 0-0 से बराबर रहा. भारतीय टीम ने दूसरे हाफ में कंगारुओं के पसीने छुड़ा दिए. तीसरे और चौथे क्वार्टर में भी यही हाल रहा. ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी गोल के लिए तरस रहे थे. मैच का फैसला पेनाल्टी शूटआउट से हुआ. बेहद रोचक मुकाबले में तब एक विवाद सामने आया जब ऑस्ट्रेलिया के बीले को शॉट मारने का दोबारा मौका दिया गया. दरअसल भारतीय गोलकीपर श्रीजेश ने ऑस्ट्रेलिया के दूसरे प्रयास को रोक लिया था और गेंद उसके पैरों के बीच फंसी, इसके बाद कंगारुओं ने रेफरल मांगा. ऑस्ट्रेलिया ने इसका फायदा उठाते हुए मैच पर पकड़ मजबूत कर ली. इसके बाद विश्व की शीर्ष टीम ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से जीत कर स्वर्ण पर कब्जा कर लिया. कुल मिलाकर भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा खेली. ओलम्पिक से पहले इस रंजत से अब और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद बढ़ गई है. टीम के खिलाड़ियों को काफी जगह सुधार करने की जरूरत है, खासकर फिटनेस पर कप्तान सरदारा और बीरेंद्र लकड़ा को अभी मेहनत करनी होगी. डिफेन्स और मिड फील्ड को मजबूत भी करना होगा. ओलम्पिक में बेहद कम दिन रह गए हैं. इसे ध्यान में रखकर भारतीय हॉकी हर टूर्नामेंट में पसीना बहा रही है. चैम्पियन्स ट्रॉफी में उसके धारदार प्रदर्शन से इतना तो साफ हो गया है कि ओलम्पिक में इस बार कुछ अलग परिणाम देखने को मिल सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

ड्रग्स की तस्कर-सुंदरी ममता कुलकर्णी

जो हीरोइन 90 के दशक की सुपरस्टार थी. वो हीरोइन 14 साल से गुमनामी की जिंदगी जी रही है. वजह है एक गैंगस्टर, एक ड्रग डीलर से उसकी बेपनाह मोहब्बत. ममता कुलकर्णी को आज दुनिया ड्रग डीलर विकी गोस्वामी के पत्नी के तौर पर जानती है. ड्रग्स रैकेट में नाम आने से पहले ममता कुलकर्णी करीब 12 साल तक गुमनाम रही. ममता कुलकर्णी 90 के दशक में बॉलीवुड में बड़ा नाम थी फिर अचानक 2002 में गायब हो गई. अंग प्रदर्शन के लिए चर्चित रह चुकी ममता पहले भी अंडरवर्ल्ड से रिश्तों को लेकर चर्चा में रही है. ममता कुलकर्णी का कई बड़े राजनेताओं के साथ भी नाम जुड़ा.

धर्मेन्द्र सिंह

पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी और उसके पति विकी गोस्वामी को पुलिस ने ड्रग्स तस्करी मामले में केन्या से गिरफ्तार किया है. कुलकर्णी 90 के दशक में सेक्स सिंबल के तौर पर मशहूर थी. लेकिन पिछले एक दशक से वह लाइमलाइट से गायब थी. खबर है कि ममता ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म अपना लिया है. ममता कुलकर्णी कुछ समय दुबई में रहने के बाद नैरोबी में रह रही थी. पुलिस ने केन्या के मोम्बासा में ममता और उसके पति से ड्रग तस्करी के मामले में गहन पूछताछ की. उसके बाद पुलिस ने ममता और उसके पति विकी को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी यूनाइटेड स्टेट ड्रग इनफोर्समेंट एजेंसी(डीईए) और मोम्बासा पुलिस विभाग ने की. इस मामले में गिरफ्तार सबसे बड़ा नाम बकताश अकाशा का है, जो केन्या का सबसे बदनाम ड्रग माफिया है. इसके अलावा मारे जा चुके ड्रग तस्कर इब्राहिम अकाशा का बेटा भी गिरफ्तार किया गया है. कोर्ट ने ममता कुलकर्णी के पति विकी को बकताश अकाशा का अहम सहयोगी मान रही है.

इधर मुंबई की ठाणे पुलिस ने ममता बनर्जी को पति विकी गोस्वामी के साथ 2000 करोड़ रुपये की ड्रग्स तक्सरी में आरोपी बनाया है. ममता के खिलाफ कुछ सबूत भी पुलिस के पास हैं. पुलिस का कहना है कि इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की जाएगी. विकी अभी केन्या पुलिस की कस्टडी में है. ममता और उसके पति विकी गोस्वामी सहित 10 लोगों के खिलाफ अप्रैल में ड्रग्स स्मगलिंग का केस दर्ज किया गया था. पुलिस के मुताबिक इस रैकेट का नेटवर्क दूसरे देशों में भी फैला हुआ है. खास बात यह है कि अप्रैल में जब विकी को केन्या में गिरफ्तार किया गया था, उसी दौरान मुंबई पुलिस ने सोलापुर में एक ड्रग फैक्टरी का पर्दाफाश किया था. इस फैक्ट्री से 20 टन एफेड्रीन ड्रग बरामद की थी. इस ड्रग की खरीद और बिक्री भारत में बैन है. ठाणे पुलिस के मुताबिक, भारत, पोलैंड और दूसरे यूरोपियन देशों की गैंग कन्साइनमेंट को मुंबई से गुजरात के रास्ते ईस्टर्न यूरोप भेजने की प्लानिंग कर रही थी.

विकी गोस्वामी के एक प्रमुख साथी जयमुखी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यूपी एसटीएफ और मुंबई पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे गोरखपुर रेलवे स्टेशन से धर दबोचा. पुलिस ने उसके पास से एक पासपोर्ट भी बरामद किया है, जो मुंबई से जारी हुआ है. वह गोरखपुर से नेपाल होते हुए विदेश में बैठे अपने आका के पास भागने की फिराक में था, लेकिन उसके पहले ही एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया. बताते चलें कि मुंबई की ठाणे पुलिस ने ड्रग्स रैकेट में ओकोयो चिनास नाम के एक नाइजीरियाई नागरिक की गिरफ्तारी के बाद मिले सबूतों के आधार पर सोलापुर की एवोन लाइफ साइंसेज कंपनी पर छापा मारा था. छापेमारी के दौरान यहां से करीब साढ़े 18 टन इफेड्रिन जब्त किया गया था. पुलिस को पता चला कि इसमें अंडरवर्ल्ड, नेता और सरकारी अधिकारी तक शामिल हैं. रैकेट के मुख्य सूत्रधारों के रूप में जयमुखी, पुनीत श्रृंगी और किशोर राठौड़ के नाम सामने आए थे. इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था. ममता अब इस ड्रग रैकेट में बुरी तरह फंस चुकी हैं. विकी गोस्वामी खुद को ममता का पति बताता है, लेकिन ममता कुलकर्णी ने एक टीवी चैनल को दिए गए अपने साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विकी से शादी नहीं की है. ममता ने घातक, करण अर्जुन और बाजी जैसी फिल्मों में काम किया है. अब ममता ने अध्यात्म पर एक किताब लिखी है, जिसका नाम है–ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी.

जो हीरोइन 90 के दशक की सुपरस्टार थी. वो हीरोइन 14 साल से गुमनामी की जिंदगी जी रही है. वजह है एक गैंगस्टर, एक ड्रग डीलर से उसकी बेपनाह मोहब्बत. ममता कुलकर्णी को आज दुनिया ड्रग डीलर विकी गोस्वामी के पत्नी के तौर पर जानती है. ड्रग्स रैकेट में नाम आने से पहले ममता कुलकर्णी करीब 12 साल तक गुमनाम रही. ममता कुलकर्णी 90 के दशक में बॉलीवुड में बड़ा नाम थी फिर अचानक 2002 में गायब हो गई. अंग प्रदर्शन के लिए चर्चित रह चुकी ममता पहले भी अंडरवर्ल्ड से रिश्तों को लेकर चर्चा में रही है. ममता कुलकर्णी का कई बड़े राजनेताओं के साथ भी नाम जुड़ा. ठाणे पुलिस के मुताबिक यह अन्तरराष्ट्रीय रैकेट है और ममता का पति विकी

गोस्वामी उसका मुख्य सरगना है. इसी वजह से ममता कुलकर्णी के रोल की भी जांच की गई थी. जांच में पता चला कि ममता को इस रैकेट के फेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. इंटरपोल अलर्ट के बाद विकी केन्या से बाहर नहीं निकल सकता था. इसलिए वह ममता को दुबई, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और यूएस में क्लाइंट से मिलने के लिए कहता था. ममता महाराष्ट्र में ड्रग नेटवर्क के साथ बिजनेस डील भी करती थी. इसके अलावा विकी पैसों के लेन–देन के लिए ममता के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल भी करता था. ये कपल हवाला के जरिए ड्रग डील का पैसा दूसरे देशों में भेजता था. ये सभी बातें ठाणे पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया. कोर्ट के सामने गिरफ्तार दो आरोपियों ने बयान दिया है कि केन्या में हुई मीटिंग में ममता भी थी और यह मीटिंग काफी देर तक चली थी. ड्रग्स को कैसे हिंदुस्तान से लाया जाए, बाजारों में कैसे बेचा जाए जैसे कई बातों पर चर्चा हुई. कंपनी के दो करोड़ शेयर में से 11 लाख शेयर ममता के नाम पर ट्रांसफर करने पर सहमति बनी थी, इससे वो कंपनी की डायरेक्टर बन जाती. करीब 23 टन एफेड्रिन यहां से अफ्रीका ट्रांसफर होने वाला था. सिंह ने कहा कि हम ममता कुलकर्णी का नाम वेरिफाई करना चाहते थे और वो अब कंफर्म हो गया है.

पुलिस का कहना है कि 8 अप्रैल को भी दुबई में बुर्ज खलीफा में एक जरूरी मीटिंग हुई थी. इनका मोरक्को का लिंक भी सामने आता है. विकी कोलंबियन ड्रग लार्ड डॉ. अब्दुल्ला के संपर्क में था. उसका अफ्रीका में खास कांटेक्ट है. करीब 100 टन की एफीड्रिन का कंसाइनमेंट करीब एक महीने पहले विकी गोस्वामी के किसी जानने वाले के घर पर मुंबई में रखवाया गया था. उसके बाद उसे हवाला के रास्ते ले जाया गया था. पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हमारे पास दो गवाहों के 164 बयान दर्ज हैं. उन्हीं के आधार पर हमने ममता कुलकर्णी को भी आरोपी बनाया है. उन्होंने भी गिरोह की केन्या में 8 जनवरी को हुई मीटिंग के लिए अहम भूमिका निभाई थी. मीटिंग में अन्तरराष्ट्रीय ड्रग्स कारोबारी अबदुल्ला भी मौजूद था. मीटिंग में उन लोगों ने बड़े पैमाने पर भारत में ड्रग्स भेजे जाने की प्लानिंग की थी.

ममता कुलकर्णी अमेरिकन डीईए रडार पर लंबे समय से थी. परमवीर सिंह का कहना है कि बॉलीवुड से भी कुछ नाम सामने आए हैं. उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है.

विकी को 1997 में दुबई में ड्रग की स्मगलिंग में अरेस्ट किया गया था. यहां उसे 15 साल की सजा हुई थी. इसके बाद वह ममता के साथ केन्या की राजधानी नैरोबी रहने चला गया था. केन्या में भी इस पर कई केस चल रहे हैं. विकी की यूएस और ठाणे पुलिस को भी ड्रग स्मगलिंग में तलाश है.

ममता और विकी ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए आरोपों का खंडन किया. उन्होंने कहा कि उन्हें साबित करने दीजिए. मेरी जानकारी में मैं कभी इस अब्दुल्ला नाम के शख्स से नहीं मिली. अब पुलिस के पास साबित करने के लिए कुछ नहीं है. पहले उन्हें कोर्ट में साबित करने दीजिए. दूसरी ओर, विकी गोस्वामी ने भी यही कहा कि वह अपनी जिंदगी में कभी भी अब्दुल्ला से नहीं मिला है.

अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट में ममता कुलकर्णी का नाम उसके पति विकी गोस्वामी की वजह से आया है. वही विकी गोस्वामी है जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के ड्रग सिंडिकेट का काम संभालता है. दरअसल यह मामला पिछले 12 अप्रैल को सामने आया था, जब ठाणे पुलिस ने एक नाईजीरियन को 500 ग्राम एफीड्रीन ड्रग के साथ गिरफ्तार किया था. पुलिस ने जब उससे कड़ी पूछताछ की तो ड्रग सिंडिकेट का पूरा ताना–बाना सामने आने लगा. शोलापुर की एक फैक्ट्री से पुलिस को साढ़े 22 टन एफीड्रीन ड्रग मिली थी. पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया. इन चारों लोगों ने तीन और लोगों के नाम बताए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में इन लोगों ने खुलासा किया कि जनवरी 2016 में तीन लोग हिंदुस्तान से केन्या गए थे. वहां इन लोगों ने विकी गोस्वामी के साथ मीटिंग की थी. इस मीटिंग में फैसला हुआ था कि भारत से 30 टन एफीड्रीन ड्रग केन्या भेजा जाएगा. इस सिंडीकेट में किशोर राठौड़ का नाम भी सामने आया है जो पूर्व कांग्रेस विधायक का पुत्र है.■

feedback@chauthiduniya.com

ड्रग्स लेते पकड़े जा चुके ये सितारे

संजय दत्त

संजय दत्त बॉलीवुड के ऐसे आभिनेताओं में शुमार हैं जो कई आपराधिक मामलों के फंस चुके हैं. संजय की मां नरगिस की मृत्यु के बाद वह पूरी तरह से टूट गए थे और उसी वक्त वह ड्रग्स के आदि हो गए थे. 1982 में उन्हें ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार भी किया गया था. संजय को इस लत से निजात दिलाने के लिए रि-हैब सेंटर भी भेज दिया गया था.

फरदीन खान

फरदीन को 2001 में एक डीलर से कोकीन खरीदते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था. ड्रग्स की लत से छुटकारा पाने के लिए उन्हें भी री-हैब सेंटर भेज दिया गया था.

रणबीर कपूर

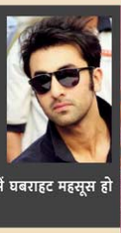

रणबीर के चेन स्मोकर होने की बात तो लगभग सभी को पता है, लेकिन उन्होंने वर्ष 2011 में दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि, जब वह स्कूल में थे तब उन्होंने ड्रग्स भी लिए थे और वह जल्द ही इसके आदि भी हो गए थे. उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब वह रॉकस्टार की शूटिंग कर रहे थे उस दौरान उन्हें एक सीन को शूट करने में घबराहट महसूस हो रही थी जिसकी वजह से उन्होंने ड्रग्स लिए थे.

मनीषा कोइराला

बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा मनीषा कोइराला का बॉलीवुड करियर उनके शराब, सिगरेट और ड्रग्स की लत के कारण पूरी तरह खराब हो चुका था. साथ ही उनकी सेहत भी इसकी वजह से बिगड़ने लगी थी, लेकिन जब उन्हें अपने कैंसर के बारे में पता चला तो उन्होंने इन सभी गलत आदतों को छोड़ दिया.

विजय राज

मानसून वेडिंग और दिल्ली बेली जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का कमाल दिखाने वाले विजय राज को 2005 में दुबई के हवाई अड्डे पर ड्रग्स रखने के आरोप में वहां कि पुलिस ने हिरासत में लिया था.

कड़वी सच्चाई दिखाती है उड़ता पंजाब

उड़ता पंजाब राजनेताओं और ड्रग के कारोबार के बीच के लिंक को बेहद सच्चाई के साथ दिखाती है. फिल्म की शुरुआत में ही साफ हो जाता है कि फिल्म की कहानी और किरदार सच्चाई के कितना नजदीक हैं, कहीं तो हमारा सिनेमा, समाज की कड़वी सच्चाई को आखिर दिखा रहा है. फिल्म पंजाब ही नहीं, देश में किस तरह से ड्रग का रैकेट फैला है उसे दिखाती है. उड़ता पंजाब ने दिखाया है कि नशे की लत कितनी बुरी होती है. एक बार अगर किसी को इसकी लत लग गई तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है. इस फिल्म में शाहिद कपूर को इस रूप में दिखाया गया है जो हमेशा नशे में रहता है. इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की ड्रग डीलर के जाल में फंस जाती है. नशे से जूझ रहे नौजवानों की असल जिंदगी की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं. 13 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग नशे से छुटकारा पाने की जंग में सब शामिल हैं.■